

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210] No. 210] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 2019/आषाढ़ 27, 1941

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 2019/ASHADHA 27, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2019

अंतिम जांच परिणाम

विषयः चीन जन. गण., थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से पीवीसी सस्पेंसन ग्रेड रेसिन के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच।

फा. सं. 7/34/2018-डीजीटीआर.— समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हए;

क. मामले की पृष्ठभूमिः

1. जबिक प्राधिकारी द्वारा ताइवान, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, थाइलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और कोरिया गणराज्य से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में मूल जांच और उसके बाद अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना निश्चयात्मक शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हुए प्राधिकारी द्वारा 26 दिसंबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 14/8/2006-डीजीएडी द्वारा जारी की गई थी। अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर अधिसूचना संख्या 11/2008 के माध्यम से 23 जनवरी, 2008 से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। अंतिम जांच परिणाम जारी करने के बाद, प्राधिकारी ने शुल्क तालिका में संशोधन करते हुए दिनांक 14 फरवरी, 2018 की अधिचना संख्या 14/8/2006-डीजीएडी द्वारा एक शुद्धिपत्र जारी किया और वह सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा 24 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 38/2008 द्वारा लगाया गया था। इस आदेश से दखी होकर हितबद्ध पक्षकार सेसटेट में गए और यह मामला प्राधिकारी को वापस भेजा गया था। जांच के बाद

3712 GI/2019 (1)

- प्राधिकारी ने उनके द्वारा 26 दिसंबर, 2007 को पारित निर्णय की पुनः पुष्टि की। एक समाप्त समीक्षा जांच की गई थी और प्राधिकारी ने कोरिया को छोड़कर संबद्ध देशों पर शुल्क लगाया जाना जारी रखने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय ने 13 जून, 2014 की अधिसूचना संख्या 27/2014 द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया।
- 2. जबिक, एक जांच 05 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 14/1012/2012-डीजीएडी द्वारा यूरोपीय संघ और मैक्सिको से संबद्ध सामानों के आयातों के विरुद्ध शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने 04 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना संख्या 14/1012/2012-डीजीएडी के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की। विक्त मंत्रालय ने 13 जून, 2014 की अधिसूचना संख्या 26/2014 के माध्यम से यूरोपीय संघ और मैक्सिको से संबद्ध सामानों के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया।
- 3. जबिक, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड, जिन्हें अब केमप्लास्ट कुड्डालोर विनाइल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, ने मौजूदा पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन जारी रहने अथवा बार-बार होने तथा परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना का आरोप लगाते हुए अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार यूरोपीय संघ, मैक्सिको, ताइवान, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने की मांग करते हुए एक संयुक्त आवेदन पत्र दायर किया।
- 4. प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करते हुए विचार किया कि यूरोपीय संघ, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ताइवान, जापान और मलेशिया से आयातों के संबंध में समीक्षा जांच करने के लिए अपर्याप्त औचित्य है। अतः प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर 29 अक्तूबर, 2018 की सार्वजनिक सूचना संख्या 7/34/2018-डीजीएडी के माध्यम से यह जांच करने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की कि चीन जन. गण., थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर उपर्युक्त शुल्कों की समाप्ति से पाटन के जारी रहने अथवा बार-बार होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 11 जून, 2019 की अधिसूचना सं. 23/2019-सीमाशुल्क (ए डी डी) के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क का समय विस्तार किया है।
- 5. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित उपर्युक्त सामानों के आयातों से संबंधित मूल जांचों के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

- 6. प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त जांच की शुरूआत अधिसूचित करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी करने के बाद इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
 - i. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम-5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच आरम्भ करने की कार्रवाई करने के पूर्व निर्णायक समीक्षा आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावास / प्रतिनिधियों को सूचित किया।
 - ii. प्राधिकारी ने संबद्ध निर्णायक समीक्षा जांच आरम्भ करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 29 अक्तूबर, 2018 को एक आम सूचना जारी की ।
 - iii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, अन्य भारतीय उत्पादकों और घरेलू उद्योग को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार जांच की शुरूआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे जांच की शुरूआत के 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।
 - iv. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को तथा ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आवेदन के अगोपनीय रुपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।
 - v. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दें। ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए

पत्र और प्रश्नावली की प्रति संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों सहित दूतावासों को भी भेजी गई थी।

- vi. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मंगाने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली तथा बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली (केवल चीन के लिए) भेजीः
 - एफपीसी यूएसए
 - शिनटेक
 - वेस्टलेक विनाइल्स इंक.
 - वेस्टलेक विनाइल्स कंपनी एलपी
 - एलजी डगु
 - विनिथाई पब्लिक लि.
 - तियानजिन डगु केमिकल कं. लि.
 - जॉर्जिया गल्फ
 - ऑक्सी विनाइल्स
 - थाई प्लास्टिक एंड केमिकल्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड
 - एपेक्स पैट्रोकेमिकल लि.
 - सिनोपेक
 - शंघाई क्लोर-अलकाली केमिकल कं. लि.
 - चाइना होहुआ केमिकल (ग्रुप) कारपोरेशन (सीएचसी)
 - यिबिन तियानयुआन ग्रुप कं. लि.
 - सिनोपेक किलू कंपनी
 - सुझोऊ होसू प्लास्टिक्स कं. लि.
 - यिचांग यिहुआ पैसिफिक कोजेन कं. लि.
 - निंजिया यिंगलीचे केमिकल्स कं. लि.
 - शानडोंग होहुआ क्लोर-अलकाली रोसिन कं. लि.
 - किंगदाओ हैजिंग केमिकल (ग्रुप) कं. लि.
 - इनर मंगोलिया सनलियान केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड
 - जिनजियांग शीहेजी झोंगफा केमिकल कं. लि.
 - हुबेई यिहुआ ग्रुप कं. लि.
- vii. संबद्ध जांच की शुरूआत के उत्तर में संबद्ध देशों से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर कर उत्तर दिया है:
 - थाई प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स पीएलसी
 - एससीजी प्लास्टिक्स कं. लि.
 - एससीजी परफॉर्मेंस केमिकल्स कं. लि.

- शिनटेक इंक
- पॉलीमर मार्केटिंग डीएमसीसी
- इटोचू प्लास्टिक्स पीटीई. लि.
- इटोचू थाईलैंड लि.
- ऑक्सी विनाइल्स एक्सपोर्ट सेल्स, एलएलसी
- आईसीसी केमिकल कारपोरेशन
- ऑक्साइड केमिकल्स इंक.
- ऑक्सी विनाइल्स, एलपी
- त्रिकोण ड्राई केमिकल्स एलएलसी, त्रिकोण एनर्जी युके लि. और त्रिकोण ओवरसीज इंक
- वेस्टलेक विनाइल्स इंक.
- वेस्टलेक विनाइल्स कंपनी एलपी
- एक्सियाल एलएलसी
- चिपिंग जिंफा पीवीसी कं. लि.
- शानडोंग जिंफा इम्पॉर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि.
- सीएनएसजी जिलनताई साल्ट केमिकल (ग्रुप) कं. लि.
- सीएनएसजी जिलनताई साल्ट क्लोरी-अलकाली केमिकल कं. लि.
- यिबि तियानयुआन ग्रुप कं. लि.
- यिबिन हैफेंग हेरूई कं. लि.
- विनथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड
- तियानेंग एलजी बोहाई केमिकल कं. लि.
- तियानेंग केमिकल कं लि.
- जिनजियांग तियानये (ग्रुप) कं. लि.
- तियानजिन डगु केमिकल कं. लि.
- बोहाई केमिकल (एचके) लिमिटेड
- जिनजियांग शेंक्जियोंग क्लोर-अलकाली कं. लि.
- जिनजियांग झोंगताई केमिकल कं. लि.

viii. इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित पक्षकारों द्वारा अनुरोध भी किए गए थे।

- थाई प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स पीएलसी
- मैसर्स एलकेएस द्वारा दायर चाइना क्लोर अलकाली इंडस्ट्री एसोसिएशन
- इटोचू (थाइलैंड) लि.
- ix. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजीः

- शालीमार रेक्सिन इंडिया लि.
- फिनोलेक्स ग्रुप
- द सुप्रीम इंडस्ट्रीज
- कृष्णा विनाइल्स ग्रुप
- प्रिंस ग्रुप
- जैन इरिगेशन सिस्टम्स
- कल्पना इंडस्ट्रीज
- कॉसमॉस कारपोरेशन
- पॉलीट्रशन्स प्राइवेट लि.
- पॉलीकैब केबिल्स प्रा. लि.
- चंदुबाई ग्रुप
- जे पी ग्रुप
- रॉयल कुशन विनाइल प्रोडक्ट
- किसान ग्रुप टेक्स सेंटर
- गोल्डन ग्रुप
- प्रीमियर पॉलीफिल्म लि.
- वी. के. गांधी ग्रुप
- ओमेगा उद्योग
- फाइन फ्लो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज
- कृति इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि.
- अमीषा विनाइल्स प्रा. लि.
- नैवेले क्रेडिट्स प्रा. लि.
- डी. आर. पॉलीमर्स लि.
- सिनटेक्स इंडस्ट्रीज लि.
- संखला इंडस्ट्रीज
- शांतिलाल महेंद्र कुमार
- सैम पॉलीमर्स
- प्रकाश इंडस्ट्रीज
- आर. एस. ओवरसीज प्रा. लि.

- सिगनेट ओवरसीज लि.
- वीके पॉलीकोट्स लि.
- एवन प्लास्टिक ग्रुप
- केआईजे ग्रुप
- कैप्रिहेंस इंडिया लि.
- पार पैट्रोकेम लु.
- सुधारकर ग्रुप
- सुरेंद्र कॉमर्शियल
- एमएम प्लास्टिक्स
- के एस प्लास्टिक्स
- डीलक्स कैरन इमोर्ट प्रा. लि.
- आसु केमपोप्लास्ट
- दुतरन प्लास्टिक्स
- प्रिंटक्राफ्ट्स
- आदित्य इंडस्ट्रीज
- जेवेल पॉलीमर्स
- फैंसी पॉलीमर्स प्रा. लि.
- वर्षा कारपोरेशन लि.
- मैक्स इम्पैक्स
- ऑरीप्लास्ट
- इनकम केबिल्स प्रा. लि.
- डायमंड पाइप्स एंड ट्यूब्स
- चैतन्य इम्पोजेनेक्स
- तिरूपति ग्रुप
- अपोलो पाइप्स
- हैवेल्स इंडिया
- ओसवाल केबिल्स प्रोड्क्ट्स लि.
- मेघा इंडस्ट्री
- एसोसिएटेड कैपसूल्स लि.
- x. संबद्ध सामानों के निम्नलिखित आयातक ने आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर कर उत्तर दिया हैः
 - ऑक्साइड केमिकल्स एंड पॉलीमर्स इंडिया प्रा. लि.
- xi. निम्नलिखित आयातकों/एसोसिएशनों द्वारा अनुरोध भी दायर किए गए थेः

- प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (प्लेक्सकोंसिल)
- ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईपीएमए)
- xii. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराया।
- xiii. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वे क्षिति की अविध तथा उससे पूर्व की अविध और जांच की अविध एवं जांच की अविध के बाद की अविध के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देन वार ब्यौरे उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा का परिकलन करने और लेन-देनों की उचित जांच करने के बाद अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्लास किया है। प्राधिकारी ने यथा व्यवहार्य सीमा तक दायर किए गए उत्तरों को वैध करने के लिए निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातों की मात्रा का सह-संबंध बनाने के लिए जांच की अविध के लिए डीजी सिस्टम से भी आंकड़े प्राप्त किए।
- xiv. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादन की इष्टतम लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xv. प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार, मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान करने के लिए 12 फरवरी, 2019 को एक मौखिक सुनवाई की जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया था। उन सभी पक्षकारों, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें। पक्षकारों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे विरोधी पक्षकारों द्वारा किए गए लिखित अनुरोधों को एकत्रित करें और उसके बाद अपने प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें।
- xvi. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। केवल आवश्यक संशोधन के साथ सत्यापित सूचना, जहां भी लागू थी, पर विश्वास किया गया है।
- xvii. वर्तमान समीक्षा जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2017 मार्च, 2018 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में संभावना विश्लेषण के लिए 2014-15, 2015-16, 2016-17 और जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के बाद की अवधि (06 माह) शामिल हैं।
- xviii. इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, जहां भी संगत पाए गए हैं, इस प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा हल कर दिए गए हैं।
- xix. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर प्रस्तुत करें।
- xx. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने मौजूदा जांच की कार्रवाई के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना कर दिया है अथवा ऐसी सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है अथवा जांच में अत्यधिक अड़चनें डाली हैं, वहां प्राधिकारी ने उन पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां रिकार्ड की हैं।
- xxi. इस दस्तावेज में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- xxii. जांच की अवधि के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 65.33 रुपए = 1 अमेरिकी डॉलर तथा जांच की अवधि के बाद (01.04.2018 से 30.09.2018) के लिए 69.15 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का क्षेत्र

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

- 7. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थेः
 - i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद पीवीसी सस्पेंसन रेसिन है जो विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंसन ग्रेड) का होमो पॉलीमर है जो कि उसी तरह का है जिसकी जांच की गई थी और मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा निष्कर्ष निकाला गया था। चूंकि, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पूर्व जांचों के समय से कोई खास विकासात्मक गतिविधियां नहीं हैं, अतः विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र मूल जांच के क्षेत्र की तरह ही रखा जाना अपेक्षित है।
 - ii. याचिकाकर्ताओं ने कुछ उत्पादों की पूर्व जांचों में इस कारण अलग रखने के लिए सहमित दी थी कि ये सस्पेंसन पीवीसी की तुलना में पूर्णतः भिन्न उत्पाद है और घरेलू उद्योग पूर्व में भी इन उत्पादों का उत्पादन नहीं कर रहा था। यहां तक कि जब सीपीवीसी जैसे ये कुछ उत्पाद अब भारत में बनाए जाते हैं, तो किसी भी दशा में वे पूर्णतः भिन्न उत्पाद हैं जो कि विभिन्न संयंत्रों में तथा काफी निवेश करने के बाद उत्पादित किए जाते हैं। इन उत्पादों में विचाराधीन उत्पाद की तुलना में पूर्णतः भिन्न उत्पाद हैं। विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र पीवीसी सस्पेंसन रेसिन तक सीमित है।
 - iii. संबद्ध सामान उप शीर्ष 39041020 के अंतर्गत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के तहत वर्गीकृत हैं, परंतु अन्य उप शीर्षों 39041090, 39042120, 39042190, 39042210, 39042290, 39049000 के तहत भी आयातित किए गए हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और जांच के क्षेत्र पर किसी तरह बाध्यकारी नहीं है।
 - iv. विविध एचएस कोडों का प्रयोग बहुत ही विस्तृत है और सरकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद के लिए एचएस कोड विनिर्दिष्ट किए जाने के बाद भी जारी है। याचिकाकर्ता यह सुनिश्चित करने में समर्थ हैं कि क्या इन सभी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क विगत में एकत्रित किया गया है अथवा नहीं। अतः याचिकाकर्ता प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे कृपया 3904 वर्गीकरण के तहत आने वाले उत्पाद के लिए पाटनरोधी शुल्क बढ़ाने पर विचार करें।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- 8. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थेः
 - i. सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और बाध्यकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह मुद्दा सीबीआईसी के लिए हल करने हेतु है। घरेलू उद्योग का 3904 वर्गीकरण के तहत सभी आयातों और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध अमान्य है क्योंकि उपर्युक्त प्रशुल्क शीर्ष विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत न आने वाले अन्य उत्पादों पर लगता है।
 - ii. डीजीटीआर ने व्यापार उपचार जांचों के लिए प्रचालन परिपाटियों की अपनी पुस्तिका में (पृष्ठ 38 पर) पहले ही विनिर्दिष्ट किया है कि "नियमावली के नियम 23(1ख) के अनुसार निर्णायक समीक्षा का आवेदन पत्र मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद के परिभाषित क्षेत्र के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। न तो आवेदक और न ही प्राधिकारी अपनी ओर से निर्णायक समीक्षा के दौरान विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र बदल सकते हैं।" इस प्रकार, प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद के वर्गीकरण के विस्तार के अनुसार भी वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में किसी संशोधन से अलग रहना चाहिए।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

9. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंसन ग्रेड) का होमो पॉलीमर ऑफ है जिसमें विभिन्न पॉलीमर श्रृंखलाएं सीमा शुल्क वर्गीकरण संख्या 3904 के तहत आने वाली एक-दूसरे से संबद्ध नहीं होते हैं"। विचाराधीन उत्पाद क्रॉस लिंक्ड पीवीसी, क्लोरीनेटिड पीवीसी (सीपीवीसी), विनाइल क्लोराइड – विनाइल एसीटेट कोपोलाइमर (वीसी – वीएसी), पीवीसी पेस्ट रेसिन और पीवीसी ब्लैंडिंग रेसिन जैसे विशिष्ट पीवीसी सस्पेंसन रेसिन को अलग करता है। विचाराधीन उत्पाद को "पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) रेसिन", "सस्पेंसन ग्रेड" अथवा "पीवीसी सस्पेंसन रेसिन" के रूप में भी उल्लिखित किया गया है।

- 10. संबद्ध सामानों को उनके के-मूल्य के आधार पर विभिन्न ग्रेडों में वर्गीकृत किया जाता है। संबद्ध सामानों का मुख्य अनुप्रयोग उनके के-मूल्य पर निर्भर करता है; जितना अधिक के-मूल्य होगा उतना ही अधिक मॉलक्यूलर भार भी होगा। लो मॉलक्यूलर भार वाले पीवीसी सस्पेंसन मुख्य रूप से रिजिड फिल्म और शीट, ब्लो मॉल्डेड बोतल और अन्य इंजेक्शन मॉल्डिंग वस्तुओं में प्रयोग पाते हैं। अधिक मॉलक्यूलर भार वाला पीवीसी सस्पेंसन मुख्य रूप से एक्सटूजन पाइपों और प्रोफाइल में अनुप्रयोग पाता है। उच्च क्षरण के साथ अधिक पीवीसी सस्पेंसन भी तारों और केबिलों में विशिष्ट अनुप्रयोग पाते हैं और शू लास्ट्स, फ्लेक्सिबल फिल्म्स आदि जैसे अन्य लचीले अनुप्रयोगों में स्थान पाते हैं।
- 11. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के नाते और संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू होने के नाते प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो मूल तथा बाद की समीक्षा जांच में है। इसके अतिरिक्त, िकसी भी हितबद्ध पक्षकार ने समीक्षा के क्षेत्र में संशोधन (स्थगन सहित) का अनुरोध करते हुए कोई उचित अनुरोध नहीं किया है। इस संबंध में, दिनांक 04 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना संख्या 21/29/2011-डीजीएडी द्वारा जारी अंतिम निष्कर्ष वाले निर्णायक समीक्षा जांच परिणाम पर विश्वास किया जाता है जिसमें विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में माना गया थाः
 - "7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंसन ग्रेड) का होमो पॉलीमर ऑफ है जिसमें विभिन्न पॉलीमर श्रृंखलाएं सीमा शुल्क वर्गीकरण संख्या 3904.21 के तहत आने वाली एक-दूसरे से संबद्ध नहीं होते हैं"। विचाराधीन उत्पाद क्रॉस लिंक्ड पीवीसी, क्लोरीनेटिड पीवीसी (सीपीवीसी), विनाइल क्लोराइड विनाइल एसीटेट कोपोलाइमर (वीसी वीएसी), पीवीसी पेस्ट रेसिन और पीवीसी ब्लैंडिंग रेसिन जैसे विशिष्ट पीवीसी सस्पेंसन रेसिन को अलग करता है। विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में माने गए उत्पाद के समान है।
 - 8. विचाराधीन उत्पाद में समर्पित एचएस कोड नहीं है और आयातों को 3904 के तहत आने वाले विभिन्न एचएस कोडों के तहत मंजूर किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह वर्तमान जांच के क्षेत्र पर और प्रस्तावित उपायों पर बाध्यकारी नहीं है।
 - 10. रिकार्ड में साक्ष्य और जांच की शुरूआत की अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को मूल जांच परिणाम में माने गए क्षेत्र के समान ही रखना उपयुक्त मानते हैं।"
- 12. प्राधिकारी चार अंक के स्तर पर आईटीसीएचएस के निर्धारण के संबंध में प्रकटन के उत्तर में किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा भिन्न आईटीसीएचएस उल्लिखित किए जा सकते हैं, तथापि उत्पाद विवरण में आईटीसीएचएस में प्राथमिक है, इन चिंताओं को मद्देनजर रखते हुए विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण चार अंक के स्तर पर उल्लिखित किया गया है, जैसा कि पूर्व के मामले में किया गया था। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण प्रकृति में केवल संकेतात्मक है और बाध्यकारी नहीं है।
- 13. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार प्रावधान हैः
 - "ऐसी वस्तु जो भारत में पाटित किये जाने के लिए जांचाधीन वस्तु से हर तरीके से समनरूप अथवा समान है अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में ऐसी दूसरी वस्तु जो यद्यपि हर प्रकार से समान नहीं है तथापि, उसमें जांचाधीन वस्तुओं से अत्यधिक मिलती-जुलती विशेषताएं हैं।"
- 14. रिकार्ड में सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, वितरण और विपणन एवं सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध सामानों की तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं।
- 15. इस प्रकार, प्राधिकारी मानते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।
- घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

- 16. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - मैसर्स केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड, मैसर्स डीसीडब्ल्यू लिमिटेड और मैसर्स डीसीएम श्रीराम लि. वर्तमान जांच में याचिकाकर्ता हैं जिनका कुल भारतीय उत्पादन में "प्रमुख अनुपात" है।
 - ii. मैसर्स केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड, सनमार समूह के सस्पेंसन पॉली विनाइल क्लोराइड बिजनेस/अंडरटेकिंग को स्थानांतरित कर दिया गया है और वह मैसर्स केमप्लास्ट कुड्डालोर विनाइल्स लिमिटेड में निहित कर दिया गया है। इसका माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एकल बैंच, चेन्नई ("एनसीएलटी") द्वारा उसके दिनांक 29 अप्रैल, 2019 के आदेश से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 और 232 के तहत व्यवस्था की सामासिक योजना/विलगन के तहत अनुमोदन कर दिया गया है।
 - iii. मैसर्स डीसीएम श्रीराम लिमिटेड की मैसर्स श्रीराम एक्सियाल प्राइवेट लिमिटेड (अब वेस्टलेक के रूप में ज्ञात) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जो पीवीसी सम्मिश्रणों के उत्पादन में लगी है। इस कंपनी ने एक्सियाल एलएलसी (वेस्टलेक), संयुक्त राज्य अमेरिका नामक अपनी संबद्ध कंपनी से विचाराधीन उत्पाद की बहुत छोटी सी मात्रा आयात की है। इस संबद्ध कंपनी द्वारा किए गए आयात भारत में उत्पादन, खपत और आयातों की दृष्टि से बहुत कम हैं।
 - iv. यहां तक कि यही विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में लगी संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई संबद्ध कंपनी है और भारत को निर्यात कर रही है तो उसका भारत में घरेलू उत्पादक की अनर्हता नहीं मानी जानी चाहिए। यद्यपि, एक्सियाल एलएलसी ने भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है, तथापि, श्रीराम एक्सियाल प्राइवेट लिमिटेड ने एक्सियाल एलएलसी से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। श्रीराम एक्सियाल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयातों का विवरण यह दर्शाता है कि थाइलैंड से आयातों की बहुत कम (नगण्य) मात्रा है।
 - v. यद्यपि, एक्सियाल एलएलसी (वेस्टलेक) ने भारत को निर्यात किया है, तथापि डीसीएम श्रीराम को अपात्र नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि श्रीराम का एक्सियाल पर कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। डीसएम ने खुद ही संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाने का अनुरोध किया है (जिसका अभिप्राय यह है कि डीसीएम ने ऐसे निर्यातक पर शुल्क की मांग की है)।
 - vi. डीसीएम श्रीराम को छोड़कर याचिकाकर्ता कंपनियों ने प्रमाणित किया कि इनमें से कोई भी भारत में संबद्ध सामानों के किसी आयातक से संबद्ध नहीं है और यह कि उनमें से किसी ने भी भारत में संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है तथा यह कि इनमें से कोई भी संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के किसी भी निर्यातक से संबद्ध नहीं है।
 - vii. भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड नामक संबद्ध सामानों के दो और उत्पादक हैं। यह तथ्य कि याचिकाकर्ता कंपनियों का भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है, इस आधार पर नकारा नहीं जा सकता कि संबद्ध सामानों का एक प्रमुख उत्पादक आरआईएल वर्तमान जांच में भाग नहीं ले रहा है। आरआईएल द्वारा भाग न लिए जाने के लिए याचिकाकर्ताओं को दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
 - viii. भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ता कंपनियों का हिस्सा सामूहिक रूप से 30.14 प्रतिशत है। यद्यपि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का उत्पादन भी काफी है, तथापि उसका अभिप्राय यह नहीं हो जाता कि याचिकाकर्ता कंपनियों का उत्पादन भारतीय उत्पादन में "प्रमुख अनुपात" नहीं बनाता।
 - ix. िकसी भी उद्योग में एक से अधिक प्रमुख अनुपात हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जहां भारत में एक से अधिक अनुपात हैं, प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या प्राधिकारी के समक्ष उद्योग उस समय भी "प्रमुख अनुपात" बनाता है जब प्राधिकारी के समक्ष दूसरा उद्योग भी "प्रमुख अनुपात" बनाए। वर्तमान परिस्थितियों में प्राधिकारी के समक्ष उद्योग स्पष्ट रूप से प्रमुख अनुपात बनाता है।
 - x. याचिकाकर्ताओं ने निरंतर क्षति का दावा नहीं किया है, परंतु क्षति के बार-बार होने की संभावना का दावा किया है। यद्यपि, घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति व्यापक रूप से घरेलू उद्योग के निष्पादन के आधार पर

- निर्धारित की जाती है और इसीलिए घरेलू उद्योग का गठन और निर्माण उस मामले में ज्यादा संगत और महत्वपूर्ण बनता है जब शुल्क बढ़ाने का अनुरोध क्षति की संभावना अथवा बार-बार होने के आधार पर हो, प्राधिकारी के लिए क्षति के बार-बार होने की संभावना का निर्धारण प्रभावित करने वाले मानदंड संगत हैं।
- xi. यह दर्शाने के लिए रिकार्ड में कोई सूचना नहीं है कि भाग न लेने वाले भारतीय उत्पादकों की सूचना ऐसी है कि वह क्षिति के बार-बार होने की संभावना का अभाव सिद्ध करेगी। हितबद्ध पक्षकारों का ऐसा कोई दावा नहीं है कि भाग न लेने वाले उत्पादकों के आंकड़ों को हटाने से विश्लेषण में वास्तविक ह्रास होगा। यह हितबद्ध पक्षकारों की केवल एक अवधारणा है।
- xii. प्राधिकारी ने कई निर्धारण जारी किए हैं जिनमें याचिकाकर्ताओं का हिस्सा 50 प्रतिशत की दहलीज से काफी कम था। प्राधिकारी के लिए यह भी अनिवार्य नहीं है कि वे डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3 के अभिप्राय के अंतर्गत क्षति निर्धारित करें। याचिकाकर्ताओं ने यह दावा नहीं किया है कि पाटित आयातों से निरंतर क्षति हुई है। यह स्थिति होने पर किसी भी दशा में अनुच्छेद 3 के अभिप्राय के अंतर्गत क्षति का मुल्यांकन न तो संगत है और न ही आवश्यक है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- 17. इस संबंध में, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - शुल्क जारी रखने के लिए एक सशक्त समर्थन होना चाहिए। घरेलू उद्योग के उत्पादन में केवल 30 प्रतिशत है। प्रमुख अनुपात वाली कंपनियां इस याचिका का समर्थन नहीं कर रही हैं।
 - ii. अन्य भारतीय उत्पादकों का उत्पादन निकालने के लिए सूचना का कोई स्रोत नहीं दिया गया है।
 - iii. डीसीएम श्रीराम पात्र घरेलू उद्योग नहीं है क्योंकि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में एक निर्यातक से संबद्ध है और उसने क्षति की अवधि में विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है।
 - iv. रिलायंस इंडस्ट्रीज और फिनोलेक्स के लिए प्राप्त सूचना के स्नोत तथा जहां तक आधार का संबंध है, याचिकाकर्ताओं की पात्रता की गणना के संबंध में याचिका मौन है। आरआईएल और फिनोलेक्स के उत्पादन को घरेलू उत्पादकों द्वारा खुद ही सिद्ध किया जाना है, जब तक कि उसे किसी अन्य दस्तावेज से सिद्ध न किया जा सके।
 - v. रिलायंस "चीन जन. गण. सीमलेस ट्यूब और पाइप" पर भी रखा जाता है जिसमें आवेदक का केवल 27 प्रतिशत हिस्सा है। समर्थन पत्रों से याचिका के बावजूद प्राधिकारी ने माना कि समर्थकों से सूचना के अभाव में क्षिति और कारणात्मक संपर्क नहीं निकाला जा सका और जांच को रद्द कर दिया। जहां तक 30 प्रतिशत उत्पादन का संबंध है, याचिकाकर्ता के दावे की वैधता विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध नहीं की गई है।
 - vi. नियम 2(ख) के अनुसार, डीसीएम श्रीराम घरेलू उद्योग के अंतर्गत आने के लिए अपात्र है क्योंकि वह एक निर्यातक यथा एक्सियाल एलएलसी से संबद्ध है जिसने 50:50 संयुक्त उद्यम बनाने के लिए यथा श्रीराम एक्सियाल प्रा. लि. के साथ भागीदारी की।
 - vii. डीसीएम श्रीराम और एक्सियाल एलएलसी कानूनी तौर पर और प्रचालनात्मक रूप से श्रीराम एक्सियाल का विरोध करने की स्थिति में हैं। श्रीराम एक्सियाल ने संबद्ध देशों से आयात किए हैं जिससे उसने असंबद्ध उत्पादकों से भिन्न रूप से व्यवहार किया है। घरेलू उद्योग के आधार का, यदि अन्य आवेदक 25 प्रतिशत की दहलीज पर हैं तो मूल्यांकन करने के लिए डीसीएम श्रीराम के उत्पादन को घटाकर पुनः मूल्यांकन किया जाए।
 - viii. आरआईएल के प्रचालनों का घरेलू उद्योग की स्थिति निर्धारित करने के लिए विश्लेषण किया जाना चाहिए।
 - ix. आवेदकों का "घरेलू उद्योग" के रूप में आधार संदिग्ध है क्योंिक वे तथाकिथत रूप से संबद्ध सामानों का केवल 30 प्रतिशत उत्पादन करते हैं, यह दावा केवल इस संबंध में एक विवरण तथा उत्पादन आंकड़ों को छोड़कर किसी साक्ष्य से सिद्ध नहीं है, जिनका स्रोत प्रकट नहीं किया गया है। आरआईएल और फिनोलेक्स द्वारा जांच की अविध के दौरान उनके उत्पादन के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई जिनका भारत में प्रमुख

- उत्पादन है। इसके अतिरिक्त, चूंकि आरआईएल और फिनोलेक्स ने पूर्व जांचों में भाग लिया, परंतु इस निर्णायक समीक्षा से अलग रहे हैं, अतः आवेदक प्रमुख अनुपात नहीं बनाते।
- x. श्रीराम एक्सियाल द्वारा अनुपातों की तुलना डीसीएम श्रीराम के अपने उत्पादन और खपत से की जानी चाहिए जो कि उसके द्वारा किए गए आयातों के अनुपात को सही-सही दर्शाएगा और यह दर्शाएगा कि क्या वह काफी है। घरेलू उद्योग के आधार का मूल्यांकन डीसीएम श्रीराम को अलग करने के बाद पुनः किया जाना चाहिए।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 18. यह याचिका केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड, जिसे अब मैसर्स केमप्लास्ट कुड्डालोर विनाइल लिमिटेड के रूप में जाना जाता है, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड और डीसीएम श्रीराम द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं के अलावा, भारत में संबद्ध सामानों के दो अन्य उत्पादक अर्थात रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैं।
- 19. यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता कंपनियों ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। तथापि, मैसर्स डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के एक संबद्ध पक्षकार अर्थात मैसर्स श्रीराम एक्सियाल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पीवीसी कंपाउंड के उत्पादन में लगा हुआ है, ने थाइलैंड और अन्य देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश (थाइलैंड) से श्रीराम एक्सियाल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए आयात केवल 62 मी. टन के हैं जो कि भारत में उत्पाद, भारतीय उत्पादन और खपत तथा डीसीएन श्रीराम लिमिटेड के उत्पादन के आयातों की तुलना में अत्यधिक नगण्य हैं।
- 20. यह तर्क दिया गया है कि डीसीएन श्रीराम लिमिटेड संयुक्त राज्य अमेरिका में एक उत्पादक से संबद्ध है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2(ख) की व्याख्या में यह प्रावधान है कि घरेलू उत्पादकों को निर्यातकों अथवा आयातकों से संबद्ध तभी माना जाएगा यदि (क) उनमें से एक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे को नियंत्रित करता है (ख) दोनों किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्क्ष रूप से नियंत्रित हैं (ग) वे इकट्ठे किसी तीसरे व्यक्ति से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित हैं (ग) वे इकट्ठे किसी तीसरे व्यक्ति से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित हैं, बशर्ते कि उनका विश्वास करने अथवा संदेह करने का आधार है कि संबंध का प्रभाव ऐसा है कि उत्पादकों का कारण गैर-संबद्ध उत्पादकों से भिन्न है। यह नहीं दर्शाया गया है कि यह विश्वास करने अथवा संदेह करने के आधार हैं कि संबंध का प्रभाव ऐसा है कि उत्पादक असंबद्ध उत्पादकों से भिन्न रूप से व्यवहार करे।
- 21. यह नोट किया जाता है कि श्रीराम एक्सियाल प्राइवेट लिमिटेड ने इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्पादक के आंशिक स्वामित्व में है, एक्सियाल एलएलसी से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। यह सहयोग तकनीकी प्रकृति का है। जैसा कि पहले नोट किया गया है, श्रीराम एक्सियाल प्राइवेट लिमिटेड ने अन्य देशों से सामानों का आयात किया है जो भारत में उत्पाद के आयातों, भारतीय उत्पादन और खपत तथा उत्पादन के संबंध में बहुत कम है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि इन आयातों से डीसीएम श्रीराम लिमिटेड नियमावली के तहत अपात्र घरेलू उद्योग नहीं हो जाता।
- 22. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ताओं का उत्पादन में कुल भारतीय उत्पादन का केवल 30 प्रतिशत है, अन्य घरेलू उत्पादकों से सूचना मांगी गई थी। तथापि, उन उत्पादकों ने वर्तमान जांच में उत्तर नहीं दिया है। यह भी नोट किया जाता है कि किसी निर्णायक समीक्षा जांच में जहां पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने का अनुरोध घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति पर आधारित न हो और उसके बजाए क्षति के बार-बार होने की संभावना के आधार पर हो, निर्यातकों की सूचना ही यह जांच करने के लिए अधिक व्यावहारिक होती है कि क्या क्षति के बार-बार होने की संभावना मौजूद है अथवा नहीं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन के उत्तर में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने उत्तर दिया है कि मैसर्स श्रीराम एक्सियाल एलएलसी को अलग कर दिया जाए, मैसर्स आरआईएल ने भाग नहीं लिया है और एक दक्ष यूनिट होने के नाते उसकी प्रतिभागिता की स्थिति में भी एनआईपी शामिल की जाएगी और इससे क्षति की संभावना प्रभावित होगी।
- 23. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी मानते हैं कि याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादन समान उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन का "प्रमुख अनुपात" है और यह कि आवेदन पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के तहत "आधार" की अपेक्षाओं को पूरा करता है (यहां तक कि यद्यपि वह निर्णायक समीक्षा के स्तर पर लागू नहीं था) और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है।

ङ. विविध अनुरोध

ङ.1 घरेलू उद्योग के विचार

24. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- ं. घरेलू उद्योग ने यूरोपीय संघ, मैक्सिको, ताइवान, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों के विरुद्ध उनके इस विचार के आधार पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने की मांग करते हुए आवेदन पत्र दायर किया कि इन देशों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क बढ़ाना उपयुक्त है। प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर केवल चीन, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध जांच की शुरूआत करना उपयुक्त माना। किसी भी दशा में यह प्राधिकारी पर है कि वे निर्णय लें कि किसके विरुद्ध जांच शुरू की जानी चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकार इस संबंध में जांच की शुरूआत की अधिसूचना देख सकते हैं।
- ii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि भारतीय उत्पादक विभिन्न उत्पादों में बाजार हिस्सा और बढ़ाने के एक व्यापारिक अस्त्र के रूप में लेते हैं, यह देखा जा सकता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ही दी गई सूची यह दर्शाती है कि वे केवल कास्टिक सोडा (जिसमें एएमएआई द्वारा याचिकाएं दायर की गई हैं और देश में उत्पाद के लिए 36 से अधिक उत्पादक हैं तथा जहां डीसीडब्ल्यू, डीसीएन और केमप्लास्ट भारत में कुछ ही उत्पादक हैं), सोडा ऐश (सोडा ऐश के अग्रणी उत्पादक देश में जीएचसीएल, निरमा और टाटा केमिकल्स हैं) का उल्लेख कर रहे हैं। याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन मैथिलीन क्लोराइड का मुश्किल से 10 प्रतिशत है (जिसमें केमप्लास्ट सनमार का उत्पादन पुनः भारतीय उत्पादन से काफी कम है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल देश में इस उत्पाद का अग्रणी उत्पादक है)। पीवीसी पेस्ट रेसिन ही वह है जिसने केमप्लास्ट सनमार एक मात्र उत्पादक है और जिसने पाटनरोधी कानून के तहत राहत ली है।
- iii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी के समक्ष भ्रामक स्थिति प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस जांच के लिए अथवा अन्य जांचों के लिए जो संगत है, वह यह है कि क्या विचाराधीन उत्पाद पाटित कीमतों पर भारत को निर्यात किया जा रहा है और क्या उससे भारतीय उद्योग को क्षति हो रही है। यह तथ्य कि भारतीय उद्योग ने कई अन्य उत्पादों के लिए कानून के तहत राहत ली है, इस प्रक्रिया में पूर्णतः अवास्तविक है।
- iv. विचाराधीन उत्पाद की पहचान में शामिल कोई विशेष सिद्धांत नहीं है। सभी लेन-देनों जिनमें विवरण में "सस्पेंसन" उल्लिखित किया गया है, को विचाराधीन उत्पाद के रूप में माना गया है। वर्तमान मामला एक निर्णायक समीक्षा होने के नाते तथा उत्पाद में विविध विवरण न होने के नाते आयात सिद्धांत को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
- v. एमसीए से प्राप्त की जा सकने वाली सूचना व्यापक सूचना से पूर्णतः भिन्न है जो कि वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है। इस प्रकार, वार्षिक रिपोर्ट प्रकृति में गोपनीय है। तथापि, याचिकाकर्ताओं ने एमसीए से जो सूचना डाउनलोड की है, अलग से दायर की गई है।
- vi. जनिहत का पहलू केवल मांग आपूर्ति अंतराल तक सीमित नहीं हो सकता, यह मानते हुए कि काफी नए निवेश चल रहे हैं, पाटनरोधी शुल्क लगाना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि ये निवेश अर्थक्षम रहें। भारत सरकार ने पहले पाटनरोधी शुल्क लगाया है और उसे बढ़ाया भी है जो अपने आप में यह सिद्ध करता है कि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाना जनिहत में होगा।
- vii. याचिकाकर्ताओं ने पहले ही वह समस्त सूचना प्रकट की है जो कि प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई परिपाटी के अनुसार प्रकट की जानी अपेक्षित है।
- viii. याचिकाकर्ता इस कारण पाटन मार्जिन के संबंध में कोई अनुरोध करने में असमर्थ हैं कि निर्यातकों ने लगभग पूरी प्रश्नावली के उत्तर गोपनीय होने का दावा किया है। प्रश्नावली के उत्तर का अगोपनीय रुपांतर मात्र एक कोरी औपचारिकता है।
- ix. निर्यातकों द्वारा दावा की गई गोपनीयता व्यापार सूचना के अनुसार नहीं है। दायर किए गए निर्यातक प्रश्नावली के उत्तरों में कमी है और किसी महत्वपूर्ण सूचना से अलग है।

ङ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- 25. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:
 - i. शुल्क 11 वर्ष से अधिक के लिए लागू रहा है और उसने अपना अपेक्षित प्रयोजन पूरा किया है।
 - ii. संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों का संचय चीन और थाइलैंड से आयातों से संभव नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात 3 प्रतिशत से कम हैं और चीन तथा थाइलैंड से आयातों से संचयन नहीं होता।
 - iii. याचिका में निहित सूचना पर विचार करते हुए अथवा वस्तुतः उसके अभाव में जांच शुरू नहीं की गई है। पर्याप्त कारणों के बिना अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। इसके अतिरिक्त, उसमें पाटन और/अथवा क्षति तथा जांच की शुरूआत का औचित्य बनाने के लिए संभावना संबंधी पर्याप्त/पर्याप्त साक्ष्य भी नहीं हैं।
 - iv. जांच की शुरूआत संबंधी अधिसूचना में संबद्ध देशों को हटाए जाने के कारण नहीं दिए गए हैं।
 - v. विभिन्न उत्पादों में बाजार हिस्सा और बढ़ाने के लिए भारतीय उत्पादकों द्वारा एक व्यापारिक हथियार के रूप में पाटनरोधी शुल्क का प्रयोग किया गया है। पाटनरोधी शुल्क के मामले की कंपनी वार सूची दी गई है।
 - vi. सोडा ऐश (तुर्की और रूस) के मामले में प्राधिकारी द्वारा किया गया निर्धारण संगत है। जहां मामला घरेलू उद्योग के अच्छे निष्पादन के आधार पर शुरू नहीं किया गया था।
 - vii. अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। आयात सिद्धांत को अनुचित रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है। एमसीए को शुल्क का भुगतान कर केमप्लास्ट की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है, फिर भी वार्षिक रिपोर्ट को गोपनीय होने का दावा किया गया है।
 - viii. याचिकाकर्ता द्वारा सुझाए गए अनुसार 10 वर्षों की अवधि के लिए माह दर माह आधार पर संबद्ध देशों का "परीक्षण" अध्ययन का व्यवहार पाटन एवं क्षति की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए निर्धारित विश्लेषण का भाग नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि कुछ देशों की कीमत सबसे कम होने का नाते उपर्युक्त अध्ययन में दी गई थी। याचिकाकर्ता यह नहीं समझ पाए कि चीनी कीमतें 120 में से 92 मामलों में सबसे कम कीमत नहीं थीं।
 - ix. प्राधिकारी को अपने निर्धारण का आधार स्पष्ट करना चाहिए कि केवल चीन जन. गण., थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध जांच की शुरूआत के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त औचित्य था। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इस संबंध में कुछ अन्य देशों का चयन न किए जाने के कारण प्रकट करें जो कि समान सूचना जांच की शुरूआत की मांग करने के लिए याचिकाकर्ताओं (संबद्ध देशों की तरह) द्वारा दी गई थी।
 - प्राधिकारी ने 08 देशों में से पांच देशों को उनको हटाने के उचित कारण दिए बिना उन्हें अलग कर दिया है। महानिदेशक को स्पष्ट आदेश देना चाहिए कि क्यों अन्य कंपनियों को हटाया गया है। विगत में पहली निर्णायक समीक्षा जांच के दौरान प्राधिकारी ने खुद ही संबद्ध देशों के क्षेत्र से कोरिया गणराज्य को अलग किया था और उसको हटाने के कारण स्पष्ट रूप से दिनांक 04 अप्रैल, 2014 के अंतिम जांच परिणाम संख्या 21/29/2011-डीजीएडी के पैरा 155 के अनुसार स्पष्ट किए गए थे। समान स्थिति यहां भी लागू की जानी चाहिए।
 - xi. हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार केमप्लास्ट के पास भारत में क्षमता अभिवृद्धि के लिए कोई योजनाएं नहीं हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मार्च, 2016 में पेट्रोकेमिकल प्लांट की कठिनाईयों को दूर करने और उसके विस्तार के लिए परियोजना रिपोर्ट जारी की है। वह अप्रैल, 2017 के दौरान अनुमोदित हो गई थी, तथापि उसने विस्तार आज की तारीख तक शुरू नहीं किया है। इस प्रकार, भारतीय उद्योग मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादकों पर पूर्णतः निर्भर नहीं रह सकता।
 - xii. याचिकाकर्ताओं ने अपने निवेशों के संबंध में टालमटोल किया है जिससे माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को गलत सूचना प्रकट करने का संदेह बनता है।
 - xiii. याचिकाकर्ताओं ने निर्यातकों द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता के विभिन्न आरोप लगाए हैं। निर्यातक याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता के अपने आरोपों को प्रस्तुत करते हैं।
 - xiv. आवेदन पत्र का अगोपनीय रुपांतर नियम 7 तथा व्यापार सूचना के अनुसार नहीं है।

- xv. नियमावली के तहत केवल प्राधिकारी ही सूचना की मांग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, नियम शिष्टमंडल को भी प्रतिबंधित करते हैं। श्री जे. एम. बिश्नोई को प्राधिकारी की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। नियमों के मद्देनजर जांच की अविध के बाद के आंकड़े मंगाने के लिए निर्देश निर्दिष्ट प्राधिकारी के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी नहीं किए जा सकते थे। इसके अतिरिक्त, दिनांक 09.04.2019 के पत्र में यह गलत उल्लेख किया गया है कि वह सूचना मांगी गई थी और मौखिक सुनवाई के समय सूचित की गई थी। सूचना प्रदान करने का निर्देश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी न किए जाने के कारण औचित्य के बिना है।
- xvi. विषयगत पत्र के अनुसरण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत जांच की अवधि के बाद की सूचना को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपने अंतिम निर्धारण के प्रयोजन के लिए नकार दिया जाना चाहिए।
- xvii. व्यापार सूचना 5/2018 के मद्देनजर, यदि गृह बाजार में उत्पादक/निर्यातक की बिक्री के आधार पर उनके द्वारा सामान्य मूल्य का दावा किया गया है तो लेन-देन वार तीसरे देश के आंकड़े नहीं देखे जाने हैं और ऐसे मामलों में "तीसरे देशों को निर्यातों के संबंध में इस प्रश्नावली में निर्धारित प्रपत्र की उपेक्षा की जाए।" व्यापार सूचना में यह उल्लेख है कि वह सभी पूर्व अनुदेशों और पूर्व में जारी व्यापार सूचनाओं के अतिक्रमण में है।
- xviii. वह सूचना प्रदान करने के लिए निर्देश नहीं दिए जा सकते जो प्राधिकारी द्वारा परिभाषित जांच की अवधि से बाहर है क्योंकि जांच की अवधि से बाहर के आंकड़ों पर विचार करने के लिए नगर निगम कानून अथवा पाटनरोधी करार के तहत कोई प्रावधान नहीं है। परिभाषित जांच की अवधि वस्तुपरक एवं निष्पक्ष निर्धारण का आधार बनाती है जबकि चुनिंदा मामलों में जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों को लेने से विषयपरकता असंगत तथा स्वेच्छाचारी होगी।
- xix. यदि प्राधिकारी का यह मत है कि जांच की अवधि के बाद के आंकड़े संगत हो सकते हैं तो फिर उसे जांच की अवधि बढ़ाने का अधिकार है। जब तक जांच की अवधि बढ़ाई नहीं जाती है, शामिल अवधि के अंतर्गत न ली गई किसी भी सूचना का कोई कानूनी आधार नहीं है और पाटन तथा क्षति निर्धारण के प्रयोजन के लिए निरर्थक होगी।
- xx. यह मानने पर भी कि जांच की अवधि के बाद के आंकड़े मांगने का अभिप्राय जांच की अवधि का विस्तार है, उससे तीन माह तक सूचना प्रदान करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को दिया गया समय कम हो गया है जो कि नियम 6(4) के क्षेत्र से बाहर है जो न्यूनतम 30 दिन की अनुमित देता है। ऐसे मामले में घरेलू उद्योग को भी निर्देश दिए जाएं कि वह अपेक्षित आंकड़े प्रस्तुत करे और हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाए जिसका अभिप्राय दूसरी सुनवाई, नए अनुरोध एवं प्रत्युत्तर होगा।

ङ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 26. संगत माने गए अनेक विविध अनुरोधों की जांच निम्नलिखित के रूप में की गई है:
 - ं। जहां तक कुछ देशों को हटाए जाने के कारणों के संबंध में उठाए गए तर्कों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरूआत की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट था कि यूरोपीय संघ, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ताइवान, जापान और मलेशिया से आयातों के संबंध में समीक्षा जांच करने का अपर्याप्त औचित्य था, इस प्रकार समीक्षा जांच का क्षेत्र चीन जन. गण., थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से ही विचाराधीन उत्पाद के आयातों तक प्रतिबंधित था।
 - ii. जहां तक आयात सिद्धांत को प्रकट न करने के तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि सभी लेन-देनों, जिनमें विवरण का उल्लेख "सस्पेंसन" किया गया है, पर वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के रूप में विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने लेन-देन वार आयात आंकड़ों की हार्ड कॉपी दायर की थी जो यह दर्शाती है कि विचाराधीन उत्पाद के रूप में घरेलू उद्योग द्वारा माने गए सभी लेन-देनों में विवरण में "सस्पेंसन" शामिल है। तथापि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में छांटे गए लेन-देन वार आंकड़े नहीं मांगे।
 - iii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि देश में मांग उत्पादकों की आपूर्ति की क्षमता से अधिक है, यह नोट किया जाता है कि देश में मांग आपूर्ति के अंतराल से पाटन का औचित्य बनाना नहीं होना चाहिए। जांच की अवधि

के दौरान सभी संबद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद सकारात्मक है।

- iv. जहां तक सूचना की गोपनीयता से संबंधित तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराया। आयातों, निष्पादन मानदंडों और घरेलू उद्योग के क्षति मानदंडों से संबंधित सूचना सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध करा दी गई है। व्यापार संवेदी सूचना परिपाटी के अनुसार गोपनीय रखी गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जो भी सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है, उसे गोपनीय नहीं माना जा सकता।
- v. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि चीन और थाइलैंड से आयातों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के आयातों का संचयन है, यह नोट किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह नहीं पाया है कि घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हो रही है। तीन देशों के लिए अलग सूचना प्रत्येक देश के लिए अलग से किए गए संभावना के विश्लेषण के साथ रिकार्ड में है।
- vi. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क 11 वर्षों से लागू है और वह अपना अपेक्षित प्रयोजन पूरा कर रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वे नियमानुसार पाटन एवं क्षति के बार-बार होने की संभावना के साक्ष्य की जांच करने का प्रस्ताव करते हैं।

च. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 घरेलू उद्योग के विचार

- 27. घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुरोध किया है:
 - ं। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे कृपया भारत में बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से विचाराधीन उत्पाद की कीमत पर विचार करें। इस अवधि में काफी निर्यात ताइवान और कोरिया से किए गए हैं। अतः प्राधिकारी कृपया सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए भारत में ताइवान और कोरिया से आयात कीमत अथवा ताइवान और कोरिया से औसत कीमत अपनाकर विचार करें।
 - ii. बाजार अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए याचिकाकर्ताओं ने प्रमुख व्यापारिक पत्रिकाओं अर्थात आईएचएस केमिकल पब्लिकेशन में उल्लिखित संबद्ध सामानों की कीमतों का उल्लेख किया है। आईएचएस केमिकल्स के संबंध में ब्यौरे रिकार्ड में हैं।
 - iii. सुस्थापित व्यापार पत्रिकाओं में उल्लिखित प्रकाशित यूनिटें यह स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार में उत्पाद की कीमत उस कीमत से काफी अधिक है जिस पर भारत को सामानों का निर्यात किया गया है।
 - iv. थाइलैंड में सामान्य मूल्य का दक्षिण पूर्व एशिया के लिए आईएचएस रिपोर्ट में प्रकाशित कीमतों के आधार पर दावा किया गया है।
 - v. निर्यात कीमत भारत में सभी ज्ञात आयातकों के आयातों की भारित औसत कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। निर्यात कीमत संबद्ध देशों से प्रति यूनिट आयात कीमत के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः निर्यात कीमतें समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय और सारसंभाल प्रभारों के लिए समायोजित की गई हैं।
 - vi. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का परिकलन यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे कृपया वीसीएम और पीवीसी कीमतों में काफी कीमत अंतरों के कारण मासिक पाटन मार्जिन निर्धारित करें।

- vii. आयातों में वृद्धि अन्य देशों से अधिक है। तथापि, जिन कीमतों पर अन्य देशों से सामान आए हैं, वे कीमतें उन कीमतों से काफी अधिक हैं जिन पर संबद्ध देशों से सामान आए हों। संबद्ध देशों के लिए क्षेत्र का निर्धारण करने हेतु आयात मात्रा पर निर्णायक कारक के रूप में विचार नहीं किया जा सकता। दूसरा संगत आधार वह कीमत है जिस पर विभिन्न देशों से सामान आए हैं।
- viii. आईएचएस में प्रकाशित कीमतों को पीवीसी उत्पादकों और वैश्विक रूप से उपभोक्ताओं द्वारा बहुत विश्वसनीय माना जाता है। सर्वाधिक वैश्विक व्यापार आईएचएस द्वारा उल्लिखित कीमतों को देखने के बाद होता है। किसी भी तर्क कि आईएचएस में उल्लिखित कीमतें अविश्वसनीय हैं, को रद्द किया जाना अपेक्षित है।
- ix. चीन के मामले में और अनुबंध-। के पैरा 7 के प्रावधानों पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य तीसरे देश से भारत सिहत अन्य देशों में कीमतों के आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित होता है। तद्नुसार, ताइवान अथवा कोरिया, अथवा ताइवान और कोरिया से आयात कीमत पर चीन के मामले में सामान्य मुल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जा सकता है।
- x. दिसंबर, 2015 के बाद 60 से अधिक मामलों में प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम के संबंध में संदर्भ दिया जाता है जिनमें प्राधिकारी ने अनुबंध-l के पैरा 7 में उल्लिखित प्रावधानों को अपनाने के बाद सामान्य मूल्य निरंतर निर्धारित किया है। वर्तमान मामले की कानूनी स्थिति अथवा तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं है जो इस संबंध में भिन्न विचार का औचित्य बनाए।
- xi. आईएचएस द्वारा दी गई सूचना में "केवल लाइसेंसधारी ग्राहकों के उपयोग के लिए" योग्यता होती है। इसके मद्देनजर, याचिकाकर्ता आईएचएस रिपोर्ट को सार्वजिनक करने की स्थिति में नहीं हैं। आईएचएस रिपोर्ट वह है जिसका प्रयोग अधिकांशतः वैश्विक रूप से पीवीसी रेसिन के अग्रणी उत्पादकों द्वारा किया जाता है। उत्तरदाता याचिकाकर्ताओं द्वारा विश्वास की गई आईएचएस रिपोर्ट की अपनी प्रति ला सकते थे। आईएचएस रिपोर्ट उस किसी के लिए भी उपलब्ध है जो उसे लेना चाहे।

च.2 हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- 28. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. तीसरे देशों से आयात संबद्ध देशों से आयात की अपेक्षा बहुत तीव्र दर पर बढ़े हैं। अन्य देशों से पाटन हो रहा है।
 - ii. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्माण के संबंध में विभिन्न विसंगतियां हैं जो याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुमानित पाटन मार्जिन को प्रभावित करती हैं।
 - iii. याचिकाकर्ताओं ने देरी से अपने लिखित अनुरोधों में सुझाव दिया कि भारतीय पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 7 के अनुसार चीन जन. गण. में संबद्ध सामानों का सामान्य मूल्य भारत में बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देशों यथा ताइवान और कोरिया गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आधार पर निर्मित किया गया है। प्रतिनिधि देश के इस चयन में उचित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। प्रथमतः उपयुक्त प्रतिनिधि देश के चयन का प्रस्ताव जांच में पक्षकारों के बजाए प्राधिकारी की ओर से जाना चाहिए। दूसरे जब निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह प्रस्ताव कर दिया गया हो तो चुने गए प्रतिनिधि देश की उपयुक्तता पर टिप्पणी करने के लिए उचित अवसर दिया जाना चाहिए। अंततः ऐसी टिप्पणियों के बाद ही यह मूल्यांकन किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच के प्रयोजन के लिए प्रतिनिधि देश को अंतिम रूप देने की कार्रवाई कर सकते हैं।
 - iv. िकसी प्रतिनिधि देश के चयन के लिए प्रक्रिया के अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि चुने गए प्रतिनिधि देश में उत्पादकों से प्राधिकारी को उत्तर प्राप्त होने चाहिए जिनमें उनकी कार्यप्रणाली, उत्पादन लागत और बिक्री कीमत से संबंधित सूचना दी गई हो। विशेष रूप से, कई पूर्व जांचों में प्राधिकारी ने कुछ देशों को उपयुक्त प्रतिनिधि देश उन देशों में उत्पादकों से उत्तर उपलब्ध न होने के कारण ही विचार करने को निरस्त कर दिया।

- v. याचिकाकर्ताओं ने असिद्ध आधार पर ताइवान और कोरिया गणराज्य से आयातों कीमतों में समायोजन किए। आयात कीमतों अथवा भाड़े, बीमा और अन्य प्रभारों अथवा समायोजनों के लिए कोई स्रोत नहीं दिए गए थे।
- vi. प्रतिभागी निर्यातकों के खपत मानदंडों पर सामान्य मूल्य निर्मित किए जाने पर भी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जाना चाहिए।
- vii. निर्यात कीमत "निर्मित करने" के लिए कोई कारण अथवा आधार नहीं है। प्राधिकारी के पास चीन जन. गण. से उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर हैं और उन्हें देखा जाए क्योंकि प्रत्येक प्रतिभागी चीनी उत्पादक/निर्यातक के लिए निवल निर्यात कीमत सिद्ध करने के लिए उसके द्वारा सत्यापित है।
- viii. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत चीनी व्यापारियों के नाम और एसोसिएशन के प्रतिभागी सदस्यों के नाम मेल नहीं खाते। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं ने भारत में अपने निर्यात की कीमतों की तुलना शेष विश्व में निर्यातों की कीमतों से की है।
- ix. ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ताओं ने जिनजियांग झोंगताई केमिकल कं. लि., शानडोंग जिनफा इम्पॉर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि. और यिबिन तियुनुआन ग्रुप कं. लि. के सिवाय उन व्यापारियों से संबंधित आंकड़े दिए हैं जो वर्तमान जांच में पक्षकार नहीं हैं। इन तीनों व्यापारियों के मामले में शेष विश्व में निर्यातों के लिए कीमतों की तुलना में भारत में निर्यातों के लिए कीमतों के बीच कीमत तुलना भारतीय कीमतें 2 प्रतिशत कम होने पर केवल 2 प्रतिशत का अंतर दर्शाती हैं। याचिकाकर्ता समानांतर रूप से यह दावा करते हैं कि तीसरे देशों को निर्यातकों की कीमत भारत में उनकी कीमतों से कम हैं (और यह कि उनके भारत में आने की संभावना है), यह पूर्णतः खत्म हो जाता है।
- x. यह अनुरोध किया गया था कि इस जांच के लिए याचिका में उल्लिखित संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्पादकों से संबंधित सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन याचिका के अनुसार उत्तरी अमेरिका के बाजार के लिए आईएचएस रिपोर्ट (आईएचएस) में प्रकाशित कीमतों पर आधारित था। जांच की अवधि के दौरान सामान्य मूल्य 80-100 भारतीय रुपए प्रति किलोग्राम था और पाटन मार्जिन माह के आधार पर 70-80 प्रतिशत दर्शाया गया था। तथापि, परिकलन के ब्यौरे नहीं दिए गए थे।
- xi. उपयुक्त सामान्य मूल्य का परिकलन प्रकाशित कीमत सूचकांक की परिशुद्धता पर विश्वास करता है। शिनटेक का तर्क है कि उत्तरी अमेरिका के लिए आईएचएस कीमत सूचकांक इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने हेतु सूचना का उपयुक्त स्रोत नहीं है।
- xii. आईएचएस संविदा कीमत सूचकांक संयुक्त राज्य अमेरिका में पीवीसी बाजार में वास्तविक कीमतों के पूर्ण मूल्य का स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है और उनके प्रयोग से डब्ल्यूटीओ तथा भारतीय विनियम के तहत सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत की अनुचित तुलना होगी। याचिका में उल्लेख है कि याचिकाकर्ताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार के लिए आईएचएस रिपोर्ट से कीमत संबंधी सूचना का प्रयोग किया जो स्पष्ट रूप से जांच के प्रयोजन के लिए उपयुक्त नहीं है।
- xiii. इसके बजाए, आईसीआईएस स्थल कीमत सूचकांक सामान्य मूल्य और जिसका सार्वजनिक स्रोतों के विरुद्ध औचित्य बनाया जा सकता है तथा जांच की जा सकती है और वर्तमान जांच में जो अन्य सूचना उपलब्ध है, के परिकलन के लिए बेहतर विकल्प पेश करता है
- xiv. सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा मानी गई कीमतें अविश्वसनीय और अस्वीकार्य हैं। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि ये दरें कारखानागत स्तर पर हैं। याचिकाकर्ताओं ने स्वेच्छाचारी समायोजनों का दावा किया है।
- xv. डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 11.3: पाटनरोधी करार और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 23(1ख) में अधिदेशित है कि निर्णायक समीक्षा की शुरूआत घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत सिद्ध अनुरोध पर की जानी चाहिए। याचिका में घरेलू उद्योग ने विशेष रूप से बिना यह उल्लेख किए हुए कि कौन सी कंपनी है, एक दक्ष याचिकाकर्ता कंपनी की उत्पादन लागत के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार वाले देशों के लिए एक व्यापारिक पत्रिका अर्थात आईएचएस केमिकल पब्लिकेशन में दिए गए आंकड़ों पर सामान्य मूल्य निर्मित करने के लिए विश्वास किया गया है।

- xvi. व्यापार पित्रकाओं में उल्लिखित कीमतें स्वीकार्य साक्ष्य अथवा न्यायिक रूप से नोट करने योग्य तथ्य तब तक नहीं हैं जब तक उस देश के सार्वजिनक दस्तावेजों के आधार पर न हों जिसके लिए सामान्य मूल्य का पिरकलन किया जा रहा है, जैसा कि डाई स्टफ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडियाः 2003 (157) ईएलटी 154 (ट्राई-डेल.) में माना गया है जिसमें यह पाया गया था कि पित्रका के आंकड़ों में "तथ्य" नहीं है और असंगत है। घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख नहीं किया है कि आईएचएस केमिकल पब्लिकेशन में आंकड़ों को सार्वजिनक दस्तावेजों से लिया गया है अथवा उस सूचना को विश्वसनीय अथवा सही सिद्ध किया गया है। अतः व्यापार पित्रकाओं पर आधारित सामान्य मूल्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार, निर्यात कीमत में समायोजनों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया था। यद्यिप, अंतिम जांच पिरणाम सत्यापित आंकड़ों पर जारी किये जाते हैं, तथापि, जांच की शुरूआत भी स्वीकार्य साक्ष्य के आधार पर होनी चाहिए क्योंकि अन्यथा उसके संबंध में कानूनी अपेक्षाएं बेकार हो जाएंगी।
- xvii. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित सामान्य मूल्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि (i) प्रत्येक माह के लिए मानी गई उच्चतम कीमत और निम्नतम कीमत का औसत, (ii) असिद्ध "सुपुर्दगी लागत" कृत्रिम रूप से सामान्य मूल्य बढ़ाने के लिए जोड़ी गई है, (iii) आईएचएस पब्लिकेशन में कीमतें क्षेत्र वार हैं न कि देश वार, (iv) यह ज्ञात नहीं है कि क्या आईएचएस पब्लिकेशन में आंकड़ों में पीवीसी सस्पेंसन रेसिन की सभी किस्में अथवा केवल विचाराधीन उत्पाद है, (v) यद्यपि सामान्य मूल्य कारखानागत स्तर पर निर्धारित किया जाता है, तथापि आईएचएस पब्लिकेशन उस स्तर को नहीं दर्शाता जिस पर सामान्य मूल्य निकाला गया है, किन समायोजनों पर विचार किया गया है, क्या कीमतें थोक अथवा खुदरा स्तर पर थीं, क्या कोई छूटें शामिल की गई थीं आदि। जब तक इन समायोजनों को ध्यान में नहीं लिया जाता तब तक सामान्य मूल्य बढ़ा हुआ रहेगा।
- xviii. चीन के लिए निर्मित सामान्य मूल्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि (i) यह ज्ञात नहीं है कि किस याचिकाकर्ता कंपनी के आंकड़ों का प्रयोग उत्पादन लागतें निकालने के लिए किया गया है, (ii) "दक्षता" का मानक अपने आप में संदिग्ध है, (iii) यह मानना कि भारतीय उत्पादकों की लागत चीन के उत्पादकों की लागत के समान है, सही नहीं है, (iv) उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार वाले तीसरे देश में कीमत/निर्मित मूल्य पर चीन का सामान्य मूल्य निर्धारित करने में घरेलू उद्योग की विफलता यह उल्लेख करते हुए कि "विचाराधीन उत्पाद का चीन में सामान्य मूल्य इस कारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है", घरेलू उद्योग के अपने इस दावे का विरोधाभासी है कि आईएचएस पब्लिकेशन में सुचित कीमतों में "सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उपयुक्त, सही और पर्याप्त सुचना" है।
- xix. चीनी अभिगम नयाचार की समाप्ति के बावजूद भारतीय प्राधिकारियों ने गलत रूप से बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली दी है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

चीन

च.3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था के दावों की जांच, और सामान्य मूल्य का परिकलन

29. जांच की शुरूआत के स्तर पर याचिकाकर्ता ने चीन जन. गण. को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानकर अपनी अवधारणा के साथ कार्यवाही की। जांच की शुरूआत पर प्राधिकारी ने चीन में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी कि वे जांच की शुरूआत की सूचना का उत्तर दें और यह इस निर्धारण के लिए संगत सूचना दें कि क्या उनके आंकड़ों/सूचना को सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन के लिए अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं। तथापि, किसी भी चीनी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करते हुए उत्तर दायर नहीं किया है।

- 30. चाइनीज एसेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैः "जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगेः
 - (क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:
 - (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मुल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
 - (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
 - (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष किनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
 - (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
 - (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"
- 31. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि 15 (क) (ii) के प्रावधान, यद्यपि 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, परन्तु एसेसन प्रोटोकोल के 15 (क) (i) के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यू. टी. ओ. के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान में एम. ई. टी. स्तर का दावा करने पर पूरक प्रश्नावली में उपलब्ध करायी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरी की जाने वाली भारत की पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में अनुबंध मानदण्ड की अपेक्षा होती है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चूंकि, चीन के किसी भी प्रतिवादी उत्पादक, निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य गणना के बारे में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
- 32. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में यथा निहित अपनायी जाने वाली सामान्य पहुंच मूल्य के बारे में कोई निवेदन नहीं किया गया है। इसके अलावा, दक्षिण कोरिया को छोड़कर कुछ देशों पर संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, जो व्यवहार्य विकल्प प्रतीत होता है, क्योंकि इसकी मात्रा

चीन के साथ तुलनीय है। प्राधिकारी ने यथा उचित समझी पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय कच्चे माल की कीमतों को स्वीकार करते हुए विभिन्न लागत तत्वों का उचित नियामक समेत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य तैयार किए हैं ऐसे परिकलित मूल्य के बारे में कोरिया (कारखानागत स्तर पर) आयात मूल्य के साथ विस्तृत तौर पर समर्थन भी किया जाता है।

चीन जन. गण. के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण:-

- 33. वर्तमान जांच के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली (ई. क्यू.) दायर की:-
 - क. चिपिंग जिनफाँ पी. वी. सी. कंपनी लि० और शानडांग जिनफाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपनी लि० (निर्यातक)
 - ख. सी. एन. एस. जी. जिलान्ताई साल्ट क्लोरी अल्काली केमिकल कंपनी लि० (उत्पादक) और उसका संबद्ध निर्यातक सी. एन. एस. जी. जिलान्ताई साल्ट केमिकल (ग्रुप) कंपनी लि०
 - ग. यिबिन हाईफेंग हेरुई कंपनी लि० (उत्पादक) और उसका संबद्ध निर्यातक यिबिन तियानयुआन ग्रुप कंपनी लि०
 - घ. तियानजिन एल. जी. बोहाई केमिकल कंपनी लि० (उत्पादक)
 - ङ. तियाननेंग केमिकल कंपनी लि० (उत्पादक) और जिनजियांग टाइनी (ग्रुप) कंपनी लि० (उत्पादक)
 - च. तियानजिन डागू केमिकल कंपनी लि० (उत्पादक और निर्यातक) और बोहाई केमिकल एच. के. लि०
 - छ. जिनजियांग शेंगजिआंग क्लोर अल्काली कंपनी लि० (उत्पादक) और जिनजियांग झोंगताई केमिकल कंपनी लि० (निर्यातक)

पूर्वोक्त सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए कारखानागत निर्यात कीमत का नीचे दिए अनुसार मूल्यांकन किया है:-

34. यिबिन हाईफेंग हेरुई कंपनी लि॰ (''हेफेंग हेरुई") और यिबिन तियानयुआन ग्रुप कंपनी लि॰ (''यिबिन तियानयुआन")-

उत्पादक/निर्यातक ने *** डॉलर/मी. टन के समकक्ष सी. आई. एफ. मूल्य पर *** अमरीकी डॉलर के कुल बीजक मूल्य पर पी. ओ. आई. के दौरान भारत के लिए *** मी. टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने क्रमश: ***, ***, *** और *** के समुद्री माल भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन प्रभार और बैंक प्रभार पर (डॉलर/मी. टन. में) समायोजनों के बारे में विचार किया है। उपर्युक्त समायोजन करने के बाद में कारखानागत निर्यात कीमत *** डॉलर/मी. टन मानी है। पहंच मुल्य *** डॉलर/ मी. टन माना है।

35. सी. एन. एस. जी. जिलान्ताई साल्ट केमिकल (ग्रुप) कंपनी लि॰ और सी. एन. एस. जी. जिलान्ताई साल्ट क्लोरी अल्काली केमिकल कंपनी लि॰

उत्पादक/निर्यातक ने *** डॉलर/मी. टन के समकक्ष सी. आई. एफ. मूल्य पर *** अमरीकी डॉलर के कुल बीजक मूल्य पर पी. ओ. आई. के दौरान भारत के लिए *** मी. टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने क्रमश: ***, *** और *** के समुद्री माल भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन प्रभार और बैंक प्रभार पर (डॉलर/मी. टन. में) समायोजनों के बारे में विचार किया है। उपर्युक्त समायोजन करने के बाद में कारखानागत निर्यात कीमत *** डॉलर/मी. टन मानी है। पहुंच मूल्य *** डॉलर/ मी. टन माना है।

36. चिपिंग जिनफॉ पी. वी. सी. कंपनी लि॰ और शानडांग जिनफॉ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपनी लि॰

उत्पादक/निर्यातक ने *** डॉलर/मी. टन के समकक्ष सी. आई. एफ. मूल्य पर *** अमरीकी डॉलर के कुल बीजक मूल्य पर पी. ओ. आई. के दौरान भारत के लिए *** मी. टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने क्रमश: ***, *** और *** के समुद्री माल भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन प्रभार और बैंक प्रभार पर (डॉलर/मी. टन. में) समायोजनों के बारे में विचार किया है। उपर्युक्त समायोजन करने के बाद में कारखानागत निर्यात कीमत *** डॉलर/मी. टन मानी है। पहुंच मूल्य *** डॉलर/ मी. टन माना है।

37. तियाननेंग केमिकल कंपनी लि॰ और जिनजियांग टाइनी (ग्रुप) कंपनी लि॰

उपरोक्त उत्पादक/निर्यातक ने *** डॉलर/मी. टन के समकक्ष सी. आई. एफ. मूल्य पर *** अमरीकी डॉलर के कुल सकल बीजक मूल्य पर पी. ओ. आई. के दौरान भारत के लिए *** मी. टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने क्रमश: ***, ***, *** और *** के समुद्री माल भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन प्रभार और बैंक प्रभार पर (डॉलर/मी. टन. में) समायोजनों के बारे में विचार किया है। उपर्युक्त समायोजन करने के बाद में कारखानागत निर्यात कीमत *** डॉलर/मी. टन मानी है। पहुंच मूल्य *** डॉलर/ मी. टन माना है।

38. तियानजिन एल. जी. बोहाई केमिकल कंपनी लि॰

उत्पादक/निर्यातक ने *** डॉलर/मी. टन के समकक्ष सी. आई. एफ. मूल्य पर *** अमरीकी डॉलर के कुल बीजक मूल्य पर पी. ओ. आई. के दौरान भारत के लिए *** मी. टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने क्रमश: ***, *** और *** के समुद्री माल भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन प्रभार और बैंक प्रभार पर (डॉलर/मी. टन. में) समायोजनों के बारे में विचार किया है। उपर्युक्त समायोजन करने के बाद में कारखानागत निर्यात कीमत *** डॉलर/मी. टन मानी है। पहुंच मूल्य *** डॉलर/ मी. टन माना है।

39. तियानजिन डागू केमिकल कंपनी लि॰ और बोहाई केमिकल (एच. के.) लि॰

उत्पादक/निर्यातक ने *** डॉलर/मी. टन के समकक्ष सी. आई. एफ. मूल्य पर *** अमरीकी डॉलर के कुल बीजक मूल्य पर पी. ओ. आई. के दौरान भारत के लिए *** मी. टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने क्रमश: ***, *** और *** के समुद्री माल भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन प्रभार और बैंक प्रभार पर (डॉलर/मी. टन. में) समायोजनों के बारे में विचार किया है। उपर्युक्त समायोजन करने के बाद में कारखानागत निर्यात कीमत *** डॉलर/मी. टन मानी है। पहंच मुल्य *** डॉलर/ मी. टन माना है।

40. जिनजियांग शेंगजिआंग क्लोर - अल्काली कंपनी लि० और जिनजियांग झोंगताई केमिकल कंपनी लि०

उत्पादक/निर्यातक ने *** डॉलर/मी. टन के समकक्ष सी. आई. एफ. मूल्य पर *** अमरीकी डॉलर के कुल बीजक मूल्य पर पी. ओ. आई. के दौरान भारत के लिए *** मी. टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने क्रमश: ***, *** और *** के समुद्री माल भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन प्रभार और बैंक प्रभार पर (डॉलर/मी. टन. में) समायोजनों के बारे में विचार किया है। उपर्युक्त समायोजन करने के बाद में कारखानागत निर्यात कीमत *** डॉलर/मी. टन मानी है। पहंच मुल्य *** डॉलर/ मी. टन माना है।

41. अवशिष्ट श्रेणी

प्राधिकारी ने अवशिष्ट श्रेणी के लिए कम से कम निर्यात कीमत अर्थात कारखानागत निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य का हवाला दिया है।

च.3.2 यू. एस. ए.

42. <u>अमेरिकी सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों और अवशिष्ट कोऑपरेटिव उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और</u> कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण:-

मै॰ वेस्टलेक विनिल्स कंपनी एल. पी. (उत्पादक और निर्यातक); मै॰ एक्सियल एल. एल. सी. (संबद्ध उत्पादक); मै॰ वेस्टलेक विनिल्स इंक. (संबद्ध उत्पादक):-

सामान्य मुल्य:

मै० वेस्टलेक विनिल्स कंपनी एल. पी. (उत्पादक और निर्यातक, जिसमें मै० एक्सियल एल. एल. सी. (संबद्ध उत्पादक) और मै० वेस्टलेक विनिल्स इंक. (संबद्ध उत्पादक) शामिल हैं, ने ई. क्यू. आर. दायर की है। केवल मै० वेस्टलेक विनिल्स कंपनी एल. पी. ने पी. ओ. आई. के दौरान भारत के लिए केवल *** मी. टन 65 ग्रेड का निर्यात किया है।

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य के प्रयोजन के लिए चूंकि तीनों कंपनियां संबद्ध हैं, इसलिए इन सभी तीनों कंपनियों की घरेलू बिक्रियों के बारे में विचार करना होगा। तथापि, अलग-अलग तुलना करने के लिए भारत के लिए निर्यातित ग्रेड की घरेलू बिक्रियों पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादक/निर्यातक ने संबद्ध और असंबद्ध दोनों क्रेताओं के लिए घरेलू बाजार में बिक्री की है। इन दोनों ग्रुपों के कीमत संबंधी अंतरों को नोट करते हुए प्राधिकारी ने सभी तीनों कंपनियों के द्वारा के. 65 ग्रेड की घरेलू बिक्रियों को केवल असंबद्ध क्रेताओं के लिए ही स्वीकार किया है, क्योंकि संबद्ध क्रेताओं और असंबद्ध क्रेताओं की कीमतों में काफी अंतर है। घरेलू बिक्रियों को पर्याप्त मात्रा संबंधी परीक्षणों को पूरा करना होता है तथा ओ. सी. टी. परीक्षण के लिए

प्राधिकारी ने *** डॉलर/मी. टन के रूप में उत्पादन की भारित औसत कारखानागत लागत का हवाला दिया है। इस परीक्षण के आधार पर ***% बिक्रियां लाभप्रद होने योग्य नोट की हैं। तदनुसार क्रमशः ***, *** और *** की छूट, माल भाड़ा और क्रेडिट लागत (सभी तीनों किस्मों) के लिए छूट करने हेतु के. 65 ग्रेड के असंबद्ध ग्राहकों को घरेलू बिक्रियों पर समायोजनों (डॉलर/मी. टन) सहित सामान्य मूल्य *** डॉलर/मी. टन माना जाता है।

कारखानागत निर्यात कीमत:

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि केवल मै० वेस्टलेक विनिल्स कंपनी एल. पी. (उत्पादक/निर्यातक) ने *** डॉलर/ मी. टन पर भारत के लिए के. 65 ग्रेड का *** मी. टन का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने पैकिंग, समुदी माल भाड़े, बीमा, अंतर्देशीय माल भाड़े, पत्तन, क्रेडिट लागत, बैंक प्रभार पर क्रमशः ***, ***, ***, ***, *** के (डॉलर/ मी. टन में) समायोजनों की अनुमित दी है। कारखानागत निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य क्रमशः *** डॉलर/ मी. टन और *** डॉलर/ मी. टन स्वीकार किया जाता है।

43. मैं अॉक्सी विनिल्स एल. पी. (उत्पादक); और मैं अॉक्सी विनिल्स एक्सपोर्ट सेल्स एल. एल. सी. (अमरीका में संबद्ध व्यापारी)

सहयोगी उत्पादक/निर्यातक:

सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण:

ऑक्सी विनिल्स एल. पी. (''ओवीएलपी''), अमरीका से विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक है। ओवीएलपी ने अपने संबद्ध निर्यातक नामतः ऑक्सी विनिल्स एक्सपोर्ट सेल्स, एल. एल. सी. (''ओवीएलएलसी'') के माध्यम से निर्यात बाजारों (भारत सहित) के लिए बिक्रियां की हैं। ओवीएलएलसी ने असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से जांच अविध में विभिन्न निर्यात बाजारों में क्रमशः बिक्रियां की थीं। भारत के लिए दो विशेष असंबद्ध व्यापारियों नामतः ट्रिकॉन ड्राई केमिकल्स एल. एल. सी. और आई. सी. सी. केमिकल कारपोरेशन (''आईसीसी'') के माध्यम से बिक्रियां की गई थीं।

प्राधिकारी ने उत्पादन लागत के विभिन्न पहलुओं, घरेलू विक्रय मूल्य, भारत तथा अन्य देशों के लिए निर्यात कीमत, और भारत के लिए निर्यात कीमत के बारे में दावा किए गए समायोजनों के बारे में दोनों ओवीएलपी, ओवीएलएलसी, ट्रिकॉन तथा आईसीसी के द्वारा दायर किए गए आंकड़ों की सारणीबद्ध जांच की गई है।

प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य के बारे में निम्नानुसार विचार किया:-

सामान्य मूल्य:

पी. ओ. आई. के दौरान ओवीएलपी ने भारत के लिए केवल एक ग्रेड अर्थात ऑक्सी विनिल्स 225 की बिक्री की थी। ओवीएलपी ने यह निवेदन किया कि यह ग्रेड उन अन्य ग्रेडों के साथ तुलनीय नही है जो विचाराधीन उत्पादके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ओवीएलपी ने केवल 225 ग्रेड से संबंधित घरेलू बिक्रियों और लागत के बारे में सूचना दी है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह ग्रेड, चूंकि घरेलू बाजार में बिक्रियों का महत्वपूर्ण भाग बनता है और भारत के लिए निर्यातित ग्रेडों के अलग-अलग आधार पर तुलना करनी होगी, इसलिए पाटन मार्जिन का मूल्यांकन करने के लिए उत्पादक/निर्यातक द्वारा दायर किए गए प्रत्युत्तर पर विचार किया गया है। प्राधिकारी ने *** डॉलर/ मी. टन के रूप में उत्पादन की कारखानागत लागत का परिकलन किया है। घरेलू बिक्रियों पर की गई ओ. सी. टी. जांच यह दर्शाती है कि ***% लेनदेन लाभ योग्य है और इसलिए प्राधिकारी ने समग्र घरेलू विक्रय मूल्य के बारे में तदनुसार हवाला दिया है।

असंबद्ध ग्राहकों के लिए उत्पाद की (सीधे तौर पर) ओवीएलपी की बिक्रियां *** मी. टन है। कारखानागत लागत प्राप्त करने के लिए अंतर्देशीय माल भाड़ा, भण्डारण और क्रेडिट लागत संबंधी कारखाने के बाद के व्यय क्रमश: *** अमरीकी डॉलर/ मी. टन, *** अमरीकी डॉलर/ मी.टन और *** अमरीकी डॉलर/ मी.टन करने का प्रस्ताव है। कारखानागत कीमत अर्थात सामान्य मूल्य *** अम. डॉलर/ मी. टन आता है।

निर्यात मुल्य:

पी. ओ. आई. के दौरान ओवीएलपी और ओवीएलएलसी ने दो असंबद्ध व्यापारियों नामत: आईसीसी और ट्रिकॉन के माध्यम से भारत के लिए विचाराधीन उत्पाद की बिकी की थी। पी. ओ. आई. के बाद की अवधि में एक अन्य असंबद्ध व्यापारी अर्थात ऑक्सीडे केमिकल्स इंक, यू. एस. ए. (''ऑक्सीडे यू. एस. ए.'') के माध्यम से बिक्रियां की गई थीं, जिसने अपने संबद्ध आयातकर्ता नामत: ऑक्सीडे केमिकल्स और पोलीमर्स इंडिया प्रा०लि० (ऑक्सीडे इंडिया) को विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की थी। सभी छ: कंपनियों ने अपने-अपने प्रासंगिक प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रस्तुत किए थे तथा भारत और अन्य देशों के लिए पी. ओ. आई. के बाद बिक्री संबंधी आंकड़े भी प्रस्तुत किए।

44. अवशिष्ट श्रेणी

उच्चतम सामान्य मूल्य और कम से कम कारखानागत निर्यात कीमत का हवाला दिया है।

मै० सिन्टेक, जिसने निवेदन केवल प्रस्तुत किया है और पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन का आकलन तैयार करने के लिए निर्यातक प्रश्नावली प्रत्यृत्तर के अनुसार कोई आंकड़े नहीं दिए हैं. उन्हें अवशिष्ट श्रेणी में माना जाता है।

च.3.3 थाईलैंड

थाईलैंड कोऑपरेटिव उत्पादकों/निर्यातकों तथा अवशिष्ट कोऑपरेटिव उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण:-

45. थाई प्लॉस्टिक और केमिकल्स पी. एल. सी. (उत्पादक), एस. सी. जी. प्लॉस्टिक कंपनी लि० (संबद्ध निर्यातक), एस. सी. जी. परफॉरमेंस केमिकल कंपनी लि० (संबद्ध निर्यातक):-

मै॰ थाई प्लॉस्टिक और केमिकल्स पी. एल. सी. (टीपीसी) उत्पादकों ने अपनी दो संबद्घ विपणन कंपनियों अर्थात मै॰ एस. सी. जी. प्लॉस्टिक्स कंपनी लि॰ और मै॰ एस. सी. जी. परफॉरमेंस केमिकल कंपनी लि॰ के माध्यम से घरेलू बाजार में तथा भारत को एवं भारत के अलावा अन्य देशों को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। घरेलू बिक्रियों और भारत के लिए निर्यातों के चैनल (माध्यम) और ग्रेड वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

टी. पी. सी. ने पी. ओ. आई. में एस. सी. जी. प्लॉस्टिक्स के लिए *** मी. टन बेची, जिसने आगे भारत के लिए *** मी. टन का निर्यात किया तथा अपने घरेलू बाजार में *** मी. टन की बिक्री की तथा भारत के अलावा अन्य देशों के लिए *** मी. टन का निर्यात किया।

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मै० एस. सी. जी. प्लॉस्टिक्स कंपनी लि० और मै० एस. सी. जी. परफारमेंस केमिकल कंपनी लि०, चूंकि थाई प्लास्टिक और केमिकल्स पी. एल. सी. से संबद्ध है, इसलिए "सामान्य मूल्य" का परिकलन दोनों कंपनियों की संयुक्त घरेलू बिक्रयों के आधार पर किया जाता है। एस. सी. जी. परफारमेंस केमिकल कंपनी लि० ने घरेलू बाजार में एक संबद्ध कंपनी के लिए ही बिक्री की है और इसलिए असंबद्ध कंपनियों के लिए उसी ग्रेड की (भारत को निर्यातित जैसे) एस. सी. जी. प्लॉस्टिक कंपनी लि० की घरेलू बिक्रियों का, जो *** मी. टन है, सामान्य मूल्य का परिकलन करने के लिए हवाला दिया गया है।

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मै० एस. सी. जी. प्लॉस्टिक्स ने अंतर्देशीय माल भाड़े, क्रेडिट लागत, बैंक प्रभारों, सीधे विपणन, तकनीकी सहायता और आर. आई. एल. के लिए समायोजनों हेतु दावा किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादक/निर्यातक ने निवेदन किया कि तकनीकी सहायता संबंधी व्यय और आर. आई. एल. प्रभार (घरेलू बिक्री प्रयास पर प्रशिक्षण हेतु) घरेलू बिक्रियों के लिए ही किए जाते हैं, जो स्थल पर जांच के दौरान औचित्यपूर्ण नहीं हो सकते थे। बाद में उत्पादक/निर्यातक ने, यद्यपि कुछ आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, परन्तु यह सुनिश्चित नहीं किया गया है कि ये व्यय केवल घरेलू बिक्रियों के लिए ही किए जाते हैं। घरेलू तथा निर्यात बिक्रियों दोनों के लिए एस. सी. जी. प्लॉस्टिस के लिए एस. जी. ए. व्यय और लाभ *** % और *** % की दर पर तथा एस. सी. जी. निष्पादन के लिए *** % और ***% की दर पर माने जाते हैं। इसलिए स्वेदशी माल भाड़े (*** भाट /मी. टन), क्रेडिट लागत (*** भाट /मी. टन), बैंक प्रभार (*** भाट /मी. टन), प्रत्यक्ष विपणन/एस. जी. ए. (*** भाट /मी. टन), लाभ (*** भाट /मी.

टन) प्रत्यक्ष विषणन/एस जी ए (*** भाट/मी. टन) लाभ (*** भाट/मी. टन) पर समायोजन (*** भाट /मी. टन) में किए गए।

घरेलू बिक्रियों पर उपर्युक्त समायोजनों पर विचार करने के बाद टी. पी. सी. स्तर पर कारखानागत घरेलू विक्रय मूल्य की *** भाट /मी. टन के रूप में मानी गई टी. पी. सी. उत्पादन की कारखानागत लागत से तुलना की जाती है। घरेलू बाजार में असंबद्ध कंपनियों के लिए निर्यातित ग्रेडों की घरेलू बिक्रियों (कारखानागत स्तर पर) ओ. सी. टी. परीक्षण यह दर्शाते हैं कि सभी घरेलू बिक्रियां लाभ योग्य हैं। अत: सामान्य मूल्य का ओ. सी. टी. परीक्षण में लिए गए सभी लेनदेनों की कारखानागत घरेलू विक्रय मूल्य के रूप में परिकलन किया जाता है, जो अमरीकी डॉलर/मी. टन आता है।

कारखानागत निर्यात विक्रय मूल्य:

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मै० एस. सी. जी. प्लॉस्टिक्स और मै० एस. सी. जी. परफॉरमेंस दोनों ने *** मी. टन एस. सी. जी. प्लॉस्टिक्स सहित *** मी. टन का निर्यात किया है। *** भाट/मी. टन के कुल मूल्य पर 258, 261, 286 एसपी 660, एसजी 660, एसएफ 580, एसजी 701, एसजी 500, एसजी 585, एसजी 610 ग्रेडों का निर्यात किया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि *** भाट/मी. टन तक एफ. ई. समायोजन के रूप में दावा किए गए समायोजन स्थल पर जांच के दौरान औचित्यपूर्ण नहीं थे और बाद में विपणन प्रभाग एवं अन्य के आंतरिक ज्ञापन ही उपलब्ध कराए गए हैं। किसी प्रकार का कोई सहायक निर्णायक औचित्य न होने से प्राधिकारी ने इस समायोजन को स्वीकार नहीं किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्रत्यक्ष विपणन खर्चों के बारे में कोई ब्यौरा दिए बिना ही घरेलू और निर्यात विक्रियों के लिए इनके अलग-अलग दावे किए गए हैं इसलिए प्राधिकारी ने समायोजन के रूप में दोनों विपणन कंपनियों के लिए घरेलू और निर्यात दोनों बिक्रियों पर औसत एस. जी. ए. व्यय (*** भाट/मी. टन) लागू किया है। प्राधिकारी ने समुद्री माल भाड़ा (*** भाट/मी. टन), समुद्री बीमा (*** भाट/मी. टन), अंतर्देशीय माल भाड़ा (*** भाट/मी. टन), पत्तन (*** भाट/मी. टन), केडिट लागत (*** भाट/मी. टन), बैंक प्रभार (*** भाट/मी. टन), निर्यात छूट (*** भाट/मी. टन), कमीशन (*** भाट/मी. टन), पर समायोजनों के बारे में विचार किया है।

भारित औसत कारखानागत निर्यात कीमत, और पहुंच मूल्य क्रमश: *** भाट/मी. टन (*** डॉलर/मी. टन) और *** डॉलर/मी. टन आते हैं।

46. <u>सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण-</u>

मै० विनीथाई पब्लिक कंपनी लि० थाईलैंड

मै॰ विनीथाई पब्लिक कंपनी लि॰ थाईलैंड ने पी. ओ. आई. के दौरान तीनों ग्रेडों अर्थात 258, 261 और 266 की घरेलू बाजार में बिक्री की है और भारत के लिए निर्यात भी किया है। इन ग्रेडों की घरेलू बिक्रियों की कुल मात्रा *** मी. टन यह मात्रा पर्याप्त मात्रा परीक्षण को पूरा करती है और इसके अलावा *** भाट/िक. ग्रा. (*** डॉलर/मी. टन) के रूप में संबद्ध वस्तुओं की कारखानागत लागत को स्वीकार करते हुए ओ. सी. टी. परीक्षण भी किए गए थे। ***% से ज्यादा बिक्रियों को लाभ योग्य नोट किया जाता है और इस प्रकार उपरोक्त तीनों ग्रेडों की संपूर्ण घरेलू बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य का हवाला दिया जाता है। छूट, अंतर्देशीय माल भाड़े, क्रेडिट लागत, पत्तन प्रभार के लिए *** डॉलर/मी. टन की कुल घरेलू कीमत पर क्रमश: ***, *** और *** डॉलर/मी. टन तक समायोजनों (डॉलर/ मी. टन में) विचार किया जाता है। तीनों ग्रेडों के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य *** डॉलर/मी. टन के रूप में माना है।

कारखानागत निर्यात कीमत:

उत्पादक/निर्यातक ने उपरोक्त तीनों को शामिल करते हुए *** मी. टन का निर्यात किया है, जिसमें *** मी. टन (सीधे), *** मी. टन (आईटीओसीएचयू के माध्यम से), *** मी. टन (मारूबेनी के माध्यम से) तथा *** मी. टन (डीएमसीसी) के माध्यम से निर्यात शामिल है। मै० इटोचू और मै० डीएमसीसी ने प्रत्युत्तर प्रस्तुत भी कर दिए हैं। कारखानागत निर्यात कीमत का परिकलन करने के लिए प्राधिकारी ने *** डॉलर/मी. टन के भारित औसत सी. आई. एफ. पर क्रमशः ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, और *** तक समुद्री माल भाड़े, अंतर्देशीय माल भाड़े, पत्तन, क्रेडिट लागत, पत्तन प्रभार, बैंक प्रभार और कमीशन पर समायोजनों (डॉलर/मी. टन में) विचार किया है, जिससे *** डॉलर/मी. टन की कारखानागत कीमत होती है। प्राधिकारी ने भारत के लिए मै० इटोचू द्वारा किए गए निर्यातों का सत्यापन किया है और वे यह नोट करते हैं कि उनके द्वारा की गई निर्यात बिक्रियां लाभ योग्य हैं तथा प्रश्नावली

प्रत्युत्तर के माध्यम से प्रस्तुत की गई डीएमसीसी की निर्यात बिक्रियों का उत्पादक के द्वारा सूचित निर्यात मात्रा के साथ मिलान किया गया था। इस संबंध में प्रतिवादी उत्पादक के लिए भारित औसत पहुंच मूल्य का मूल्यांकन करने हेतु डी. जी.- सिस्टम के डाटा से मेरूबेनी (व्यापारी) की निर्यात कीमत का संदर्भ दिया गया है। भारत के लिए उत्पादक के 4 निर्यात चैनलों के लिए भारित औसत एल. वी. निम्नानुसार हैं:-

चैनल	सीआईएफ (डॉलर / मी.टन)	एलवी (डॉलर/मी.टन)
सीधे	***	***
इटोचू	***	***
डीएमसीसी	***	***
मेरूबेनी	***	***

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इटोचू ने टी. पी. सी. और विनिथाई दोनों की वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए समग्र पहुंच मूल्य के मूल्यांकन हेतु उपर्युक्त रूप से दोनों उत्पादकों के लिए इटोचू की भारत के लिए सी. आई. एफ. कीमत के बारे में विचार किया है। विनिथाई की वस्तुओं की लाभप्रदता ***% है, जबिक टी. पी. सी. के क्रमश: *** डॉलर/मी. टन के सी. आई. एफ. पर ***% है। प्राधिकारी ने पी. ओ. आई. के दौरान विनिथाई द्वारा निर्यातित वस्तुओं के पहुंच मूल्य का निर्धारण करने हेतु औचित्य रूप से *** डॉलर/मी. टन के डीएमसीसी की सी. आई. एफ. कीमत का हवाला दिया है।

47. **अवशिष्ट श्रेणी**

दो सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों में से सबसे अधिक पाटन मार्जिन का उल्लेख है।

च.3.4 पाटन मार्जिन

48. उपर्युक्त के आधार पर पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:-

उत्पादक / निर्यातक	एनवी	ईएक्स-ईपी	डीएम	डीएम %	डीएम % रेंज
चीन (सहयोगी)	(डॉलर / मी.	(डॉलर/मी. टन)	(डॉलर/मी. टन)		
	टन)				
यिबिन हाईफेंग हेरुई कंपनी लि०	***	***	***	***	15-20
("हाईफेंग हेरुई ") और यिबिन					
तियानयुआन ग्रुप कंपनी लि० ("यिबिन					
तियानयुआन")					
सी. एन. एस. जी. जिलान्ताई साल्ट	***	***	***	***	25-30
केमिकल (ग्रुप) कंपनी लि० और सी.					
एन. एस. जी. जिलान्ताई साल्ट क्लोरी					
अल्काली केमिकल कंपनी लि०					
चिपिंग जिनफॉ पी. वी. सी. कंपनी	***	***	***	***	30-35
लि० और शानडांग जिनफॉ इंपोर्ट और					
एक्सपोर्ट कंपनी लि०					
तियाननेंग केमिकल कंपनी लि० और	***	***	***	***	20-25
जिनजियांग टाइनी (ग्रुप) कंपनी लि०					

तियानजिन एल. जी. बोहाई केमिकल कंपनी लि०	***	***	***	***	5-10
तियानजिन डागू केमिकल कंपनी लि० और बोहाई केमिकल (एच. के.) लि०	***	***	***	***	10-15
जिनजियांग शेंगजिआंग क्लोर - अल्काली कंपनी लि० और जिनजियांग झोंगताई केमिकल कंपनी लि०	***	***	***	***	35-40
असहयोगी अवशिष्ट (उच्चतम)	***	***	***	***	35-40
यूएसए (कोऑपरेटिव)	***	***	***	***	
ऑक्सी विनिल्स एलपी और ऑक्सी विनिल्स एक्सपोर्ट सेल्स एलएलसी	***	***	***	***	5-10
वेस्टलेक विनिल्स कंपनी एलपी, ऑक्जियल एलएलसी और वेस्टलेक विनिल्स इंक.	***	***	***	***	10-15
नॉन-कोऑपरेटिव	***	***	***	***	10-15
/ अवशिष्ट					
थाईलैंड (उच्चतम)	***	***	***	***	
विनीथाई पब्लिक कंपनी लि०	***	***	***	***	5-10
थाई प्लॉस्टिक और केमिकल्स एससीजी परफॉरमेंस केमिकल कंपनी लि० और एससीजी प्लॉस्टिक कंपनी लि०	***	***	***	***	5-10
असहयोगी अवशिष्ट			***		5-10

49. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन, नियमावली में निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण:

50. क्षति पर विचार, समान वस्तु और कारणात्मक संबंध निम्नानुसार हैं:-

छ.1 घरेलू उद्योग के विचार

- i. याचिकाकर्ताओं ने आयातों के परिणामस्वरूप निष्पादन में ह्रास के बारे में दावा नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं ने जारी क्षति के बारे में भी दावा नहीं किया है। लागू ए. डी. डी. के परिणामस्वरूप विभिन्न आर्थिक मानदंडों के निष्पादन में सुधार हुआ है। वर्तमान ए. डी. डी. के समाप्त होने की स्थिति ए. डी. डी. का विस्तार करने के लिए अनुरोध क्षति होने की संभावना पर आधारित होता है।
- ii. क्षति अवधि के दौरान मांग में बढ़ोतरी हुई है। संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में वर्ष 2015-16 में हुई गिरावट को छोड़कर क्षति अवधि के दौरान संपूर्णत: बढ़ोतरी हुई । पी. ओ. आई. में कुछ बढ़ोतरी होने सहित संबद्ध आयातों के शेयर में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आयी।

- iii. सभी संबद्ध देशों से कीमतों में कटौती ए. डी. डी. के बिना काफी हद तक सकारात्मक है। लागू किए गए ए. डी. डी. से विचाराधीन उत्पाद का किसी प्रकार से मूल्य ह्रास अथवा न्यूनीकरण होने से रोका गया है। कीमत में पर्याप्त कटौती पर विचार करते हुए यह स्पष्ट है कि ए. डी. डी. के समाप्त हो जाने से बाजार में कीमत ह्रास/न्यूनीकरण हो जाएगा। कीमतों में हल्का सा अंतर भी बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे एक उत्पादक अंतर होने की वजह से किसी आर्डर को गंवा सकता है।
- iv. जब ए. डी. डी. लागू होता है, तब घरेलू उद्योग के द्वारा लाभों का वर्तमान स्तर प्राप्त किया है । यदि वर्तमान ए. डी. डी. समाप्त हो जाता है तो लाभप्रदता धीरे-धीरे कम होती चली जाएगी जैसा कि चीन से हुए आयातों के मामले में कीमत में हुई कटौती के स्तर से स्पष्ट है।
- v. प्राधिकारी से आर. ओ. आई. पर विचार करने का अनुरोध है जो विगत में अर्जित किया गया था। यदि विगत 15 वर्षों के बारे में विचार किया जाता है तो आर. ओ. आई. यथोचित स्तरों से बहुत कम हो जाता है, चाहे प्राधिकारी (पिछले 2 वर्षों को छोड़कर) निवेशों के निवल वर्तमान मूल्य पर आर. ओ. आई. का निर्धारण करता हो। विचाराधीन उत्पाद के लिए किए गए निवेश बहुत पुराने होते हैं। डी. सी. एम. श्रीराम और डी. सी. डब्ल्यू. के मामले में मूल संयंत्रों का काफी हद तक मूल्य कम हो गया है। आर. ओ. आई. का स्तर अधिक होने का एकमात्र कारण निवेशों का कम स्तर होना है।
- vi. पर्याप्त और सकारात्मक पाटन मार्जिन का निहितार्थ यह है कि विदेशी उत्पादकों के द्वारा अर्जित लाभ अधिक है। जहां तक अमरीका का संबंध है, शेल गैस की उपलब्धता के दृष्टिगत अमरीका में उत्पादन की लागत वैश्विक उत्पादकों की तुलना वस्तुत: कम होती है। कम कीमतों पर बेचने के बावजूद वे काफी लाभ अर्जित करते हैं।
- vii. पहले दो अवसरों पर प्राधिकारी ने यह पाया कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई। इनका मूल जांच के दौरान वस्तुगत क्षति पायी गई तथा पूर्व निर्णायक समीक्षा में क्षति का जारी रहना पाया। वर्तमान निर्णायक समीक्षा के दौरान ही घरेल उद्योग को क्षति में कमी हुई और विगत 2 वर्षों में कुछ लाभ ले सका है।
- viii. थाईलैंड से आयात कीमत घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से कम है। थाईलैंड के मामले में कीमत में कटौती करना सकारात्मक है। थाईलैंड से आयात 7.5 प्रतिशत के एम. एफ. एन. की तुलना में 5 प्रतिशत के कम बी. सी. डी. के अध्यधीन भी हैं और इस तरह, थाईलैंड से कम आयात कीमत का प्रभाव उतना ही अधिक है।
- ix. पी. ओ. आई. के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए थे, क्योंकि प्राधिकारी ने ऐसी सूचना नहीं मांगी है। तथापि, यह लिखित निवेदनों में उपलब्ध कराई गई है।
- लागू किए गए ए. डी. डी. की वजह से क्षिति अविध के दौरान कीमत ह्रास/न्यूनीकरण नहीं था। जारी क्षिति के लिए भी दावा नहीं किया गया है। क्षिति अविध के दौरान मूल्य ह्रास अथवा न्यूनीकरण न होने का अर्थ ए. डी. डी. समाप्त होने की स्थिति में संभावित मुल्य ह्रास/न्यूनीकरण का न होना नहीं होता है।
- xi. मूल्य ह्रास और न्यूनीकरण प्रभावों के संबंध में अनुबंध-II के पैरा (ii) और पैरा (vii) के तहत अपेक्षा अलग-अलग होती है। अनुबंध II के पैरा (ii) में विगत को ध्यान में रखते हुए अर्थात क्षति अविध के दौरान पी. ओ. आई. में मूल्य ह्रास/न्यूनीकरण प्रभाव पर विचार करने की प्राधिकारी अपेक्षा करते हैं, क्षति जांच की संभावना में, प्राधिकारी के द्वारा पी. ओ. आई. में कीमतों के बारे में विचार करना तथा यह निर्धारण करना होता है कि क्या आयातों से कीमतों में कमी अथवा न्यूनीकरण प्रभाव होने की संभावना होती है।
- xii. जब याचिकाकर्ताओं ने स्वयं जारी क्षति के बारे में कोई दावा नहीं किया हो, तब जारी क्षति न होने के बारे में किसी भी निवेदन की कोई प्रासंगिकता नहीं होती है। ए. डी. डी. का विस्तार करने का अनुरोध क्षति होने की पुनरावृत्ति के आधारों पर ही आधारित होता है।
- xiii. एन. आई. पी. और एन. एस. आर. की तुलना करने संबंधी स्थिति सुनिश्चित है। एन. आई. पी. का केवल उस स्थिति में ही निर्धारण करना होता है जब प्राधिकारी शुल्क का निर्धारण कर रहे हों। वर्तमान जांच कोई मूल जांच नहीं होती है और इसलिए शुल्क की मात्रा का निर्धारण करना अपेक्षित नहीं होता है। वर्तमान मामले में एन. आई. पी. और एन. एस. आर. की तुलना करना महत्व नहीं रखता है।

xiv. लगाए गए शुल्क के परिणामस्वरूप ही घरेलू उद्योग के द्वारा पर्याप्त क्षमताएं बनायी जा रही हैं। यह स्पष्ट तौर पर वियचराधीन उत्पाद के विगत दो वर्षों के निष्पादन के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है यदि वर्तमान ए. डी. डी. को पूरी तरह से वापस ले लिया जाता है, तो उचित निष्पादन के बारे में केवल दो वर्षों में घरेलू उद्योग को हुआ विश्वास पूरी तरह से चूर-चूर हो जाएगा।

छ.2 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के मत</u>

- i. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की बढ़ोतरी का कारण अनुप्रवाह उद्योग की मांग है।
- ii. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और विक्रय मूल्य के बीच में परस्पर संबंध नहीं है। संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य अपेक्षाकृत अन्य संबद्ध देशों के मूल्य से अधिक होता है।
- iii. वर्तमान जांच में कीमत कटौती की कोई प्रासंगिकता नहीं होती है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने कीमत कटौती के बावजूद अपने लाभों में सुधार किया है।
- iv. क्षमता, उत्पादन, उपयोग और बिक्रियों में बढ़ोतरी हुई है।
- v. व्यापार नोटिस 10/2018 के अनुसार याचिकाकर्ता विक्रय मूल्य संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं करा सके हैं।
- vi. लाभप्रदता में भी बढ़ोतरी हुई है। चूंकि आर. आई. एल. उच्चतम मार्जिन पर कार्य कर रहा है, इसलिए आर. आई. एल. को भी जांच में शामिल करना चाहिए। हो रही क्षति के अन्य कारक हैं, जैसाकि वार्षिक रिपोर्टों से स्पष्ट है। यहां तक आर. ओ. सी. ई. उससे भी काफी अधिक है जितने के लिए प्राधिकारी के द्वारा स्वाभाविक रूप से अनुमति दी जाती है।
- vii. घरेलू उद्योग के पास रोजगार में बढ़ोतरी हुई है और उत्पादकता ने भी बढ़ोतरी को दर्शाया है।
- viii. एन. आई. पी. और एन. एस. आर. अधिक है। सभी आर्थिक मापदण्ड बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। सामान सूचियों में बढ़ोतरी हुई है और यदि अन्य आर्थिक मापदण्ड सुधार दर्शाते हैं तो सामान सूची में बढ़ोतरी होने का कोई अर्थ नहीं है। वर्तमान मामले में कीमत में कटौती प्रासांगिक नहीं है, क्योंकि सकारात्मक कीमत कटौती के बावजूद घरेलू उद्योग के निष्पादन में काफी सुधार हुआ है।
- ix. वर्तमान मामले में कीमत में कटौती प्रासांगिक नहीं है, क्योंकि सकारातमक कीमत कटौती के बावजूद घरेलू उद्योग के निष्पादन में काफी सुधार हुआ है। थाईलैंड से ए. डी. डी. सहित पहुंच मूल्य विक्रय मूल्य की उच्चतम रेंज से अधिक है।
- x. याचिकाकर्ता ने पी. ओ. आई. के बाद कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए और क्षति संबंधी पी. ओ. आई. के बाद के सत्यापन योग्य प्रमाण नहीं दिए हैं।
- xi. घरेलू उद्योग के द्वारा कोई कीमत ह्रास और न्यूनीकरण का दावा नहीं किया है।
- xii. याचिकाकर्ताओं ने हुई जारी क्षति के बारे में दावा किया है। गैर संबद्ध देशों से आयातों से देश की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हो रही है। अत: घरेलू उत्पादों की प्रतिस्पर्धा गैर संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के साथ है और न कि संबद्ध देशों से आयात की जा रही वस्तुओं के साथ।
- xiii. जबिक आयात कीमतों में कमी हुई है, परन्तु याचिकाकर्ता अपनी बिक्री लागतों में कमी भी होने के बावजूद अपनी कीमतों में कमी करने के लिए बाध्य नहीं किए गए हैं। याचिकाकर्ता अपनी कीमतों को बढ़ा सके थे। यह इस बात को दर्शाता है कि आयात कीमतें याचिकाकर्ताओं की कीमतों को प्रभावित नहीं कर रही थीं तथा पी. ओ. आई. के दौरान औसत आर. ओ. सी. ई. सहित लाभ में बढ़ोतरी 50 से 60 प्रतिशत थी। संबद्ध देशों की आयात कीमतों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव नहीं हुआ है।
- xiv. याचिकाकर्ताओं ने उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी को दर्शाया है और उनका क्षमता उपयोग भी काफी रहा है। याचिकाकर्ताओं की बिक्रियों और बिक्रियों की वसूली में भी बढ़ोतरी हुई है। वस्तुत: अन्य घरेलू उत्पादकों का उत्पादन भी बढ़ा है।

- xv. सामान सूचियों में बढ़ोतरी हुई है, परन्तु घरेलू उद्योग को प्रभावित करने के वे प्रमुख कारक नहीं हैं। बिक्रियों में कोई बढ़ोतरी न होने के साथ यदि समान सूचियों में बढ़ोत्तरी न हो, तो उनका महत्व होगा। रोजगार और उत्पादकता के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं को भी कोई क्षति नहीं हुई है।
- xvi. संबद्ध देशों से आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है और घरेलू उद्योग का सभी मानदंडों में अच्छा विकास हुआ है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के लाभ, नकद प्रवाह और आर. ओ. आई. में भी काफी बढ़ोतरी हुई है और यह पर्याप्त लाभ अर्जित कर रहा है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच:

- 51. आगे चलकर प्राधिकारी के द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए विभिन्न प्रासंगिक निवेदनों के बारे में बताता है।
- 52. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षित के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षित जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सिहत सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षित का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थित को प्रभावित करने वाले कारकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विचार किया गया है।
- 53. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.1 और नियमावली के अनुबंध-II में इन दोनों की तथ्यपरक जांच की व्यवस्था है, (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती।
- 54. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9(क) (5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क, जब तक पहले रद्द न किया हो, लागू करने की तारीख से पांच वर्षों की अविध समाप्त हो जाने पर समाप्त हो जाएगा (बशर्ते, यिद केंद्र सरकार का, पुनरीक्षा के दौरान यह मत हो, कि ऐसे शुल्क को समाप्त कर दिया जाने से पाटन और क्षिति की जारी रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना हो सकती है और ऐसे लागू करने की अविध को पांच वर्ष की और अविध के लिए समय-समय पर बढ़ा सकती है तथा आगे बढ़ायी गई ऐसी अविध ऐसे विस्तार करने के आदेश की तारीख से शुरू होगी।
- 55. भारत में घरेलू उद्योगों पर आयात के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के अनुसार ॥ (IV) के अनुसार उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे सूचकांकों के बारे में विचार किया है।
- 56. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देशों से आयातों के कारण पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं को अपनाने से पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच करने का प्रस्ताव करते है।

छ.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

ा. <u>मांग/प्रत्यक्ष खपत का आकलन</u>

57. प्राधिकारी भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ के रूप में भारत उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत या पर निम्नानुसार विचार किए जाने का प्रस्ताव करते हैं:-

क्र. सं.	विवरण (मी. टन में)	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई	पश्च पीओआई-ए
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	3,84,878	3,99,740	4,14,871	4,24,166	3,96,004
2	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	7,76,038	8,31,580	7,88,357	7,87,562	7,90,728
3	संबद्ध देशों से आयात	3,40,890	2,01,402	3,29,366	3,51,297	2,45,054
4	अन्य देशों से आयात	8,82,293	12,12,964	12,60,085	12,34,889	11,02,677
5	कुल मांग	23,84,098	26,45,686	27,92,680	27,97,914	25,34,463

58. मांग में लगातार वृद्धि हो रही है और यह लगभग 28 मिलियन टन के स्तर पर स्थिर है।

ii. <u>पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव</u>

आयात मात्रा और बाजार हिस्सा

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई	पश्च पीओआई-ए
1	संबद्ध देश (मी. टन में)					
2	चीन	2,90,122	1,69,114	2,47,949	2,07,289	1,22,724
3	थाईलैंड	35,687	18,100	33,505	1,17,154	50,126
4	यू. एस. ए.	15,082	14,188	47,912	26,853	72,204
5	उप जोड़	3,40,890	2,01,402	3,29,366	3,51,297	2,45,054
6	अन्य देश	8,82,293	12,12,964	12,60,085	12,34,889	11,02,677
7	जोड़	12,23,183	14,14,366	15,89,452	15,86,186	13,47,731
8	संबद्घ देश (% में)					
9	चीन	24 %	12%	16%	13%	9%
10	थाईलैंड	3%	1%	2%	7%	4%
11	यू. एस. ए.	1%	1%	3%	2%	5%
12	उप जोड़	28%	14%	21%	22%	18%
13	अन्य देश (% में)	72%	86%	79%	78%	82%
14	जोड़	100%	100%	100%	100%	100%
15	के संबंध में संबंद्ध देशों से आयात (% में)					
क	भारतीय उत्पादन	26.89%	14.68%	23.59%	25.17%	17.03%
ख	भारतीय मांग	14.30%	7.61%	11.79%	12.56%	9.67%

59. कुल रूप में संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है जबिक सापेक्ष रूप में समग्र आयातों से तुलना में उत्पादन और मांग मामूली रूप से निम्न रहे हैं। समग्र आयातों में गैर संबद्ध देशों के हिस्से में वृद्धि हुई है।

छ.3.2 घरेलू उद्योग आयात पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

क. कीमत में कटौती

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई	पश्च पीओआई-ए
1	चीन						
क	पहुंच कीमत	रू/कि.ग्रा.	65.59	56.17	57.12	61.09	66.54
ख	निवल बिक्री कीमत	रू/कि.ग्रा.	***	***	***	***	***
ग	कीमत में कटौती	रू/कि.ग्रा.	***	***	***	***	***
घ	कीमत में कटौती	%	0-10%	10-20%	15-25%	10-20%	5-15%
2	थाईलैंड						
क	पहुंच कीमत	रू/कि.ग्रा.	69.52	58.36	63.05	63.49	69.61
ख	निवल बिक्री कीमत	रू/कि.ग्रा.	***	***	***	***	***
ग	कीमत में कटौती	रू/कि.ग्रा.	***	***	***	***	***
घ	कीमत में कटौती	%	(0-10)%	0-10%	5-15%	5-15%	0-10%
3	यू. एस. ए.						
क	पहुंच कीमत	रू/कि.ग्रा.	69.49	55.92	62.33	63.19	68.57
ख	निवल बिक्री कीमत	रू/कि.ग्रा.	***	***	***	***	***
ग	कीमत में कटौती	रू/कि.ग्रा.	***	***	***	***	***
घ	कीमत में कटौती	%	(0-10)%	10-20%	10-20%	5-15%	5-15%
4	समग्र रूप में संबद्ध देश						
क	पहुंच कीमत	रू/कि ग्रा	66.17	56.35	58.48	62.05	67.77
ख	निवल बिक्री कीमत	रू/कि.ग्रा.	***	***	***	***	***
ग	कीमत में कटौती	रू/कि.ग्रा.	***	***	***	***	***
घ	कीमत में कटौती	%	0-10%	5-15%	15-25%	5-15%	5-15%

60. संबद्ध देश से आयातों के द्वारा कीमत में कटौती जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि दोनों में पाटनरोधी शुल्क के बिना सकारात्मक है। गैर संबद्ध देशों की पहुंच कीमत संबद्ध देशों की तुलना में अधिक है।

	विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई
1	एन. एस. आर.	रू/कि.ग्रा.	***	***	***	***
2	संबद्ध देश, पहुंच कीमतें					
क	चीन	रू/कि.ग्रा.	65.59	56.17	57.12	61.09
ख	थाईलैंड	रू/कि.ग्रा.	69.52	58.36	63.05	63.49
ग	यू. एस. ए.	रू/कि.ग्रा.	69.49	55.92	62.33	63.19
3	अन्य देश, पहुंच कीमतें					
क	ताईवान	रू/कि.ग्रा.	69.00	62.09	65.75	67.42

ख	जापान	रू/कि.ग्रा.	66.14	56.61	61.09	65.64
क	यूरोपियन संघ	रू/कि.ग्रा.	70.59	64.15	66.66	78.86
ख	मैक्सिको	रू/कि.ग्रा.	71.55	37.56	75.11	46.06
क	इंडोनेशिया	रू/कि.ग्रा.	69.39	-	59.10	-
ख	मलेशिया	रू/कि.ग्रा.	63.76	-	-	-
क	कोरिया गणराज्य	रू/कि.ग्रा.	68.10	58.48	63.02	68.48

ख. कीमत ह्वास/ न्यूनीकरण

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पी ओ आई	पोस्ट पीओआई
1	बिक्रियों की लागत	रू/कि.ग्रा.	***	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	92	89	99
3	बिक्री कीमत	रू/कि.ग्रा.	***	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	101	101	108
5	पहुंच कीमत	रू/कि.ग्रा.	66.17	56.35	58.48	62.05	67.77
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	88	94	102

पी. ओ. आई. और आंशिक पश्च पी. ओ. आई. में बिक्री कीमतें लगातार बिक्रियों की लागत से अधिक रही हैं।

छ.3.3 घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

- 61. ए. डी. नियमावली के अनुबंध ॥ के अनुसार यह अनिवार्य है कि क्षित के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्यपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में ए. डी. नियमावली में आगे व्यवस्था की गई है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारक और संकेतकों का उद्देश्यपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा जिनमें बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेशों पर आय अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रभाव, माल सूची, रोजगार, वेतन वृद्धि पूंजीगत निवेशों के जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभाव और शामिल हैं।
- 62. तदनुसार, घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मापदंडों का यहां नीचे विश्लेषण किया गया है:-

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई	पश्च पीओआई
1	क्षमता	मी. टन	420,000	460,000	460,000	460,000	460,000
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	110	110	110
3	उत्पादन	मी. टन	383,738	403,147	425,679	420,567	416,120
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	111	110	108
5	क्षमता उपयोग	%	91.37%	87.64%	92.54%	91.43%	90.46%
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	101	100	99
7	घरेलू बिक्री मात्रा	मी. टन	384,878	399,740	414,871	424,166	396,004
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	108	110	103

63. घरेलू बिक्रियां, क्षमताएं और सी. यू. स्थायित्व और वृद्धि को दर्शाती है और घरेलू बिक्रियां, उत्पादन और सी. यू. पश्च पी. ओ. आई. अवधि में मामूली रूप से निम्न रहे हैं।

मांग में बाजार हिस्सा

64. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में नीचे दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	मांग में बाजार हिस्सा (% में)	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई	पश्च पीओआई
1	घरेलू उद्योग	16.14%	15.11%	14.86%	15.16%	15.62%
2	अन्य भारतीय उत्पादक	32.55%	31.43%	28.23%	28.15%	31.20%
3	संबद्ध देश	14.30%	7.61%	11.79%	12.56%	9.67%
4	अन्य देश	37.01%	45.85%	45.12%	44.14%	43.51%
5	जोड़	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

65. मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा पी. ओ. आई. और पश्च पी. ओ. आई. अवधि में कुल मिला कर स्थिर बना रहा है। भारतीय उद्योग का हिस्सा कुल रूप में पी. ओ. आई. संबद्ध देशों के मामूली रूप से निम्न स्तर के साथ निम्न रहा है।

लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकदी प्रवाह

66. लाभों, निवेश पर आय और नकदी प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई	पश्च पीओआई-ए
1	बिक्रियों की लागत	रू/कि.ग्रा.	***	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	92	89	99
3	बिक्री कीमत	रू/कि.ग्रा.	***	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	101	101	108
5	लाभ/(हानि)	रू/कि.ग्रा.	***	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	752	2,810	3,513	2,709
7	लाभ/(हानि)	लाख रू	***	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	781	3,029	3,872	2,787
9	पी. बी. आई. टी.	लाख रू	***	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	167	368	439	310
11	नकदी लाभ	लाख रू	***	***	***	***	***
12	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	338	1, 104	1,404	1,032
13	आर. ओ. सी. ई.	%	***	***	***	***	***
14	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	0-10%	5-15%	40-50%	50-60%	35-45%

67. क्षति अवधि के दौरान लाभप्रदता काफी हद तक स्थिर रही है और आर. ओ. सी. ई. उर्ध्वमुखी रहा है।

<u>माल सूचियां</u>

68. घरेलू उद्योग की माल सूचियां निम्नानुसार हैं:-

विवरण (मी. टन)	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई	पश्च पीओआई
अथ शेष	***	***	***	***	***
अंत शेष	***	***	***	***	***
औसत	5,970	4,770	9,022	9,216	9,591
प्रवृत्ति	100	80	151	154	161

पी. ओ. आई. और पश्च पी. ओ. आई. में माल सूचियों में वृद्धि हुई है, किंतु उत्पादन के प्रतिशत के रूप में यह उच्च नहीं है।

रोजगार और उत्पादकता

69. रोजगार, उत्पादकता और वेतनों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पीओआई	पश्च पीओआई-ए
1	दैनिक उत्पादकता	मी. टन/दिन	***	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	111	110	108
3	रोजगार	संख्या	***	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	109	108	108

70. उत्पादकता और रोजगार ने स्थिर प्रवृत्ति दर्शायी है।

पाटन की मात्रा

71. प्राधिकारी ने पी. ओ. आई. के दौरान सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का मूल्यांकन किया है, जैसाकि पूर्ववर्ती पैरा में कहा गया है।

सहयोगी और अवशिष्ट उत्पादकों/निर्यातकों दोनों के लिए संबद्ध देशों से पी. ओ. आई. के दौरान पाटन न्यूनतम सीमा से अधिक है।

पूंजीगत निवेश को जुटाने की क्षमता

72. इस समय प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्कों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग साथ ही अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा किए जा रहे या आयोजना किए जा रहे निवेश जोखिम में पड़ सकते हैं यदि वर्तमान शुल्कों को समाप्त करने की अनुमित दी जाती है।

क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

73. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्घ वस्तुओं की क्षति रहित कीमत, जैसाकि ए. डी. नियमावली के अनुबंध III की शर्तों में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है, की पी. ओ. आई और पश्च पी. ओ. आई. के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देश से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है और क्षति मार्जिन निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	विवरण	इकाई	पी ओ आई	पश्च पीओआई
क	चीन			
1	क्षति रहित कीमत	रू/कि. ग्रा.	***	***

2	पहुंच मूल्य	रू/कि. ग्रा.	61.09	66.54
3	क्षति मार्जिन	रू/कि. ग्रा.	***	***
4	क्षति मार्जिन	%	0-10%	0-10%
ख	थाईलैंड			
1	क्षति रहित कीमत	रू/कि. ग्रा.	***	***
2	पहुंच मूल्य	रू/कि. ग्रा.	63.49	69.61
3	क्षति मार्जिन	रू/कि. ग्रा.	***	***
4	क्षति मार्जिन	%	(0-10)%	(0-10)%
ग	यू. एस. ए.			
1	क्षति रहित कीमत	रू/कि. ग्रा.	***	***
2	पहुंच मूल्य	रू/कि. ग्रा.	63.19	68.57
3	क्षति मार्जिन	रू/कि. ग्रा.	***	***
4	क्षति मार्जिन	%	(0-10)%	(0-10)%

यह नोट किया जाता है कि पी. ओ. आई. और पश्च पी. ओ. आई. के लिए चीन के लिए क्षति मार्जिन समग्र आधार पर सकारात्मक है और थाईलैंड और यू. एस. ए. के लिए समग्र आधार पर ऋणात्मक है।

छ.3.4 सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए क्षति मार्जिन

74. सहयोगी उत्पाकदों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन को निम्नानुसार मूल्यांकित किया गया है:-

उत्पादक/निर्यातक (पीओआई)/एनआईपी = ***	एल. वी.	आई. एम.	आई. एम.%	आई.एम.
अम.डॉलर/मी. टन चीन (सहयोगी)	(डॉलर/मी. टन)	(डॉलर/मी. टन)	(डॉलर / मी. टन)	% रेंज
यिबिन हाईफेंग हेरुई कंपनी लि० ("हाईफेंग हेरुई") एंड यिबिन तियानयुआन ग्रुप कंपनी लि० ("यिबिन तियानयुआन")	***	***	***	(0 to 5)
सी. एन. एस. जी. जिलान्ताई साल्ट केमिकल (ग्रुप) कंपनी लि० एंड सी. एन. एस. जी. जिलान्ताई साल्ट क्लोरी अल्काली केमिकल कंपनी लि०	***	***	***	0-5
चिपिंग जिनफाँ पी. वी. सी. कंपनी लि० एंड शानडांग जिनफाँ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लि०	***	***	***	5-10
तियाननेंग केमिकल कंपनी लि० एंड जिनजियांग तियान्ये (ग्रुप) कंपनी लि०	***	***	***	0-5
तियानजिन एल. जी. बोहाई केमिकल कंपनी लि०	***	***	***	(0-5)
तियानजिन डागू केमिकल कंपनी लि० एंड बोहाई केमिकल (एच. के.) लि०	***	***	***	0-5
जिनजियांग शेंगजिआंग क्लोर - अल्काली कंपनी लि०	***	***	***	0-5

एंड जिनजियांग झोंगताई केमिकल कंपनी लि०				
असहयोगी / (उच्चतम)	***	***	***	5-10
अवशिष्ट				
यू. एस. ए.	***	***	***	
ऑक्सी विनिल्स एलपी एंड ऑक्सी विनिल्स एक्सपोर्ट सेल्स एलएलसी	***	***	***	(0-5)
वेस्टलेक विनिल्स कंपनी एलपी, ऑक्जियल एलएलसी एंड वेस्टलेक विनिल्स इंक.	***	***	***	(0-5)
असहयोगी/अवशिष्ट (830 डॉलर / मी. टन के न्यूनतम सीआईएफ)	***	***	***	0-5
थाईलैंड (सहयोगी)	***	***	***	
विनीथाई पब्लिक कंपनी लि०	***	***	***	0-5
थाई प्लॉस्टिक एंड केमिकल्स एससीजी परफॉरमेंस केमिकल कंपनी लि० एंड एससीजी प्लॉस्टिक कंपनी लि०	***	***	***	(0-5)
अवशिष्ट/असहयोगी (उच्चतम = सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार) (840 डॉलर/मी. टन के निम्नतम निर्यात कीमत)	***	***	***	5-10

क्षति पर निर्णायात्मक टिप्पणी

75. यह देखा गया है कि पाटित आयातों पर संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में कटौती हुई है। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। घरेलू उद्योग उत्पादन, बिक्रियों, लाभों, नकद लाभ और आर. ओ. सी. ई. की शर्तों में अपने निष्पादन में सुधार करने में सक्षम है। प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग उल्लेखनीय क्षति का सामना नहीं कर रहा है।

छ.3.5 पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना:

76. प्राधिकारी ने निर्णय दिया कि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इस जांच का केंद्र लगातार वाले पाटन और परिणामी क्षति के संभावित परिदृश्य की जांच करना है यदि पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है, चाहे कोई वर्तमान क्षति न हुई हो।

घरेलू उद्योग का मत:

- 77. पाटन के जारी रहने की संभावना और क्षति की परिणामी पुनरावृत्ति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं:-
 - भारत और अन्य देश जैसे चीन, आस्ट्रेलिया, टर्की और पाकिस्तान सिहत, विभिन्न बाजारों में पी. यू. सी. के पाटन का लंबा इतिहास रहा है, जहां इस पर इस समय विभिन्न देशों में शुल्क लागू है। याचिकाकर्ता पाटन के विपरीत प्रभावों से उबर रहे हैं और एक संवेदनशील स्थिति में हैं।
 - ii. चीन में उनकी घरेलू मांग की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं। पिछले 5 वर्षों में औसत प्रचालनात्मक दर 57 प्रतिशत से 72 प्रतिशत की रेंज में रही है, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि चीन में महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमताएं हैं शुल्कों की वापसी के मामले में, जिसे भारत को आसानी से अपवर्तित किया जा सकता है।

- iii. इसके अतिरिक्त, चीन में बड़ी संख्या में उत्पादकों द्वारा क्षमताओं को बढ़ाने की एक और योजना है और क्षिति अविध में चीन से महत्वपूर्ण निर्यात हुए हैं। चीन में पी. वी. सी. सस्पेंशन रेसिन के 150 से अधिक उत्पादक हैं। केवल सात चीनी उत्पादकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है, जिसमें से चार पर पृथक शुल्क लगा है और तीन पर अविषष्ट शुल्क लगा है। चूंकि चीन से उत्पादकों/निर्यातकों की अविषष्ट श्रेणी पर शुल्क राशि अन्यों की तुलना में अधिक है, इस समय चीन में बड़ी संख्या में उत्पादक भारत को उत्पाद का निर्यात भी नहीं कर रहे हैं। तथापि, शुल्कों की वापसी के पश्चात्, यह संभावना है कि ये अन्य उत्पादक भी निर्यात आरंभ कर देंगे।
- iv. आई. एच. एस. बाजार (विनिल्स) रिपोर्ट, 2017 के अनुसार चीनी उत्पादकों पर आवश्यकता से अधिक आपूर्ति किए गए घरेलू बाजार से दबाव को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादों को अपवर्तित करने के लिए दबाव पड़ने की संभावना है। यू. एस. बाजार के प्रतिबंध सहित, चीन अपने उत्पादों को आगे भारतीय बाजार में अपवर्तित कर देगा और यह भारतीय उद्योग की घरेलू कीमत और अन्य संबद्ध देशों से आयातों की कीमत की तुलना में निम्न कीमतों पर प्रवेश करता रहेगा।
- v. भारत को चीन से आयातों की तुलना पर मूल मामले प्रथम पुनरीक्षा जांच और वर्तमान जांच की पी. ओ. दर्शाता है कि भारतीय मांग में चीन का हिस्सा 2 प्रतिशत से बढ़कर 7 प्रतिशत हो गया है। चीन से आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक है। पिछले 10 वर्षों के लिए प्रवृत्त ए. डी. डी. के बावजूद चीन से आयातों में वृद्धि हुई है और इस बात की अत्यधिक संभावना है कि शुल्कों की वापसी के पश्चात चीन से आयातों में उच्च् दर पर वृद्धि होगी।
- vi. विभिन्न क्षेत्राधिकारों में चीन से निर्यातों पर ए. डी. डी. लागू है। पाकिस्तान प्राधिकारियों द्वारा भी उपायों को लागू किया गया है। पाकिस्तान ने 33,097 मी. टन निर्यातों के आधार पर शुल्क लगाया है, जबकि चीन भारत को इससे बहुत अधिक मात्रा में निर्यात कर रहा है।
- vii. तीसरे देशों के साथ भारतीय कीमतों की कीमत तुलना महत्वपूर्ण पाटन और क्षति मार्जिन और तृतीय देश आधार पर कीमत कटौती को दर्शाती है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ए. डी. डी. की वापसी के पश्चात भारत तीसरे देशों को किए गए निम्न कीमत वाले निर्यातों को आसानी से भारत को अपवर्तित किया जा सकता है। पिछले 5 वर्षों में भी भारत चीन के लिए शीर्ष निर्यात लक्ष्य रहा है।
- viii. याचिकाकर्ताओं ने प्रत्येक चीनी निर्यातक के लिए भारत को निर्यात कीमत और तृतीय देश की कीमतों की तुलना की है। यह उन उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पृथक-पृथक रूप से किया गया है, जिन्होंने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है और जिन्होंने प्रश्नावली उत्तर दायर नहीं किया है। उत्तर देने वाले चीनी निर्यातकों की तृतीय देश की कीमतों भारतीय कीमतें की तुलना में कम है। वे निर्यातक जो भारत को 70 प्रतिशत से अधिक निर्यात मात्रा के लिए उत्तरदायी हैं, ने प्रश्नावली उत्तर दायर किया है।
- ix. मांग का वर्तमान स्तर और भावी संभावित आयात दर्शाते हैं कि भारत संबद्ध वस्तुओं का प्रमुख क्रय कर्ता है। भारत का चीन से निर्यातों में शीर्ष स्थान पर आधिपत्य है।
- प्र. भारतीय बाजार में अभिभावी कीमतें चीन में उत्पादकों के लिए आकर्षण है, जैसा कि (क) भारत को वर्तमान निर्यात कीमत, और (ख) बाकी विश्व को वर्तमान निर्यात कीमत द्वारा स्थापित किया गया है। प्रत्येक व्यापार उद्यम अपने शीर्षस्थ सीमा को अधिकतम करने के लिए व्यापार कर रहा है, यह साक्ष्य है कि विदेशी उत्पादक अपनी तृतीय देश की निम्न कीमत वाली बिक्रियों को भारतीय बाजार को विपथित करने में नहीं हिचकेंगे। ए. डी. डी. को समाप्त किए जाने की स्थिति में, यह साक्ष्य है कि भारतीय प्रयोक्ता आयातित उत्पाद को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। पी. वी. सी. सस्पेंशन बाजार में, कीमत में 500 रू/मी. टन का अंतर किसी प्रयोक्ता को स्रोत का स्विच करने के लिए पर्याप्त है।
- xi. संबद्ध देशों के अप्रैल, 2008 से मार्च, 2018 (अर्थात 120 महीने) तक हर महीने आयात कीमतों के व्यवहार की जांच की गई है। संपूर्ण प्रक्रिया अप्रैल, 2008 –मार्च, 2018 तक 120 महीनों के लिए अपनाई गई थी। यह देखा गया कि कुल 120 महीनों में से चीनी कीमतें 28 महीनों में सबसे निम्न थी।

- xii. चीन इस समय भारत को अपना अधिकतर निर्यात भारतीय उद्योग की घरेलू कीमतों की तुलना में निम्न कीमतों पर निर्यात कर रहा है। संबद्ध वस्तुओं के महत्वपूर्ण निर्यातकों में से एक अन्य संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत कीमतों की तुलना में निम्नतम कीमत पर बिक्री कर रहा है।
- xiii. देश में घरेलू मांग की तुलना में काफी अधिक महत्वपूर्ण क्षमताएं यू. एस. ए. में विद्यमान हैं। पिछले 5 वर्षों में औसत प्रचालन दर 80 प्रतिशत से 86 प्रतिशत की सीमा में रही है जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि निर्यातों पर उल्लेखनीय दबाव है और उनमें महत्वपूर्ण प्रयक्त क्षमताएं विद्यमान हैं।
- xiv. आयातों की तुलना प्रथम एस. एस. आर. की पी. ओ. आई. में वृद्धि को दर्शाती है, क्योंकि मूल शुल्क निम्न था। जब प्रथम एस. एस. आर. में शुल्क में वृद्धि हुई तब वर्तमान जांच के पी. ओ. आई. में आयात भी कम हो गए थे, जिसका अर्थ है कि लागू किया गया शुल्क अनुचित आयातों के विरूद्ध एक निवारक के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्राधिकारों में यू. एस. ए. से निर्यात ए. डी. डी. को आकर्षित कर रहा है।
- xv. निम्नतम शुल्क रखने वाला वेस्टलेक भारत को सबसे अधिक मात्रा का निर्यात कर रहा है। उल्लेखनीय क्षमता रखने वाले अन्य उत्पादक भारत को महत्वपूर्ण मात्रा में निर्यात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन पर ए. डी. डी. की उच्च राशि लागू की गई है। शुल्क की उच्चतम राशि के साथ आयातों की पहुंच कीमत भारत में अभिभावी कीमतों की तुलना में काफी अधिक है। एक दृढ़ संभावना है कि जिन उत्पादकों की कीमतें प्रवृत्त ए. डी. डी. के कारण भारत में अप्रतिस्पर्धी हैं, शुल्कों को समाप्त किए जाने के बाद प्रतिस्पर्धी हो जाएंगी।
- xvi. 6 अमरीकी उत्पादकों में से, पिछली पुनरीक्षा जांच में प्रतिभागी 2 के विरूद्ध 4 उत्पादकों ने उत्तर दिया है। यह दर्शाता है कि उत्पादकों की भविष्य में निर्यात करने की योजना है और इसलिए उन्होंने वर्तमान जांच में भाग लिया है। 19 प्रतिशत उत्तर न वाले निर्यातकों की श्रेणी 1457 के. टी. क्षमताओं के लिए उत्तरदायी हैं, जो कि भारतीय मांग का लगभग आधा है।
- xvii. अन्य देशों को यू. एस. ए. कीमतें भारत की तुलना में उच्च है। तथापि, 59,409 मी. टन पर निर्यात मात्रा भारत की तुलना में निम्नतर कीमतों पर है। तृतीय देश आधार पर उल्लेखनीय पाटन और क्षति मार्जिन तथा कीमत कटौती है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि तृतीय देशों को निम्न कीमत वाले निर्यातों को ए. डी. डी. को समाप्त करने के बाद आसानी से भारत को विपथित किया जा सकता है।
- xviii. अप्रैल, 2008 से मार्च, 2018 तक (120 महीने) संबद्ध देशों की आयात कीमतों के प्रत्येक माह के व्यवहार की जांच की गई है। संपूर्ण प्रक्रिया अप्रैल, 2008 से मार्च, 2018 तक 120 महीनों के लिए अपनाई गई थी। यह देखा गया कि कुल 120 महीनों में से 49 महीनों में सभी देशों के बीच कीमतें निम्नतम थी। इसके अतिरिक्त, यू. एस. ए. से आयात कीमत 59 महीनों में चीन से आयात कीमतों की तुलना में निम्न थी। यू. एस. ए. घरेलू बिक्री कीमत की तुलना में निम्न कीमत पर भारत को उत्पाद का निर्यात कर रहा है।
- xix. हाल ही में एक उतार-चढ़ाव में, चीन और यू. एस. दोनों ने एक दूसरे पर 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त सीमा शुल्क टैरिफ लागू किए हैं। इसकी दोनों बाजारों अर्थात चीन द्वारा यू. एस. ए. को पी. वी. सी. आयात और चीन को यू. एस. ए. के पी. वी. सी. निर्यात, में पी. वी. सी. के निर्यात पर निहितार्थ हैं। इन कारणों से भारत के लिए समस्या के जटिल होने की संभावना है कि यू. एस. ए. से चीन को महत्वपूर्ण निर्यात हुए हैं (भारतीय मांग के लगभग 10 प्रतिशत की सीमा तक) और यू. एस. से चीन को निर्यात कीमत (लगभग 90 अमरीकी डॉलर/मी. टन द्वारा) बाकी विश्व को यू. एस. से निर्यात कीमत की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से निम्न है।
- xx. जहां तक थाईलैंड का संबंध है, देश में घरेलू मांग की तुलना में महत्वपूर्ण क्षमताएं काफी उच्च है।
- xxi. पिछले 5 वर्षों में औसत प्रचालन दर 83 प्रतिशत से 89 प्रतिशत की रेंज में है जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि थाईलैंड में महत्वपूर्ण प्रयुक्त क्षमताएं हैं, जिन्हें शुल्कों की समाप्त किए जाने के मामले में, भारत को आसानी से अपवर्तित किया जा सकता है। थाईलैंड में उल्लेखनीय रूप से स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य क्षमताएं हैं।
- xxii. मूल मामले, प्रथम पुनरीक्षा जांच और वर्तमान जांच की पी. ओ. आई. में भारत को थाईलैंड से आयातों की तुलना दर्शाती है कि वर्तमान जांच की पी. ओ. आई. में थाईलैंड से आयातों में 1058 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

- यह उत्पादकों के व्यवहार को दर्शाता है कि वे पिछले 10 वर्षों के लिए प्रवृत्त शुल्क के बाद भी लगातार निर्यात कर रहे हैं। प्रथम पुनरीक्षा जांच में 6.93 अमरीकी डॉलर/मी. टन की शुल्क में कमी के परिणामस्वरूप आयातों में 1058 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- xxiii. थाईलैंड से निर्यात विभिन्न क्षेत्राधिकारों में ए. डी. डी.के अध्यधीन थे और इस समय पाकिस्तान में ए. डी. डी. लागू है। भारत को निर्यातों की मात्रा की तुलना में पाकिस्तान ने आयातों की बहुत निम्न मात्रा पर ए. डी. डी.लागू किया है।
- xxiv. थाईलैंड में पी. वी. सी. सस्पेंशन का उत्पादन करने वाले दो उत्पादक हैं। पिछले 10 वर्षों के लिए प्रवृत्त शुल्कों के बावजूद, प्रथम पुनरीक्षा जांचों में पाटनरोधी शुल्कों की राशि में कमी के कारण थाईलैंड से निर्यातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, चूंकि, दोनों उत्पादकों ने उत्तर प्रस्तुत किया है, जो दर्शाता है कि भारत को निर्यात किए जाने की भावी योजनाएं हैं।
- xxv. अन्य देशों को थाईलैंड की कीमतें भारत की तुलना में उच्च हैं। महत्वपूर्ण निर्यात मात्रा भारत की तुलना में निम्न कीमत पर हैं। तृतीय देश आधार पर महत्वपूर्ण पाटन और क्षति मार्जिन व कीमत कटौती मौजूद है जो दर्शाता है कि तृतीय देशों को किए जाने वाले निम्न कीमत वाले निर्यात आसानी से भारत को विपथित किए जा सकते हैं।
- xxvi. अप्रैल, 2008 से मार्च, 2018 तक (अर्थात 120 महीनों) संबद्ध देशों के व्यवहार की माह से माह की कीमतों का व्यवहार दर्शाता है कि कुल 120 महीनों में से, 17 महीनों में कीमतें निम्नतम थीं। थाईलैंड से आयात कीमत 38 महीनों में चीन की कीमतों की तुलना में निम्न थीं। इसके अतिरिक्त, वे अपनी घरेलू कीमतों से निम्न कीमतों पर भी बिक्री कर रहे हैं। भारत विश्वव्यापी निर्यातों के 28 प्रतिशत के साथ थाईलैंड से निर्यातों में शीर्षस्थ स्थान पर आधिपत्य रखता है।
- xxvii. प्राधिकारी ने विभिन्न जांच परिणाम जारी िकए हैं, जिसमें उन्होंने संभावना दर्शाने वाले मापदंडों में से एक के रूप में अधिशेष क्षमताओं की विद्यमानता पर विचार िकया है। विश्वव्यापी रूप से अपनाई गई पद्धित इसका समर्थन करती है कि जांच कर्ता प्राधिकारियों ने क्षिति की पुनरावृत्ति की संभावना के प्रमुख साक्ष्यों से एक के रूप में अधिशेष क्षमताओं पर विचार िकया है। इसका महत्वपूर्ण क्षिति के संकट से संबंधित कानूनी प्रावधानों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से समर्थन िकया गया है।
- xxviii. ''स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य उत्पादन क्षमताओं' से तात्पर्य प्रयुक्त क्षमताओं की तुलना में अधिक उच्च क्षमताओं से है। घरेलू मांग से परे की कोई क्षमता ''स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य उत्पादन क्षमता'' को समाविष्ट करती है। उसके बाद अन्य देशों को किए जा रहे निर्यातों की मात्रा पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।
- xxix. यह साक्ष्य है कि चीनी उत्पादक 72-79 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर प्रचालन कर रहे हैं और इसलिए उल्लेखनीय रूप से कम उपयोग की गई उत्पादन क्षमताओं का सामना कर रहें हैं।
- xxx. जहां यू. एस. में मांग में वृद्धि हुई है और परिणाम स्वरूप यू. एस. से निर्यातों में 43 प्रतिशत से 39 प्रतिशत की गिरावट आई है, यू. एस. ने अभी भी 2017 में विश्वव्यापी रूप से 27,89,397 मी. टन पी. वी. सी. का निर्यात किया है। यू. एस. ए. से निर्यातों की कुल मात्रा उल्लेखनीय रूप से उच्च है। यू. एस. ए. ने चीन को लगभग 3 लाख मी. टन पी. वी. सी. निर्यात किया है। चीन द्वारा प्रस्तावित टैरिफ उपाय 25 प्रतिशत की सीमा में हैं जो इन निर्यातों को पूरी तरह से अलाभकारी बनाएगा। इन परिस्थितियों के तहत, यू. एस. में उत्पादक 3 लाख मी. टन की सीमा तक निश्चित रूप से बाजार की हानि का सामना करेगें जो भारतीय मांग का लगभग 10 प्रतिशत ठहरता है।
- xxxi. यू. एस. उत्पादकों के उत्पादन की लागत भूमंडलीय रूप से किसी अन्य देश की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से निम्न है, क्योंकि यू. एस. उत्पादन पी. वी. सी. के उत्पादन के लिए शैल गैस का प्रयोग करते हैं। यू. एस. में उत्पादकों की नकद लागत 500-660 अमरीकी डॉलर की सीमा में है। इसमें केवल मूल्य ह्रास राशि शामिल नहीं है।

- xxxii. चीनी संघ ने उच्च उपयोग के लिए कोई समर्थक प्रमाण उपलब्ध नहीं कराए हैं। यहां तक कि यह भी नहीं बताया गया है कि कैसे यह पी. यू. सी. के सभी चीनी विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है, क्या विवरण केवल चुनिंदा कुछ कंपनियों से संबंधित है या केवल उनके सदस्यों या संपूर्ण चीनी पी. वी. सी. उद्योग से । यह संघ सभी चीनी उत्पादकों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। रिकार्ड पर यह दर्शाने के लिए कोई सूचना नहीं है कि यह चीन में संपूर्ण पी. वी. सी. संस्पेंशन रेसिन उत्पादकों का प्रतिनिधि है।
- xxxiii. याचिकाकर्ताओं की सूचना पी. वी. सी. सस्पेंशन रेसिन के सभी चीनी उत्पादकों पर विचार करती है। साक्ष्य अप्रयुक्त उत्पादन क्षमताओं को दर्शाते हैं। हितबद्ध पक्षकार चीन में अप्रयुक्त क्षमताओं की अनुपस्थिति को स्थापित करने में सक्षम नहीं हैं।
- xxxiv. याचिकाकर्ता किसी सार्वजनिक सूचना की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए माल सूचियों पर संगत सूचना उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं हैं। हालांकि, संघ ने भी यह स्थापित नहीं किया है कि चीनी उत्पादक महत्वपूर्ण माल सूचियों का सामना नहीं करना पड़ता है। चीनी संयत्रों का सकल रूप से कम उपयोग किया जा रहा है जो स्वयं में यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि वे अल्प नोटिस पर अपनी माल सूचियों में वृद्धि कर सकते हैं।
- xxxv. याचिकाकर्ताओं ने प्रमाणात्मक कारकों के आधार पर संभावना की विद्यमानता का दावा किया है जिनमें कानून के तहत निर्धारित कारक और निरीक्षण सूचना के रूप में सकारात्मक साक्ष्यों के साथ भली भांति समर्थित अतिरिक्त कारक भी शामिल हैं, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संभावना की अनुपस्थित का दावा सिर्फ विवरणों पर आधारित है। सकारात्मक साक्ष्य के अर्थ को कानून और डब्ल्यू. टी. ओ. अपीलीय निकाय की संयुक्त राज्य जापान से कुछ विशेष हॉट-रोल्ड स्टील उत्पादों पर पाटनरोधी उपाय, मामले में जारी रिपोर्ट के अनुसार लिया जाएगा।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के मत:

- 78. नीचे पाटन के जारी रहने और क्षति की परिणामी पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन दिए गए हैं:-
- i. याचिकाकर्ताओं ने स्वयं स्वीकार किया है कि कोई कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण नहीं हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी स्वीकार किया है कि अन्य बाजारों को किए गए यू. एस. ए. निर्यातों का 99 प्रतिशत दावा किए गए एन. आई. पी. से अधिक कीमत पर है। अन्य शब्दों में, चाहे यह माना गया है कि (स्वीकार किए बिना) शुल्कों को समाप्त किए जाने से यू. एस. ए. अपने तृतीय देश निर्यातों को भारत की तरफ पनर्प्रेषण कर सकता था. ऐसी संभावना प्रतीत होती है कि उन आयातों की कीमत क्षति रहित होगी।
- ii. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई अधिशेष क्षमताओं की संकल्पना गलत है। भारतीय बाजार को निर्यातों के लिए एक अनुकूल गंतव्य नहीं माना गया है। भारतीय बाजार विशाल है और घरेलू क्षमता अकेले इन बड़ी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत की जनसंख्या चीन के बराबर है किंतु पॉलीमर के लिए मांग केवल पांचवा हिस्सा है।
- iii. प्राधिकारी ने विगत में निर्णायक की अनुपस्थिति/ क्षति की संभावना के कारण निर्णय समीक्षा जांच की शुरूआत करने अथवा उसकी समाप्ति से भी इंकार किया था। इसके अतिरिक्त, ए. डी. डी. का जारी रहना भी सार्वजनिक हित में नहीं होगा।
- iv. पिछले एस. एस. आर. में शुल्क को जारी रखने के कारण वर्तमान परिदृश्य में अब लागू नहीं होंगे।
- v. याचिकाकर्ता द्वारा क्षति की पुनरावृत्ति और पाटन की संभावना पर प्रस्तुत आंकड़े त्रुटिपूर्ण और असंगत है।
- vi. चीन के निर्यात प्रचालन का याचिकाकर्ता द्वारा गलत रूप से आकलन किया गया है और उनके दावों का कोई आधार नहीं है। आंकड़ों का कोई स्रोत नहीं है और इसलिए वे विश्वसनीय नहीं है। क्लोर – अल्काली इंडस्ट्री एसोसिएशन के सदस्यों के आंकड़ों के परस्पर विरोधी हैं।
- vii. कीमत आकर्षकता पर दावा भी त्रुटिपूर्ण है। भारत और अन्य देशों की कीमतें समकक्ष हैं। चीन से आयातों से इंकार करना भारतीय बाजार में उनकी अरूचि की ओर संकेत करता है। थाई और यू. एस. निर्यातक उन

कीमतों से उच्च कीमतों पर तृतीय देशों को अधिक मात्रा की बिक्री कर रहे हैं, जिस पर वे भारतीय बाजार में विक्रय कर रहे हैं।

- viii. एक निर्यात लक्ष्य होने का भारत का दावा भी गलत और झूठा है। उपलब्ध कराये गए आंकड़े एक बार फिर से अविश्वसनीय हैं। इसके अतिरिक्त, से अधिक वर्षों के लिए प्रवृत्त शुल्कों के साथ, व्यापार प्रणालियों को पुन: एक साथ इकट्ठा किया गया है और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इसे शुल्कों की समाप्ति पर संशोधित किया जाएगा।
- ix. याचिकाकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट की गई लाभप्रदता उनकी अत्यधिक उच्च आर. ओ. सी. ई., किसी प्रकार की कीमत से कम कीमत पर बिक्री की कमी (याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित) और विभिन्न अन्य सकारात्मक आर्थिक मापदंडों, को ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा उसकी संभावना का कोई मामला नहीं बनता। इस संबंध में, यह नोट करना भी संगत है कि चीन जन. गण. से आयात मात्रा कुल रूप में साथ ही सापेक्ष रूप में भी एक गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाती है और किसी भी संबद्ध देश से आयात न करना घरेलू उत्पादकों पर कीमत दबाव की ओर संकेत करता है।
- x. पी. ओ. आई. के पश्चात की अवधि से संबंधित कोई भी आंकड़े नहीं दिए गए हैं हालांकि, 6 महीने के लिए पश्च - पी. ओ. आई. आंकड़े आसानी से उपलब्ध थे। यह ऐसा संदेह है कि याचिकाकर्ताओं ने पश्च पी. ओ. आई. आंकड़े अधिप्राप्त किए हैं, किंतु वे उनके दावों का समर्थन नहीं करते।
- xi. याचिकाकर्ताओं ने चीन से आयातों की मात्रा की तुलना 10 वर्ष पहले चीन जन. गण. से होने वाले आयातों के साथ की है। विधि तंत्र पिछले 10 वर्षों में मांग में समग्र वृद्धि पर विचार, करने में असफल रहा है, जिससे चीन से आयातों की तुलना की जानी है। चीन जन. गण. से आयातों ने क्षित की अविध और पी. ओ. आई. में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी है और चीनी सीमा शुल्क के आंकड़ों के आधार पर, पी. ओ. आई. पश्चात की अविध में यह गिरावट जारी रही है।
- xii. चीन में कोई अधिक क्षमताएं नहीं हैं और उत्पादकों की सूचना पहले ही प्राधिकारी के पास दर्ज है। प्राधिकारी को संघ के प्रतिभागी सदस्यों के आंकड़ों की संगतता को अवश्य नोट करना चाहिए। यह वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ संगत चीनी क्षमताओं और उपयोग का प्रतिनिधि है।
- xiii. संघ के प्रतिभागी सदस्यों के आंकड़ों के आधार पर अधिकतर प्रतिभागी सदस्यों की महत्वपूर्ण बिक्रियां (लगभग 95 प्रतिशत) चीन घरेलू बाजार अथवा तृतीय देशों के निर्यात बाजारों को की गई हैं, भारतीय बाजार की बजाय, पी. ओ. आई. में अधिक सदस्यों, जो वर्तमान पुनरीक्षा जांच में प्रतिभागिता कर रहे हैं, की क्षमता के 90 प्रतिशत से अधिक भाग का पूरी तरह से उपयोग किया गया है, केवल एक लघु भाग अप्रयुक्त रह गया है, जांच में भाग लेने वाले चीन क्लोर अल्काली इंडस्ट्री एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा धारित कोई "निष्क्रिय" या अधिशेष क्षमता नहीं है।
- xiv. यह मानना उचित नहीं होगा कि चीनी में लघु उत्पादक भारत में शुल्कों को समाप्त किए जाने के लिए 11 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वे अपने लघु उद्योग प्रचालनों का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकें।
- xv. याचिकाकर्ताओं की लागत प्रवृत्तियों के समानांतर चल रही संबद्ध देशों की कीमत निर्धारण प्रवृत्तियां दर्शाती हैं कि संबद्ध देशों के लिए क्षति जांच अवधि के दौरान कीमत में उतार-चढ़ाव किसी अन्य कारण की बजाय लागत की प्रवृत्तियों पर आधारित हैं।
- xvi. चीनी जन. गण. स्वयं पी. वी. सी. का सबसे बड़ा प्रयोक्ता है। पी. वी. सी. का 90 प्रतिशत से अधिक चीन जन. गण. द्वारा घरेलू रूप से उपभोग किया जाता है और विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। चीन ने अपनी आपूर्ति पक्ष की क्षमताओं को प्रतिबंधित किया है और चीनी पी. वी. सी. क्षमताओं के विस्तार के विरूद्ध प्रतिबंध लागू है, इसलिए, चीन में बढ़ती हुई स्थानीय मांग को निर्यात बाजार की ओर उन्मुख होने की बजाय अधिक घरेलू बाजार उन्मुखी होने की आवश्यकता होगी।
- xvii. क्षति अवधि में चीन की उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं हुई है। इसमें सरकार की हाल की ''ऊर्जा संरक्षण एवं उत्सर्जन में कमी'' नीति के कारण भविष्य में इसका विस्तार नहीं होगा। संदर्भ इसके समर्थन में पी. आर. सी. पब्लिक सं. (2016) 57 के स्टेट काउंसिल के जनरल आफिस द्वारा जारी चीन सरकार के दिनांक 23

- जुलाई, 2016 के नोटिस, पुनर्संरचना पर मार्गनिर्देश परिवर्तन को बढ़ावा देने और पेट्रोकेमिकल उद्योग का लाभ बढ़ाने संबंधी मार्गनिर्देशों में प्रस्तुत किये गये हैं।
- xviii. आई. एच. एस. बाजार पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले वर्षों में यू. एस. ए. में पी. वी. सी. उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं होगी और इस वर्ष की प्रचालन दर के 90 प्रतिशत से अधिक होने की आशा है। यू. एस. उत्पादकों के पास इस समय भारत को महत्वपूर्ण अतिरिक्त मात्रा का निर्यात के लिए अतिरिक्त क्षमता नहीं है।
- xix. जहां तक यू. एस. ए. का संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने अविश्वसनीय स्रोतों का सहारा लिया है। ए. डी. नियमों के तहत "महत्वपूर्ण अत्यधिक क्षमताएं" संभावनाओं के विश्लेषण का भाग नहीं है और इसलिए अतर्क संगत है।
- xx. याचिकाकर्ताओं के निवेदन के अनुसार, उच्च शुल्कों के अधीन निर्यातक और उत्पादक भारत को कम निर्यात करेंगे और विपरीतत: कार्य करेंगे। तथापि, वर्तमान तथ्यात्मक मैक्ट्रिक्स में यह सत्य नहीं है, क्योंकि अविशष्ट दर की तुलना में फोरमोसा प्लॉस्टिक कारपोरेशन की शुल्क काफी कम है और इसने पूरी क्षित के दौरान भारत को अपने निर्यातों में वृद्धि नहीं की है और वास्तव में पी. ओ. आई. के दौरान निर्यात ही नहीं किया है।
- xxi. याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार किया है कि यू. एस. ए. की तृतीय देश निर्यात बाजार का लगभग 80 प्रतिशत उस कीमत से उच्च कीमत पर आधिपत्य रखता है जिस पर यू. एस. ए. भारत को निर्यात करता है। शुल्कों को समाप्त करने का भारत में कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा न ही यह आयातों के विपणन का कारण बनेगा।
- xxii. निर्यातकों ने प्रस्तुत किया है कि स्वायत्त संपन्न तृतीय देश द्वारा लागू किए गए शुल्क स्वरूप में प्रतिकारात्मक हैं और प्रत्येक राष्ट्र अपने स्वयं के शुल्क भी लागू करते हैं।
- xxiii. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि यह क्षति का सामना नहीं कर रहा है और पाटन के पिछले प्रभाव से उबर चुका है। यह दावा कि यदि ए. डी. डी. को समाप्त किया जाता है तो पाटन और क्षति की संभावना विद्यमान होगी, शब्दाडंबर पूर्ण बयानों पर आधारित है और समर्थक साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं हैं।
- xxiv. पिछली जांच पर विश्वास यह इंगित नहीं कतरा कि क्षति जारी रहेगी, क्योंकि वर्तमान मामले में तथ्यों और आंकड़ों में पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पिछले 15 वर्षों के दौरान घरेलू उत्पादकों ने क्षमताओं में लगातार वृद्धि की है और इन्हें और अधिक बढ़ाने की प्रक्रिया में हैं।
- xxv. डी. आई. ने दावा किया है कि थाईलैंड में अधिशेष क्षमताएं विद्यमान हैं जिसने इसकी घरेलू मांग को महत्वपूर्ण बनाया है। प्रथमत: ये आंकड़े आई. एच. एस. प्रकाशन पर आधारित होने के कारण, स्वीकृत साक्ष्य नहीं है। द्वितीय, उनमें उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में गैर पी. यू. सी. उत्पाद भी शामिल हैं। तृतीय, अत्यधिक क्षमताओं की उपस्थिति यह इंगित नहीं करती कि इसे भारत को अपवर्तित किया जाएगा।
- xxvi. हालांकि, डी. आई. ने स्वीकार किया है कि पिछले 10 वर्षों में थाईलैंड से आयातों में लगातार वृद्धि हुई है, उक्त वृद्धि को एक रिक्त स्थान के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि मांग में समानुपातिक वृद्धि के संदर्भ में देखा जा सकता है जिसे घरेलू उत्पादक पूरा करने में सक्षम नहीं थे और द्वितीय, चूंकि ऐसे निर्यातों पर ए. डी. डी. प्रवृत्त था, इसलिए इस तथ्य के बावजूद वृद्धि हुई कि पहुंच मूल्य डी. आई. के एन. आई. पी. से अधिक था।
- xxvii. यह आरोप कि ए. डी. डी. में कमी के कारण थाईलैंड से आयातों में वृद्धि हुई, गलत है, क्योंकि यह डी. आई. के एन. आई. पी. के विरूद्ध बेंचमार्क किया गया है। इसलिए थाईलैंड से आयात कीमतें भारत में लेवी के निर्वाह के दौरान घरेलू उद्योग के एन. आई. पी. के या तो समकक्ष होगी या उन से अधिक होगी।
- xxviii. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि थाईलैंड से अन्य देशों के निर्यात भारत की तुलना में कीमतों और निम्न मात्रा पर किए गए थे जो अनुबंध 19 पर निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन की संगणना को दर्शाने वाले आंकड़ों पर आधारित थे। ऐसी संगणनाओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी संगणनाओं पर पहुंचने के

स्रोत और आधार को उपलब्ध नहीं कराया गया है और घरेलू उद्योग ने निर्यात कीमत का निर्धारण करते समय बिना किसी आधार या समर्थन दस्तावेजों के बिना अतिशय समायोजनों का दावा किया है।

- xxix. घरेलू उद्योग का दावा है कि थाईलैंड से आयात कीमतें पिछले 120 महीनों में 38 महीनों के लिए चीन से कम थीं। तथापि, चीनी कीमतों पर आधारित ऐसा विश्लेषण असंगत है, क्योंकि प्रथमत: इसे वर्तमान क्षति विश्लेषण अवधि पर आधारित होना चाहिए और द्वितीय, तुलना भारत में अभिभावी कीमतों के साथ होनी चाहिए।
- xxx. हालांकि घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि क्षिति की निरंतरता/पुनरावृत्ति, भविष्य की घटनाओं के प्रति तथ्यात्मक विश्लेषण पर जोर देती है, किंतु अपने समर्थन में कोई सूचना उपलब्ध कराने में असमर्थ है जैसे पश्च पी. ओ. आई. सूचना या संबद्ध देशों में वर्तमान या नियोजित क्षमता परिवर्धन या आधारित भावी प्रक्षेपण, व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन आदि।
- xxxi. संयुक्त राज्य अमरीका (यू एस ए) में कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है । वर्ष 2018 के लिए वैश्विक विश्लेषण आई एच एस बाजार रिपोर्ट के अनुसार, यू एस ए में उत्पादक/निर्यातक क्षमता उपयोग के 85 प्रतिशत से अधिक पर प्रचालन कर रहे हैं । रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यू एस ए उत्पादकों, विशेषकर "शिनटेक" की क्षमता में आगामी पांच वर्षों में वृद्धि नहीं होगी । इस प्रकार, यू एस ए में कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है ।
- घरेलु उद्योग पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना को प्रमाणित करने में असफल रहा है, क्योंकि (i) पाटित आयातों में वृद्धि की कोई उल्लेखनीय दर नहीं है (क्षिति विश्लेषण अवधि में केवल 3 प्रतिशत) जैसाकि अनुबंध II पैरा (vii) के तहत जरूरी है। इसके बजाय, पी.यू.सी. के आयातों में वृद्धि संबद्ध देशों की तुलना में उच्चतर कीमतों वाले गैर-संबद्ध देश अर्थात जापान से है जो स्थापित करता है कि आयातों में वृद्धि/कमी कारक के रूप में कीमत पर निर्भर नहीं है, (ii) घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि 2013 की तुलना में चीन जन. गण., थाईलैंड, यू. एस. ए. की क्षमता में 13 प्रतिशत, 0 प्रतिशत और 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो क्षति विश्लेषण अवधि से बाहर है और इसलिए अतर्कसंगत है। इसके बजाय वास्तविक क्षति विश्लेषण अवधि में क्षमता में वृद्धि की दर क्रमश: 2 प्रतिशत, 0 प्रतिशत और 6 प्रतिशत है, (iii) अप्रयुक्त क्षमताओं की उपलब्धता और क्षमताओं में वृद्धि किसी भी प्रकार भारत को बढ़े हुए निर्यातों की संभावना की ओर संकेत नहीं करती क्योंकि स्वयं घरेल उद्योग की याचिका में दिए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि उन देशों के लिए क्षमताएं वही बनी हुई हैं जिनके भारत को निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अर्थात जापान, थाईलैंड जबिक चीन और यू. एस. ए. से उनकी क्षमताओं में वृद्धि के बावजूद निर्यातों में गिरावट आई है, (v) अधिशेष क्षमताओं की रेंज उन पर अर्थपूर्ण टिप्प्णियां किए जाने के लिए बहुत विस्तृत है और इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तृत याचिका में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए उक्त संबद्ध देश में कथित रूप से धारित अधिशेष क्षमताओं और भारत को निर्यात के बीच कोई संबंध नहीं है, (vii) घरेलू उद्योग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि भारी लाभ अर्जित करने के बाद भी यह अभी भी कैसे असरक्षित है. (viii) घरेल उद्योग द्वारा दावा किए गए अनुसार, भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता सही नहीं है, क्योंकि बाकी संबद्ध देशों से तृतीय देशों को 81 प्रतिशत निर्यात भारतीय बाजार की अपेक्षा उच्च कीमतों पर है और घरेल उद्योग द्वारा उनकी याचिका में प्रस्तुत आंकड़ों के लिए स्रोत उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- xxxiii. संभावना संबंधी विश्लेषण भी वर्तमान आंकड़ों के उद्देश्यपरक विचार प्रस्तुत करता है और क्या ऐसे आंकड़े दर्शाते हैं कि आयात भारत में ह्रासित/न्यून कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं। इस संबंध में, पहुंच मूल्य में ए. डी. डी. को शामिल किए बिना भी, आयात भारत में घरेलू उद्योग के उक्त एन. आई. पी. (जो लगभग 943 अमरीकी डॉलर है) से अधिक प्रवेश कर रहे हैं और इसलिए क्षति की पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं है।
- xxxiv. संबद्ध देशों में स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य क्षमताओं के दावे आई. एच. एस. प्रकाशन पर आधारित होने के कारण आधारहीन हैं जो कि लिखित निवेदनों में बताए गए कारणों से अस्वीकृत साक्ष्य हैं। संबद्ध देशों में क्षमताएं केवल नगण्य वृद्धि के साथ अधिकतर स्थिर बनी रही है। यह सुझाव देने के लिए रिकार्ड पर कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है कि निर्यातकों का निर्यात प्रचालन और अत्यधिक क्षमता की विद्यमानता स्वत: ही भारत को निर्यातों के अपवर्तन का कारण बनेंगे।

छ.3.6 प्राधिकारी द्वारा जांच

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच संबद्ध वस्तुओं पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है और प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और क्षिति की संभावना की जांच की जानी है। प्राधिकारी ने नियमों के अनुबंध ॥ (vii) की शर्तों में महत्वपूर्ण क्षिति के जोखिम से संबंधित मापदंडों पर विचार करते हुए क्षिति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना की जांच की है। नियमों के अनुबंध ॥ के खंड (vii) में निम्नलिखित कारकों के लिए व्यवस्था की गई है:-

क्षति मार्जिन पी. ओ. आई. और पश्च पी. ओ. आई. के लिए मामूली रूप से सकारात्मक है जबकि समग्र आधार पर यू. एस. ए. और थाईलैंड के लिए ऋणात्मक है।

महत्वपूर्ण रूप से बढ़े हुए आयातों की संभावना को दर्शाते हुए भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की महत्वपूर्ण दर

80. आयातों की प्रवृत्ति निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	पी ओ आई	पश्च पीओआई (ए)
1	संबद्ध देश						
क	चीन	मी. टन	2,90,122	1,69,114	2,47,949	2,07,289	1,22,724
ख	थाईलैंड	मी. टन	35,687	18,100	33,505	1,17,154	50,126
ग	यू. एस. ए.	मी. टन	15,082	14,188	47,912	26,853	72,204
2	उप जोड़	मी. टन	3,40,890	2,01,402	3,29,366	3,51,297	2,45,054
3	अन्य देश	मी. टन	8,82,293	12,12,964	12,60,085	12,34,889	11,02,677
4	जोड़	मी. टन	12,23,183	14,14,366	15,89,452	15,86,186	13,47,731

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों में 2015-16 में गिरावट आई और तत्पश्चात पी. ओ. आई. में वृद्धि हुई। पी. ओ. आई. के पश्चात की अविध में चीन और थाईलैंड से आयातों में गिरावट आई। तथापि, चीन से आयात महत्वपूर्ण बने रहे। यू. एस. ए. से आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पी. ओ. आई. पश्चात की अविध में वे दोगुनी से अधिक हुई। प्राधिकारी ने पाया कि आयातों में कोई निर्धारित पैटर्न नहीं है, किंतु आयातों का स्तर उल्लेखनीय बना रहा है

किसी अतिरिक्त आयातों को अमामेलित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय बाजारों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़े हुए पाटित आयातों की संभावना को दर्शाते हुए निर्यातक की क्षमता, में पर्याप्त स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य अथवा तत्काल, पर्याप्त वृद्धि

82. महत्वपूर्ण क्षिति के संकट को सुनिश्चित करने के लिए इस मापदंड को भारतीय बाजार को निपटान योग्य मात्रा के अपवर्तन की संभावना का अन्वेषण करने के लिए स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य क्षमताओं और क्षमता परिवर्धन, यदि कोई हो, के मूल्यांकन की आवश्यकता है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध देशों में उत्पादक पहले ही उल्लेखनीय अधिशेष क्षमताओं का सामना कर रहे हैं जैसा कि नीचे सारणी में दिया गया है और कि ये उत्पादक बड़ी संख्या में देशों को उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं जिसका उल्लेखनीय समानुपात भाग भारत के संबंध में निर्धारित कीमतों से कम कीमत पर निर्यात किया जा रहा है जो इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क को वापिस लिए जाने की स्थित में भारत को इन निर्यातों के अपवर्तन की संभावना को दर्शाते हैं:-

(विवरण) इकाई: के. टी./वाई	इकाई	2012	2013	2014	2015	2016
चीन						
क्षमता	के.टी./वाई	23,410	24,760	23,890	23,480	23,260
उत्पादन	के.टी./वाई	13,416	15,295	16,296	16,092	16,691

क्षमता उपयोग	के.टी./वाई	57%	62%	68%	69%	72%
आयात	के.टी./वाई	1,060	915	808	820	752
निर्यात	के.टी./वाई	395	662	1,111	780	1,117
मांग	के.टी./वाई	14,081	15,548	15,993	16,132	16,326
वृद्धि दर	%	3%	10%	3%	0.90%	1.20%
स्वतंत्र निपटान योग्य क्षमता	के.टी./वाई	8,934	8,550	6,786	6,568	5,817
<u>यू. एस. ए.</u>		l .				
क्षमता	के.टी./वाई	7,779	7,794	7,884	7,884	8,184
उत्पादन	के.टी./वाई	6,719	6,716	6,574	6,622	6,949
निर्यात	के.टी./वाई	3,015	2,903	2,641	2,618	2,776
मांग	के.टी./वाई	3,960	4,071	4,174	4,229	4,373
वृद्धि दर	%	8.30%	2.80%	2.50%	1.30%	3.40%
स्वतंत्र निपटान योग्य क्षमता	के.टी./वाई	804	820	1,069	1,037	1,035
उत्पादन के % के रूप में निर्यात	%	45%	43%	40%	40%	40%
<u>थाईलैंड</u>		- 11	.	II.	'	1
क्षमता	के.टी./वाई	890	890	890	890	890
उत्पादन	के.टी./वाई	783	774	792	739	792
घरेलू मांग	के.टी./वाई	284	289	281	228	177
विश्व में निर्यात	के.टी./वाई	344	302	339	333	494
भारत में निर्यात	के.टी./वाई	47	45	25	45	137
स्वतंत्र निपटान योग्य क्षमता	के.टी./वाई	262	299	270	329	219
उत्पादन के % के रूप में निर्यात	%	44%	39%	43%	45%	62%

- 83. प्राधिकारी यह अनुरोध करते हैं कि थाईलैंड के मामले में उत्तर दोनों उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो थाईलैंड में समग्र वस्तुओं का उत्पादन करता है । यह नोट किया जाता है कि चूंकि बिक्री के लिए अतिरिक्त क्षमता नहीं है अत: केवल व्यापार से संबंधित विपथन के संबंध में संभावना की जांच की गई है ।
 - <u>क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं, जिनका घरेलू कीमतों पर उल्लेखनीय ह्रासित अथवा न्यूनीकरण</u> प्रभाव होगा और जिनसे आगे आयातों के लिए मांग में वृद्धि की संभावना होगी ।
- 84. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में चालू पहुंच कीमत पर लागू ए. डी. डी. पर विचार किए बिना पी. ओ. आई. के दौरान कीमत कटौती सकारात्मक रही है। यह अवलोकन किया गया है कि वर्तमान ए. डी. डी. की विद्यमानता के कारण आयातों के परिणामस्वरूप घरेल उद्योग की कीमतों कोई में कीमत ह्रास/न्यनीकरण नहीं हआ।

<u>चीन और यू. एस. ए. द्वारा लागू किए गाए व्यापार प्रतिबंधात्मक उपाय और संबद्ध वस्तुओं पर लागू पाटनरोधी उपाय</u>

85. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि यू. एस. ए. से आयातों पर चीन और तुर्की में ए. डी. डी. लागू है। पाटनरोधी शुल्क 15 से अधिक वर्षों से प्रवृत्त है। पाटन और क्षति की संभावना के आधार पर शुल्क लागू किए हैं। इसके अलावा, पाकिस्तान ने भी थाईलैंड पर पाटनरोधी शुल्क लगाए हैं। चीन और यू. एस. ए. ने एक दूसरे पर 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त सीमा शुल्क टैरिफ लगाया है जो दोनों बाजारों में पी. वी. सी. निहितार्थ है। प्राधिकारी ने भारतीय बाजार की आकर्षकता और प्रकटन के उत्तर में दायर टिप्पणियों पर विचार करते हुए निम्नानुसार पाटनरोधी शुल्क के समापन की स्थित में तृतीय देश निर्यातों के विपणन की जांच की है।

86. प्राधिकारी नोट करते है कि भारत में अपवर्तित किए जा रहे तृतीय देश निर्यातों के विपणन की संभावना को निर्धारित करने के लिए, संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों द्वारा विद्यमान अधिशेष क्षमता और क्षमता परिवर्धन, यदि कोई हो के होते हुए भी, भारतीय बाजार की आकर्षकता का विश्लेषण और उसके द्वारा घरेलू उद्योग पर इसकी क्षति कारक प्रभाव को प्रकटन विवरण में बताए गए विधि तंत्र के अनुसार लागू किया जा चुका है।

भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता संभावना विश्लेषण

- 87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पी. ओ. आई. के दौरान सभी सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन नयूनतम सीमा से अधिक है जैसा कि पूर्ववर्ती पैरा में कहा गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पी. ओ. आई. के दौरान और पी. ओ. आई. पश्चात यू. एस. ए. से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में क्षिति मार्जिन ऋणातमक है, जबिक थाईलैंड के लिए, क्षित मार्जिन टीपीसी/एससीजी ग्रुप के लिए ऋणात्मक है और पी. ओ. आई. में और पी. ओ. आई. पश्चात विनीथाई के लिए सकारात्मक है। है। अत: प्राधिकारी ने प्रकटन टिपपणियों सहित पाटन और क्षित की संभावना के पहलुओं पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों को ध्यान में रखने के बाद ही क्षित की संभावना की जांच की है।
- 88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने तीन संबद्ध देशों के लिए पी. ओ. आई. और पी. ओ. आई. पश्चात अवधि के लिए ट्रेड मैप से भूमंडलीय निर्यात आंकड़े उपलब्ध कराए थे। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े सकल आंकड़े हैं और न कि सौदावार। इसलिए ये आंकड़े वास्वितक नहीं है और इन्हें संभावना के विश्लेषण हेतु नहीं अपनाया जा सकता।
- 89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि सहयोग उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अगोपनीय पाठ में उपलब्ध कराए गए पी. ओ. आई. और पी. ओ. आई. पश्चात अविध के लिए तृतीय देश सौदा वार आंकड़े अर्थपूर्ण नहीं हैं और यह कि सभी को गोपनीय रखा गया है और वे इस पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने पी. ओ. सभी संबद्ध देशों के लिए पी. ओ. आई. और पी. ओ. आई. पश्चात अविध के लिए दिनांक 14.06.2019 के पत्र के अनुसार मासिक कुल आंकड़े और चीन के लिए उत्पादन वार आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आंकड़े उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए ट्रेड मैप आंकड़ों के साथ सकल आधार पर सह संबद्ध है जैसा कि प्रकटन में कहा गया था। तथापि केवल सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों और ट्रेड मैप को अपनाया गया है। जहां तक हितबद्ध पक्षकारों में से एक के आरोप का संबंध है कि डब्ल्यू. टी. ए. के आंकड़े क्यों नहीं अपनाए गए, प्राधिकारी ने स्पष्ट किया है कि डब्ल्यू. टी. ए. एक सौदावार आंकड़े नहीं हैं और प्राधिकारी ने ट्रेड मैप डाटा को मान्य बनाने के लिए, ट्रेड मैप डाटा के साथ सकल आधार पर डब्ल्यू. टी. ए. डाटा को सह सबंद्ध किया है।
- 90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया ट्रेड मैप डाटा विभिन्न गंतव्यों को भेजा गया विश्वव्यापी निर्यात का मासिक डाटा है जो ट्रेड मैप डाटा अपनाने को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए पी. ओ. आई. और पी. ओ. आई. पश्चात कुल आधार पर डी. जी. टी. आर. के पास उपलब्ध डब्ल्यू. टी. ए. डाटा के साथ घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए ट्रेड मैप डाटा को मान्य बनाता है।
- 91. यह सत्यापित करने के लिए कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनाया गया ट्रेड मैप का मासिक कुल डाटा विश्वसनीय और प्रतिनिधि है, प्राधिकारी पी. ओ. आई. और पी. ओ. आई. पश्चात अवधि के दौरान सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए तृतीय देश सौदावार आंकड़ों का विश्लेषण किया है। चूंिक, सहयोग उत्पादक/निर्यातक पी. ओ. आई. के दौरान चीन से भारत के निर्यातित मात्रा का लगभग 50 प्रतिशत, यू. एस. ए. से 80 प्रतिशत और थाईलैंड से 100 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके विश्लेषण को संबंधित संबद्ध देशों से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए भी प्रतिनिधि के रूप में विचारित किया गया है।
 - 92. उपर्युक्त और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के अवलोकनों को ध्यान में रखते हुए कि घरेलू उद्योग द्वारा अपनाया गया ट्रेड मैप डाटा मासिक सकल स्तर पर है, प्राधिकारी ने पी. ओ. आई. के दौरान और पी. ओ. आई. पश्चात, दोनों के लिए सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए तृतीय देश सौदावार निर्यात आंकड़ों का विश्लेषण किया है।
 - 93. विश्लेषण को प्रथम: वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के समापन की स्थिति में भारतीय बाजार की आकर्षकता की सीमा का मुल्यांकन करने और उसके पश्चात कौन से सभी सौदे भारत में घरेलू उद्योग को क्षति कारक होंगे, जानने के लिए

किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने निम्नलिखित पर विचार किया है जैसा कि प्रकटन विवरण में कहा गया है।

- क. पी. ओ. आई. के दौरान भारत के अतिरिक्त अन्य देशों को सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा निर्यात और वर्तमान उपायों की समाप्ति पर भारत को उनका संभावित अपवर्तन और उसके द्वारा डी. आई. पर विपरीत प्रभाव। विपणन की सीमा का विश्लेषण करने के लिए, भारत के अतिरिक्त अन्य देशों को निर्यात कीमतों को भारत को निर्यात कीमतों की तुलना में निम्न हैं, विपणन के लिए भारतीय बाजार के आकर्षण और विपणन निर्यातों के पहुंच मूल्य एन. आई. पी. की तुलना में निम्न हैं तो उन्हें क्षति कारक माना जाएगा।
- ख. उपर्युक्त विधि तंत्र पी. ओ. आई. के लिए अपनाए गए विश्लेषण के अतिरिक्त पी. ओ. आई पश्चात अवधि के दौरान सहयोगी उत्पाकदों/निर्यातकों द्वारा तृतीय देश निर्यातों पर भी लागू होगा।
- 94. संभावना का विश्लेषण केवल ''क्षिति की संभावना" के लिए किया गया है, क्योंकि पाटन की विद्यमानता सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पी. ओ. आई. के दौरान स्थापित की गई है। अविशष्ट / असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों को सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना को लागू किए जाने के द्वारा भी पाटन के रूप में मूल्यांकित किया गया है। आकर्षकता और विपणित निर्यात जो क्षिति कारक हो सकते हैं, पर भी राष्ट्र स्तर पर मूल्यांकन किया गया है। हालांकि इस पर सहयोगी उत्पादक/निर्यातक स्तर पर व्यक्तिक रूप से विचार किया गया है। आकर्षकता और निर्यातों को अपवर्तित किए जाने की संभावना की सीमा, जो क्षिति कारक हैं, को सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए संबद्ध देश के लिए मूल्यांकित किया गया, ट्रेड मैप डाटा के अनुसार संबद्ध देश के भूमंडलीय निर्यातों (भारत को छोड़कर) पर लागू किया गया है। ट्रेड मैप डाटा को समग्र आधार पर उचित रूप से डब्ल्यू. टी. ए. डाटा के साथ सह संबद्ध किया गया जैसा कि ऊपर कहा गया है। तथापि, चूंकि, थाईलैंड में केवल 2 उत्पादक हैं, वे दोनों ही सहयोगी हैं, केवल इन दोनों सहयोगी उत्पादों/निर्यातकों के समेकित आंकड़े ट्रेड मैप या डब्ल्यू. टी. ए. डाटा का आश्रय लिए बिना संदर्भित किए गए हैं।
- 95. भारत के लिए बाजार आकर्षकता का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित पर विचार किया गया है जैसाकि प्रकटन विवरण में कहा गया है।

क.

- 1. किसी सहयोगी उत्पादक/निर्यातक की भारत से अन्य देशों की सौदावार एफ. ओ. बी. निर्यात कीमत।
- 2. उपलब्ध एफ. ओ. बी. कीमत को अपनाया गया है अथवा अन्यथा रूप से एफ. ओ. बी. को माल कीमत के साथ सी. आई. एफ. कीमत से परिकलित किया गया है, जैसा दावा किया गया है अथवा अन्यथा सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के साथ तृतीय देश सौदे के औसत माल भाड़े पर विचार करने के द्वारा।
- 3. इसके अतिरिक्त, उक्त औसत माल भाड़े की संबद्ध देश से भारत को औसत माल भाड़े के साथ तुलना की गई है और दोनों में से निम्न को अपनाया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि विपणन की आकर्षकता की सीमा बढ़ाई नहीं गई है और आकर्षकता का मूल्यांकन करने के लिए केवल अपरिवर्तनशील अनुमानों को लागू किया गया है।
- 4. ऊपर संदर्भित सहयोगी उत्पादक/निर्यातक की एफ. ओ. बी. कीमत की उस विशेष माह के लिए भारत की एफ. ओ. बी. कीमत से की गई है।
- ख. विश्लेषण के दूसरे स्तर पर, तृतीय देश से विपथित किए जाने की संभावित क्षति कारक निर्यातों का मूल्यांकन करने के लिए ऐसे तृतीय देश के 'पहुंच मूल्य' किसी उत्पादक/निर्यातक की एफ. ओ. बी. निर्यात कीमत को समुद्री माल भाड़े को जोड़ने के द्वारा जैसा कि सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा रिपोर्ट किया जाता है और उसके पश्चात भारत को 0.05 प्रतिशत समुद्री बीमा जोड़ कर तथा मूल्यांकन योग्य मूल्य पर बी. सी. डी. और उप कर जोड़ कर परिकलित किया जाता है
- 96. पहुंच मूल्य की तब पी. ओ. आई. और पी. ओ. आई. पश्चात अवधि के लिए भी एन. आई. पी. के साथ तुलना की जाती है। क्षिति कारक निर्यातों का समानुपात जैसािक सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए मूल्यांकित किया गया है, विश्वव्यापी स्तर पर लागू किया जाता है जैसा विश्वव्यापी स्तर पर आकर्षकता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है जैसािक ऊपर पैराओं में कहा गया है।
- 97. उपर्युक्त के आधार पर, संभावित मूल्यांकित क्षति कारक आयात, पी. ओ. आई. और पी. ओ. आई. पश्चात के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग के समानुपात के रूप में इस प्रकार है; चीन, यू. एस. ए. और थाईलैंड के लिए क्रमश:

- 10-20 प्रतिशत, 30-40 प्रतिशत और 0-10 प्रतिशत । पी. ओ आई. पश्चात अवधि के लिए ये समानुपात क्रमश: 5-15 प्रतिशत, 70-80 प्रतिशत और 0-10 प्रतिशत हैं।
- 98. घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर, जांच की अविध के दौरान चीन, यू.एस.ए और थाईलैंड के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं की कुल मांग के अनुपात के रुप में जांच की अविध के दौरान और जांच की अविध के बाद मूल्यांकन किए गए संभावित क्षतिकारक आयात क्रमश: 10-20 %, 5-15% और 0-10% हैं। जांच की अविध के बाद के लिए, यह अनुपात क्रमश: 5-15%,10-20%और 0-10 % हैं।

झ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

99. मैसर्स वेस्टलेक विनाइल कंपनी एलपी (उत्पादक और निर्यातक); मैसर्स एक्सियल, एलएलसी (संबद्ध उत्पादक); मैसर्स वेस्टलेक विनाइल्स इंक. (संबद्ध उत्पादक) जिनका प्रतिनिधित्व मैसर्स सीतारमण एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया

- i. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ओसीटी परीक्षा के लिए उत्तरदाताओं द्वारा उनके संबद्ध क्रेताओं को की गई घरेलू बिक्री को गलत रद्द किया है। कानून में ऐसा कोई निर्धारण नहीं है जो केवल कीमत अंतर के आधार पर संबद्ध क्रेताओं को बिक्री रद्द करने के लिए अधिदेशित करे अथवा अनुमति दे। पूर्व निर्णायक समीक्षा-1 में संबद्ध और असंबद्ध, दोनों ग्राहकों को घरेलू बिक्री सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए साथ-साथ मानी गई थी। संबद्ध और असंबद्ध क्रेताओं के बीच बिक्री कीमत में अंतर *** प्रतिशत की रेंज में है जो सामान्य है और किसी भी परिस्थिति में उसे रद्द करने के लिए अधिक अथवा सामान्य नहीं मानी जा सकती।
- ii. वीसीएम, एसजीए की लागत बिना कोई कारण बताए तथा किए गए संशोधनों के लिए आधार प्रकट किए बिना भी प्राधिकारी द्वारा "स्वविवेक" से बढ़ाई गई है। ऐसा कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है कि एसजीए लागतें "बिक्री कारोबार" के आधार पर आबंटित की जाएंगी।
- iii. किसी निर्यातक अथवा उत्पादक द्वारा प्रस्तुत लागतें तब तक स्वीकार की जाएंगी जब तक वे निर्यातक द्वारा रखे गए रिकार्ड के आधार पर हैं और वे रिकार्ड जीएएपी के अनुसार हैं। पूर्व में माने न गए लेखांकन रिकार्डों से उद्धरों सहित कई कार्यकारी तालिकाएं और विवरणियां यह दर्शाती हैं कि प्रस्तुत लागत उपयुक्त है।
- iv. एथिलीन और क्लोरीन अपने क्लोर-अलकाली प्रभाग में और जब उपर्युक्त मदें "पीवीसी प्रभाग" को अंतरित की जाती हैं, अंतरण कीमत पर रिकार्ड की जाती हैं। लाभ राष्ट्रीय होता है और इस प्रकार समायोजित किए जाने की आवश्यकता होती है। तथापि, उसे रद्द कर दिया गया है।
- v. प्राधिकारी ने प्रति यूनिट लागत निकालने के लिए कुल बिक्री मात्रा के बजाए कुल उत्पादन द्वारा मैसर्स वेस्टलेक विनाइल्स कंपनी और एक्सियाल एलएलसी की कुल बिक्री लागत विभाजित की है। उत्पादन मात्रा बिक्री मात्रा से कम है जिसके कारण प्राधिकारी द्वारा निकाली गई प्रति यूनिट लागत अधिक है।
- vi. प्राधिकारी ने उत्पादन की भारित औसत कारखानागत लागत *** प्रति मी. टन अमेरिकी डॉलर उल्लिखित की है जो टंकण की त्रुटि प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वास्तव में उत्पादन की भारित औसत कारखानागत लागत *** प्रति मी. टन अमेरिकी डॉलर अपनाई है। इसके परिणामस्वरूप, असंबद्ध व्यापारियों को *** प्रतिशत घरेलू बिक्री हुई जिसे लाभप्रद माना जा रहा है। दूसरे, *** प्रति मी. टन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा गलत है क्योंकि सही आंकड़ा *** प्रति मी. टन अमेरिकी डॉलर होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप असंबद्ध व्यापारियों को लगभग *** लाभप्रद घरेलू बिक्री होगी।
- vii. भारत में मौजूदा बाजार से कम कीमत वाले संबद्ध सामानों का व्यापार आने से भारत में लाई जा रही कीमत क्षमता तीसरे देशों से लाई गई कीमत से काफी अधिक होनी चाहिए जिसका एनआईपी से कोई संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त, बाजार आकार काफी व्यापक होना चाहिए और जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्पादकों एवं निर्यातकों का संबंध है, और वृद्धि की संभावना भी होनी चाहिए, पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में व्यापार पलटने की संभावना नहीं बढ़ती क्योंकि उनके पास निर्यात के लिए अन्य महत्वपूर्ण, व्यापक और स्थापित बाजार है जिनमें अब भी मांग बढ़ रही है जबिक भारत जिसका अपने निर्यातों का बहत थोड़ा सा भाग ही है. स्थिर हो रहा है।

- viii. व्यापार परिवर्तन के लिए रुझान एनआईपी से कम होने वाली कीमतों पर निर्भर नहीं करता, वह उत्पाद की गुणवत्ता एवं सुपुर्दगी समय जैसे कारकों पर निर्भर करता है। अन्यथा जो देश जांच के अध्यधीन नहीं है, उनसे आयात इतनी अधिक मात्रा में घरेलू बाजार में नहीं आए होते।
- ix. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मानी गई रिलायंस और फिनोलेक्स की उत्पादन मात्रा जिसके आधार पर यह निर्धारित किया गया है कि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के रूप में योग्य हैं, खुद रिलायंस और फिनोलेक्स द्वारा सिद्ध किया जाना है अथवा कुछ अन्य सार्वजनिक दस्तावेजों के आधार पर सिद्ध किया जाना है।
- x. प्राधिकारी की कई पूर्व की टिप्पणियों में यह माना गया कि लाभप्रदता और अन्य मानदंडों की प्रवृत्ति में उछाल के मद्देनजर पूंजीगत निवेश जुटाने में घरेलू उद्योग की क्षमता प्रभावित नहीं हुई थी। तथापि, प्राधिकारी ने इस मामले में विपरीत टिप्पणी की है।
- xi. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए निर्धारित स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य क्षमताएं थाइलैंड की क्षमताओं से ज्यादा अधिक नहीं हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे यह देखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादकों के पास कोई अधिशेष क्षमताएं मौजूद नहीं हैं, जैसा कि थाइलैंड के लिए माना गया है।
- xii. मेसर्ज सीतारमन एसोसिएट्स ने दिनांक 5.7.2019 के पत्र द्वारा बताया है कि चूंकि केन्द्रीय बजट 2019-20 के अनुसार विचाराधीन उत्पाद पर बीसीडी की पूर्व-बजट प्रभावी दर (3904 और उसके अंतर्गत और 8 अंकीय वर्गीकरण) 7.5% से बढ़ा कर 10% कर दी गई है, निर्दिष्ट प्राधिकारी को क्षिति मार्जिन का निर्धारण करने और ऐसी संभवनाएं होने के समय 2.5% की बढ़ी हुई बीसीडी के संदर्भ में पहुंच मूल्य को संशोधित करना चाहिए।

100. मैसर्स ऑक्सी विनाइल/ऑक्साइड केमिकल्स/त्रिकोण/आईसीसी केमिकल कारपोरेशन जिनका प्रतिनिधित्व मैसर्स ईएलपी द्वारा किया गया

- i. याचिकाकर्ताओं को अद्यतन आयात आंकड़े विशेष रूप से जांच की अवधि के बाद के लिए या तो जांच की शुरूआत के समय अथवा जांच के बाद 40 दिनों के भीतर और न कि जांच के इस विलंब के स्तर पर दायर करने चाहिए थे। जांच के आरंभिक चरणों में याचिकाकर्ताओं द्वारा उपर्युक्त जांच की अवधि के बाद की सुचना प्रदान न करने से नियम 6 के तहत हितबद्ध पक्षकारों के अधिकार प्रभावित हुए हैं।
- ii. जहां तक पूर्ण अध्याय 3904 को शामिल करने पर विचार करने का संबंध है, यह असंगत होगा क्योंकि शुल्क की वैधता उत्पाद पर देय रहती है न कि वर्गीकरण के आधार पर और इसके अतिरिक्त ऐसे अन्य उत्पाद हैं जो वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हैं जो वर्गीकरण में आते हैं।
- iii. यह अनुचित है कि प्राधिकारी पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए भारत में प्रतिभागी उत्पादकों एवं निर्यातकों की 70-80 प्रतिशत बिक्री का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद करते हैं, परंतु घरेलू उद्योग निर्धारित करने के लिए भारत में घरेलू उत्पादकों की अधिकतम प्रतिभागिता की अपेक्षा नहीं रखते। यह निर्दिष्ट प्राधिकारी बनाम होलडोर तापसे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए है जिसमें यह नोट किया गया है कि यदि मांगी गई सूचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर नहीं की गई है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी एक प्रतिकृत दृष्टिकोण ले सकते हैं।
- iv. इसके अतिरिक्त, संभावना के मूल्यांकन के मामले में भी कई कारक हैं जिनमें घरेलू उद्योग की लागत, कीमत और निष्पादन संगत हैं। इस प्रकार, घरेलू उद्योग का आधार एवं क्षेत्र क्षति के बार-बार होने की संभावना में भी संगत हो जाता है।
- v. यदि घरेलू उद्योग उन पक्षकारों को हटाने के बाद बनाया जाता है जिनको शामिल करने से अन्यथा कम एनआईपी और लागत दर्शाएगी, तो संभावना के मूल्यांकन का ह्रास होना निश्चित है।
- vi. आरआईएल और एफआईएल द्वारा रुचि का अभाव इसी तरह इस निष्कर्ष का समर्थन करता है कि ऐसे आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति का खतरा भविष्य में होने की संभावना नहीं है।

- vii. संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों पर शुल्क लगाना अनुचित है जब संयुक्त राज्य अमेरिका से जांच की अविध में आयात कुल आयातों के 2 प्रतिशत से कम है और आयातों के विभिन्न अन्य स्रोत काफी अधिक मात्रा में तथा तुलनीय अथवा कम कीमतों पर आ रहे हैं।
- viii. संयुक्त राज्य अमेरिका को शामिल करना और अन्य देशों को हटाना, समान बाजार और आर्थिक तथ्यों के संदर्भ में रहते हुए, अमान्य है।
- ix. प्राधिकारी ने उल्लेख किया है कि सभी शामिल कंपनियों ने "अपने संगत प्रश्नावली के उत्तर तथा भारत और अन्य देशों को जांच की अवधि के बाद के बिक्री आंकड़े" भी दायर किए हैं। इस संबंध में, यह नोट किया जाए कि निर्यातकों ने भी जांच की अवधि के लिए तीसरे देशों को बिक्री से संबंधित आंकड़े दायर किए हैं।
- x. याचिकाकर्ताओं के जांच की अवधि के बाद के क्षति संबंधी आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि यहां तक कि यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात बढ़े हैं, फिर भी उनका याचिकाकर्ताओं के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं रहा है।
- xi. जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए क्षति मार्जिन नकारात्मक है। अतः, यहां तक कि यद्यपि आयात मात्रा में वृद्धि है, तथापि ये आयात याचिकाकर्ताओं के लिए क्षतिकारक नहीं हैं।
- xii. याचिकाकर्ताओं के बाजार हिस्से में गिरावट "अन्य" देशों से आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप है जो इस जांच के अध्यधीन नहीं है।
- xiii. यहां तक िक यदि संयुक्त राज्य अमेरिका पर शुल्क समग्र रूप से जारी रखे जाते हैं तो निर्यातकों को पाटन एवं क्षिति मार्जिन (जो भी कम हो) के आधार पर शुल्क की अलग-अलग दर दी जानी चाहिए। चूंकि वर्तमान मामला निर्णायक समीक्षा का है, अतः यथोचित परिवर्तनों सहित पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(3) के तहत पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 को शामिल करना भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, यहां तक कि यदि शुल्क पाटन अथवा क्षिति के बार-बार होने के आधार पर बढ़ाए जाते हैं तो निर्यातकों के लिए शुल्क क्षिति मार्जिन के अनुसार शून्य होने चाहिए।
- xiv. विचाराधीन उत्पाद एक रासायनिक उत्पाद है और यह अच्छी तरह से समझा जाता है कि 85-90 प्रतिशत का क्षमता उपयोग दर इष्टतम से ऊपर माना जाता है। इस प्रकार, भारत को निर्यात के लिए कोई क्षमता उपयोग करने हेतु बेकार नहीं रखी गई है।
- xv. यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने स्वयं ही विश्व व्यापार एटलस के आंकड़ों का प्रयोग क्यों नहीं किया।
- xvi. याचिकाकर्ताओं द्वारा 14.6.2019 को दायर आंकड़ों का स्रोत नहीं दिया गया है तािक उनके प्राधिकार का निष्कर्ष निकाला जा सके। इन निर्यातों की सहशर्ते (चाहे सीआईएफ, एफओबी या कोई अन्य हो) उपर्युक्त दायर सूचना में कहीं भी नहीं दर्शाए गए हैं। दिए गए आंकड़े छः अंकों के स्तर पर व्यापक एचएस कोड शीर्षों के आधार पर चुने गए प्रतीत होते हैं जिनसे यह स्पष्ट नहीं है कि गैर विचाराधीन उत्पाद के ब्यौरे अलग करने के लिए आंकड़े कैसे छापे गए हैं। इस प्रकार, स्पष्टता के अभाव में इन आंकड़ों के रद्द किया जाना चाहिए।
- xvii. कीमत आकर्षकता विश्लेषण वर्तमान समीक्षा जांच में "अनिवार्य तथ्य" बनते हैं जिनसे उन्हें एक अगोपनीय स्वरूप में प्रकट किया जाना चाहिए। इन्हें प्रकट न करना नियम 16 तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में है।
- xviii. प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि भारत में 30-40 प्रतिशत मांग संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्पादकों से क्षितिकारक आयातों से पूरी की जा सकती है जो कि जांच की अविध के आंकड़ों के अनुसार है और जांच की अविध के बाद की अविध के लिए यह रेंज 70-80 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। तथापि, जिस कीमत पर संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्पादक/निर्यातक भारत में बिक्री कर रहे हैं, वे स्पष्ट रूप से जांच की अविध तथा जांच की अविध के बाद की अविध के लिए याचिकाकर्ताओं की क्षित रहित कीमत से अधिक है।

- xix. कीमत आकर्षकता संभावना पर विचार किए जाने के लिए मात्र एक मानदंड है। संभावना के मानदंडों का एक अनुकूल दृष्टिकोण लिए जाने की आवश्यकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जांच की अवधि के बाद में भारत को व्यापार किया। तथापि, अपनी कीमत बढ़ाई जो कि क्षति रहित है, इस प्रकार यहां तक कि यदि भारत को निर्यात किए जाते हैं तो वे क्षति रहित कीमत पर होंगे। भारत में निर्यातों में वृद्धि दूसरे देशों को घटते हुए निर्यातों के परिणामस्वरूप आई जहां कीमतें भारत में कीमत से कम थीं।
- xx. निर्यातकों को केवल तभी अपना बाजार बदलने से लाभ होगा यदि वे अधिक कीमत पर भारत में उत्पाद की बिक्री कर सकें।
- xxi. संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से चिरस्थायी शुल्कों का संभावना के कारकों पर कोई प्रभाव नहीं है।
- xxii. याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित अनुबंध में भी यह उल्लेख है कि "पीवीसी के लिए देखा गया प्रभाव सीमित" और यह कि "चीन के प्रशुल्कों का प्रभाव पीवीसी के लिए सीमित होगा, यहां तक कि यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के लिए प्रमुख पीवीसी निर्यातक है।" इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका-चीन के प्रशुल्कों का पीवीसी व्यापार पर प्रमुख प्रभाव नहीं था।
- xxiii. मेसर्ज ईएलपी ने दिनांक 9.7.2019 के पत्र द्वारा बताया है कि चूंकि केन्द्रीय बजट 2019-20 के अनुसार विचाराधीन उत्पाद पर बीसीडी की पूर्व-बजट प्रभावी दर (3904 और उसके अंतर्गत और 8 अंकीय वर्गीकरण) 7.5 से बढा कर 10% कर दी गई है, निर्दिष्ट प्राधिकारी को क्षति मार्जिन का निर्धारण करने और ऐसी संभावनाएं होने के समय 2.5% की बढी हुई बीसीडी के संदर्भ में पहुंच मूल्य को संशोधित करना चाहिए।

101. मैसर्स विनाइथाई पब्लिक कं. लि., थाइलैंड जिनका प्रतिनिधित्व मैसर्स सीतारमण एंड एसोसिएट्स द्वारा किया गया

- पैरा 46 की प्रथम पंक्ति में एक टाइप है (सामान्य मूल्य के संबंध में), जिसमें एक ग्रेड 261 के बजाए ग्रेड 201 उल्लिखित किया गया है जिसे सही किया जा सकता है।
- ii. "बाजार आकर्षकता" विश्लेषण से संबंधित परिकलनों के संबंध में संगत आंकड़े, प्राधिकारी द्वारा यूरोपीय संघ, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ताइवान, जापान और मलेशिया के संबंध में जांच शुरू न करने के लिए पाए गए "अपर्याप्त औचित्य" के ब्यौरे इस टिप्पणी का समर्थन करने वाले आंकड़े कि संबद्ध देशों के पास "स्वतंत्र निपटान योग्य क्षमताएं" है, इस टिप्पणी का समर्थन करने वाले ब्यौरे कि चीन और अमेरिका ने एक-दूसरे पर 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त प्रशुल्क लगाया है, प्रकट नहीं किए गए हैं।
- iii. प्राधिकारी को सिद्धांत को प्रकट नहीं करना है परंतु उनके लिए यह भी अपेक्षित है कि वे कीमत आकर्षक परिकलन प्रदान करें (संबंधित पक्षकारों को उनके आंकड़ों के संबंध में गोपनीय तरीके से और अन्य पक्षकारों के आंकड़ों के संबंध में अगोपनीय तरीके से)। "बाजार आकर्षकता" विश्लेषण के लिए विस्तृत परिकलन प्रकट न करना पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के प्रावधानों के विरुद्ध है।
- iv. जांच की अवधि के दौरान थाइलैंड से आयात कुल मांग के केवल 7 प्रतिशत थे और जांच की अवधि के बाद के दौरान वह कुल मांग का 4 प्रतिशत थे। प्राधिकारी की यह टिप्पणी कि थाइलैंड से क्षतिकारक आयात कुल मांग के 0.10 प्रतिशत हैं (जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद दोनों), यह दर्शाएगा कि थाइलैंड से लगभग सभी आयात क्षतिकारक हैं। यह त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि थाइलैंड से प्रमुख निर्यातक तथा समग्र रूप से देश के लिए क्षति मार्जिन नकारात्मक है।
- प्राधिकारी ने इस बात की जांच नहीं की है कि क्या कम कीमत पर सभी निर्यात भारत को भेजे जाएंगे।
 इसका कोई कारण नहीं है कि कोई देश मात्रा को कम कीमत वाले देश से दूसरे कम कीमत वाले देश में क्यों
 ले जाएगा। अन्य देशों से भारत को मात्राओं के परिवर्तन के लिए रुझान कीमत पर ही निर्भर नहीं होंगे।
- vi. यह मानना उपयुक्त नहीं है कि दूसरे देशों को निर्यातों की पूरी मात्रा जो एनआईपी से कम है, उन देशों से भारत को भेजी जाएंगी।
- vii. व्यापार परिवर्तन विश्लेषण अथवा बाजार आकर्षकता विश्लेषण में कम से कम निम्नलिखित कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिएः

- क. उन निर्यात बाजारों से अतिरिक्त क्षमता सहित क्षमता जहां परिवर्तन की संभावना मानी जा रही है।
- ख. बाजार/बाजारों में उत्पाद के लिए मांग में संभावित वृद्धि सहित मांग।
- ग. संबंधित बाजार/बाजारों में उत्पाद के कुल आयातों के प्रतिशत के रूप में कम कीमत वाले आयात।
- घ. इस बात को देखते हुए कि दोनों बाजारों में कीमतें कम हैं, मौजूदा तीसरे देश के बाजार की तुलना में भारतीय बाजार अधिक आकर्षक क्यों है।
- viii. प्राधिकारी केवल यह उल्लेख नहीं कर सकते कि कुछ देशों जो थाइलैंड के समान ही रखे गए हैं, के विरुद्ध मामले शुरू न करने के लिए वास्तविक कारण दिए बिना अपर्याप्त औचित्य था।
- ix. यह ज्ञात नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन द्वारा अतिरिक्त सीमा प्रशुल्क लगाए जाने में क्या संबद्ध उत्पाद शामिल है अथवा नहीं।
- प्रेसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता की न्यूनतम संभावित निवल बिक्री वसूली (किए गए प्रकटन विवरण के आधार पर निकाली गई) अर्थात 66.7 रुपए प्रति किलोग्राम, जांच की अविध के दौरान उच्चतम संभावित एनआईपी (63.5 रुपए प्रति किलोग्राम) की तुलना में 5 प्रतिशत तक अधिक थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता निर्माण एवं बिक्री की अपनी लागत से काफी अधिक कमा रहे थे और इसीलिए उन्हें कोई क्षति नहीं हो रही थी।
- xi. जांच की अवधि के बाद के दौरान स्थिति बेहतर हो जाती है क्योंकि याचिकाकर्ता की न्यूनतम संभावित बिक्री वसूली (69.4 रुपए प्रति किलोग्राम) जांच की अवधि के बाद के दौरान उच्चतम संभावित एनआईपी (62.5 रुपए प्रति किलोग्राम) की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत तक अधिक थी।
- xii. थाइलैंड के लिए कम कीमत पर बिक्री अथवा क्षति मार्जिन जांच की अवधि के दौरान एवं जांच की अवधि के बाद नकारात्मक था।
- xiii. कुल 70 प्रतिशत भारतीय उद्योग से कोई समर्थन नहीं है जो कि मूल जांच में भाग ले रहे थे।
- xiv. चीन जन. गण. से सीमलेस ट्यूबों और पाइपों में वर्तमान मामले में लागू है, घरेलू उद्योग के पास समर्थकों से प्राप्त किसी सूचना के अभाव में कुल 27 प्रतिशत भारतीय उत्पादन ही था, क्षति एवं कारणात्मक संपर्क विश्लेषण प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जा सका।
- xv. यह स्पष्ट नहीं है कि प्रकटन विवरण में उल्लिखित 62 मी. टन क्या जांच की अवधि अथवा पूरी क्षित अवधि से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, मात्रा को नगण्य मानते हुए इस पर विचार किया जाए कि चूंकि आवेदक इस तथ्य से अवगत थे कि वे पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के लिए याचिका दायर करेंगे, यह संभव है कि एक्सियाल श्रीराम जांच की अवधि के दौरान आयातों को रोक दे अथवा प्रतिबंधित कर दे। प्रकटन विवरण से यह पता नहीं चलता कि क्या निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एक्सियाल श्रीराम द्वारा किए गए आयातों की जांच की अवधि के बाद की प्रवृत्ति की जांच की अथवा नहीं की।
- xvi. प्राधिकारी ने इस संबंध में स्पष्ट नहीं किया है कि संबंध में "तकनीकी प्रकृति" शब्द का क्या अर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने इस तथ्य के संबंध में आगे कोई जांच नहीं की है कि क्या दो कंपनियों के बीच संबंध से उत्पादकों ने गैर संबद्ध उत्पादकों से असंगत रूप से व्यवहार किया है।
- xvii. एक उचित विश्लेषण के लिए मात्रात्मक एवं कीमत प्रभाव तथा आयातों के बाजार हिस्से पर विचार करते समय श्रीराम एक्सियाल द्वारा किए गए सभी आयातों को हटा दिया जाना चाहिए।
- xviii. प्राधिकारी द्वारा निर्णायक समीक्षा स्वविवेक के आधार पर शुरू नहीं की गई थी, इसके बजाए उन घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर शुरू की गई है जो नियम 2(ख) के अभिप्राय से और इस न्यायिक तथ्य का निर्णय लेने में प्राधिकारी के संबंध में कि आवेदक जांच की शुरूआत के चरण में प्रमुख अनुपात है, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर शुरू की गई है। इस प्रकार, अंतिम जांच परिणाम जारी करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्या आवेदकों का वास्तव में प्रमुख अनुपात है।

- xix. उत्तरदाता इस निर्धारण से मतभेद रखते हैं कि क्षति के बार-बार होने की संभावना की जांच करने में निर्यातकों की सूचना अधिक व्यावहारिक है। घरेलू उद्योग को क्षति के बार-बार होने की संभावना की जांच करने के लिए भारत में पीवीसी के पूरे घरेलू उद्योग के मौजूदा एवं पूर्वानुमानित निष्पादन की जांच करना व्यावहारिक है।
- xx. दूसरे देशों से मात्रा, जिनसे याचिकाकर्ताओं पर कोई प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव, यदि कोई है, पड़ रहा है।
- xxi. जांच की अविध और जांच की अविध के बाद की अविध के बीच विनथाई द्वारा भारत को निर्यातों में भारी गिरावट आई है। भारत को निर्यात जांच की अविध के बाद की अविध के दौरान लगभग रुक गए हैं। जांच की अविध के बाद की अविध के दौरान भारत को कारखानागत निर्यात कीमत जांच की अविध में कीमत से अिधक है, पाटन की कोई संभावना नहीं है।
- xxii. विनथाई का अन्य देशों में काफी स्थापित बाजार है, जबिक भारत एक बहुत ही छोटा बाजार है। यह छोटा भारतीय बाजार जांच की अवधि के बाद और भी अधिक सिकुड़ जाता है क्योंकि भारत को निर्यात जांच की अवधि की तुलना में लगभग 91 प्रतिशत तक कम हो गए, इस प्रकार भारतीय बाजार आकर्षक नहीं है।
- xxiii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों का व्यापक विश्लेषण किया है। तथापि, यह निर्धारित करने में समान कार्य नहीं किया गया है कि क्या याचिकाकर्ताओं को खुद ही कोई क्षति होने की संभावना है अथवा नहीं। तथापि, भारतीय उद्योग में अनुमानों तथा आगे के विकासों की जांच नहीं की गई है। जब संबद्ध देशों से व्यापार परिवर्तन केवल प्रतिभागी उत्पादकों तथा निर्यातकों तक सीमित नहीं हैं तो फिर वही मानक भारतीय उद्योग के मामले में भी लागू होना चाहिए।
- xxiv. प्राधिकारी के पास प्रत्येक भारतीय उद्योग के उत्पादकों के संबंध में उनके उत्पादन, बिक्री और वार्षिक लेखों के संबंध में सूचना देने हेतु उत्पाद शुल्क जीएसटी आयुक्तालय/एमसीए से अपेक्षित अनुरोध करने के पर्याप्त अधिकार हैं। इसके अतिरिक्त, संगत नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 में दिए गए प्रावधान किसी आरंभिक सीमा को पार करने के बाद कंपनियों से अपेक्षा होती है कि वे कारपोरेट कार्य मंत्रालय में लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टें दायर करें। चूंकि, ये रिपोर्टें किसी सांविधिक निकाय में दायर की जाती हैं, अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपर्युक्त आंकड़ों के लिए अनुरोध करने और उनकी जांच करने के पर्याप्त अधिकार हैं।
- xxv. डीसीएम श्रीराम की जहां तक क्लोर-विनाइल क्षेत्र का संबंध है, जांच की अवधि के बाद की अवधि में लाभप्रदता है क्योंकि वर्ष दर वर्ष आधार पर उनका लाभ ही नहीं बढ़ा बल्कि त्रैमासिक आधार पर भी लाभ बढ़ा।
- xxvi. केमप्लास्ट सनमार ने हाल ही में (जांच की अवधि के बाद) अपने कुड्डालोर स्थित नए संयंत्र में परीक्षण उत्पादन शरू किया जिसकी पीवीसी परियोजना की 170,000 टन क्षमता है।
- xxvii. आरआईएल ने हमेशा से अधिक पीवीसी का तिमाही उत्पादन हासिल किया और वह भी एक तिमाही में लगभग 190 किलोटन है जो कि पूरे वर्ष के लिए सभी याचिकाकर्ता कंपनियों को एक साथ रखकर उनके द्वारा हासिल कुल उत्पादन का लगभग 45 प्रतिशत है।
- xxviii. आरआईएल द्वारा एक तिमाही में प्राप्त उत्पादन जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के बाद को एक साथ रखकर थाइलैंड से कुल आयातों से अधिक है। भारत में ही मौजूद इतने प्रभावी उत्पादक, जो कि लाभ भी कमा रहा है, के लिए यह नोट करना आश्चर्यजनक है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी व्यापार परिवर्तन निर्धारित करने के लिए और याचिकाकर्ताओं को परिणामस्वरूप संभावित क्षति के निर्धारण के लिए संबद्ध देशों से निर्यातों की आनुपातिक रूप से आंशिक प्रतिशतता के रूप में व्यापक जांच करना चाहते हैं।

102. मैसर्स इटोचू (थाइलैंड) लि. और मैसर्स इटोचू प्लास्टिक्स पीटीई. लि., जिनका मैसर्स डब्ल्यूटीसी कंसल्टेंट्स द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया

प्राधिकारी ने प्रतिभागी सहयोगी निर्यातकों को पाटन मार्जिन और क्षिति मार्जिन की पृथक दर नहीं दी है।
 यद्यपि, प्रश्नावली का उत्तर निवल निर्यात कीमत (एनईपी) के परिकलन के लिए दोनों निर्यातकों/उत्पादकों
 द्वारा दायर किया जाना अपेक्षित है। निर्यातकों के हित को ध्यान में नहीं रखा जाता है जो उन्हें प्रश्नावली का

उत्तर दायर करने नहीं देता। निर्यातकों के हित को ध्यान में रखते हुए उत्पादक विशिष्ट परिपाटी में संशोधन/परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।

103. मैसर्स थाई प्लास्टिक एंड केमिकल्स पीएलसी (उत्पादक); मैसर्स एससीजी प्लास्टिक कं. लि. (संबद्घ निर्यातक) और मैसर्स एससीजी परफॉर्मेंस केमिकल कं. लि. (संबद्घ निर्यातक), थाइलैंड

- i. एक गैर इरादतन टंकण की त्रुटि है और यह कि कारखानागत सामान्य मूल्य (xxx) पढ़ा जाना चाहिए न कि टीपीसी के लिए थाई बहट प्रति मी. टन में।
- ii. भत्तों को अस्वीकार करने पर सहमित नहीं हुई है । इसमें प्रशिक्षण से संबंधित कोई खर्च शामिल नहीं है। विदेशी विनिमय लाभ के मुद्दे पर (वाणिज्यिक रुप से संवेदनशील और यह एस सी जी प्लास्टिक्स कंपनी लि. और एस सी जी परफारमेंस कंपनी लि.) की विपणन नीति को दर्शाता है। निर्यात में छूट शुल्क वापसी प्रणाली को दर्शाता है और इसकी प्रतिपूर्ति निर्यात पर की जाती है । अत: इस छूट को निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करने के लिए निर्यात की कीमत में जोड़ा जाना चाहिए और कटौती नहीं किया जाना चाहिए।
- iii. टीपीसी इस मामले में निर्यात कारखानागत कीमतों का पुनर्समाधान करने में असमर्थ है कि यदि हम गोपनीय प्रकटन में भेजी गई विस्तृत तालिकाओं को आधार बनाते हैं।
- iv. टीपीसी की नीति हमारे प्रमुख बाजारों में मौजूद रहने की है जो उनके निर्यातों को दूसरे बाजार से भारत में भेजने का संकेत देता है, जैसा कि 2014 से वर्तमान तक बिक्री की मात्रा से देखा जा सकता है जो यह दर्शाता है कि तीसरे बाजारों को उनके निर्यात 2018 की अवधि के बाद में आनुपातिक रूप से बहुत कम वृद्धि के साथ इन वर्षों में स्थिर रहे हैं। वे सामान्य रूप से भारत को अधिक निर्यात करने के लिए अन्य देशों में ग्राहकों का त्याग नहीं करेंगे।
- जांच की अविध के बाद के निर्यातों में नकारात्मक क्षिति मार्जिन के साथ गिरावट आई है। थाइलैंड के विरूद्ध पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि कोई भी मानदंड यह नहीं दर्शाता कि थाइलैंड के निर्यातों से पाटन एवं क्षिति होने की संभावना मौजूद है।
- 104. मैसर्स तियानजिन एलजी बोहाई केमिकल कं. लि. (उत्पादक), मैसर्स तियानेंग केमिकल कं. लि. (उत्पादक), मैसर्स जिनजियांग तियानये (ग्रुप) कं. लि. (संबद्ध व्यापारी), मैसर्स तियानजिन डगु केमिकल कं. लि. (उत्पादक), मैसर्स बोहाई केमिकल (एचके) लिमिटेड (संबद्ध व्यापारी), मैसर्स जिनजियांग शेंक्सियांग क्लोर-अलकाली कं. लि. (उत्पादक) और मैसर्स जिनजियांग झोंगताई केमिकल कं. लि. (संबद्ध व्यापारी) जिनका एलकेएस द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया
 - i. प्राधिकारी ने बोहाई केमिकल (एचके) लिमिटेड और जिनजियांग शेंक्सियांग क्लोर-अलकाली कं. लि. के नाम नोट किए हैं और वे गलत नोट किए गए हैं।
 - ii. यदि प्राधिकारी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करते हैं तो प्राधिकारी को कमतर शुल्क नियम अपनाना चाहिए और वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में निर्धारित किए गए अनुसार कमतर पाटन एवं क्षति मार्जिन के आधार पर शुल्क जारी रखने की सिफारिश करनी चाहिए।
 - iii. प्रथम निर्णायक समीक्षा शुल्कों में किए गए निर्धारणों के आधार पर ऊपर की ओर संशोधन किए गए थे। इस प्रकार, वर्तमान जांच में प्राधिकारी उन्हीं शुल्कों को जारी नहीं रख सकते।
 - iv. वर्तमान समीक्षा जांच में प्रतिभागी उत्पादक तथा पूर्व निर्णायक समीक्षा में उत्पादक अलग-अलग हैं और उन पक्षकारों को अलग मार्जिन दिया जाना चाहिए जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग लिया है।
 - v. पूर्व निर्णायक समीक्षा जांच अधिसूचना में क्रम सं. 15 और 16 पर दिए गए नामों वाले पक्षकारों ने नाम में परिवर्तन कर दिया है और वर्तमान जांच में भी भाग लिया है। पूर्व की सीमा शुल्क अधिसूचना जारी रखने से पूर्व निर्णायक समीक्षा जांच तथा वर्तमान जांच में सक्रिय प्रतिभागिता के बावजूद शुल्क की अविशष्ट दर के लिए प्रतिभागी बाध्य हो जाएंगे।
 - vi. डीसीएम श्रीराम का एक संबंधित आयातक होने के बावजूद, जो कि थाइलैंड और अन्य देशों से तथा उस संबंधित उत्पादक से आयात कर रहा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से बड़ा निर्यातक है तथा जिसके सहयोग

- से उसका संबंधित आयातक है, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबंधित पक्षकारों द्वारा सभी आयातों और निर्यातों की उपेक्षा की है और याचिकाकर्ता को घरेलू उद्योग का "पात्र" घटक माना है।
- vii. यदि डीसीएम श्रीराम लिमिटेड को पात्र घरेलू उत्पादक से अलग किया जाता है तो शेष उत्पादक 25 प्रतिशत आधार सिद्ध करने में समर्थ नहीं होंगे जिसके कारण डीसीएम श्रीराम को घरेलू उद्योग के क्षेत्र में शामिल किया गया है।
- viii. अनुकूल घरेलू उद्योग की पहचान क्षति का मूल्यांकन करने चाहे सतत हो अथवा बार-बार होने की संभावना हो, के लिए महत्वपूर्ण आरंभिक बिन्दु है।
- ix. मूल जांच में प्राधिकारी ने नोट किया था कि आरआईएल एक प्रमुख उत्पादक है और उसने क्षिति मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए अपने आंकड़ों को शामिल करने पर जोर दिया था जिन्हें उसे बाद में दायर करना था। उसने बाद की समीक्षा जांचों में भी भाग लिया, इस प्रकार सतत जांच में निवेश के इस अचानक अभाव का प्राधिकारी द्वारा विचार किए जाने का औचित्य बनता है।
- x. आरआईएल सबसे दक्ष घरेलू उत्पादकों में है और आरआईएल के आंकड़ों को शामिल करने से एनआईपी काफी प्रभावित होगी। इस प्रकार, उसकी प्रतिभागिता महत्वपूर्ण है।
- xi. निर्णायक समीक्षा के मामलों में भी घरेलू उद्योग की प्रतिभागिता निर्णायक समीक्षा के स्तर पर संगत हो जाती है क्योंकि निर्धारित एनआईपी संभावित विश्लेषण के लिए प्रयुक्त की जा रही है जो कि अदक्ष घरेलू उत्पादकों के आधार पर है।
- xii. यह संभव है कि जिन कारणों से अन्य देशों को देखते हुए जांच शुरू नहीं की गई थी, वे संबद्ध देशों पर समान रूप से लागू हो सकते हैं, परंतु उन अन्य देशों को शामिल न करने के लिए प्राधिकारी द्वारा कारणों को प्रकट न करने के मद्देनजर यह संभव नहीं है कि जिन पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा है और जिनका आयातों की मात्रा में अधिक हिस्सा है।
- xiii. प्राधिकारी ने संचयन के संबंध में उल्लेख किया है कि तीन देशों के लिए पृथक सूचना प्रत्येक देश के लिए किए गए पृथक संभावना विश्लेषण के साथ रिकार्ड में है, परंतु निरंतर क्षति के मूल्यांकन के संदर्भ में उसे हल करने में पूरी तरह विफल रहे।
- xiv. प्राधिकारी ने कोरियाई उत्पादकों से सूचना के लिए किसी अनुरोध के बिना कोरिया को एक प्रतिनिधि देश स्वीकार करने से संबंधित उत्तरदाता से टिप्पणी के लिए कोई अनुरोध किए बिना तथा पूर्णतः सामान्य मूल्य पर विचार करने के लिए कोई अवसर दिए बिना चीन जन. गण. से सामान्य मूल्य के प्रयोजन के लिए "व्यवहार्य विकल्प" होने के लिए कोरिया से कीमतों पर विचार किया है और इन सबके बावजूद उन्होंने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर वास्तव में सामान्य मूल्य निर्मित किया है।
- xv. प्राधिकारी को उत्तरदाता के पूर्वाग्रह सामान्य मूल्य के निर्माण पर रोक लगानी है और स्पष्ट करना है कि लागत का कौन सा घटक याचिकाकर्ताओं से संबंधित है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से किन-किन को लिया गया है।
- xvi. पाटनरोधी शुल्क जारी रखना पांच वर्षों के बाद शुल्क की समाप्ति की शुल्क की अन्यथा अधिदेशित समाप्ति में एक "अपवाद" है जैसा कि कंपनी से कुछ क्षरण – प्रतिरोधक कार्बन स्टील फ्लैट उत्पादों पर संयुक्त राज्य अमेरिका – कार्बन प्रतिकारी शुल्क में डब्ल्यूटीओ एबी रिपोर्ट में नोट किया गया है।
- xvii. प्राधिकारी को या तो जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर विश्वास करना चाहिए या आंकड़ों को पूरी तरह अलग कर देना चाहिए। यह आंकड़ा लेने और चुनने का कार्य अस्वीकार्य है। "थोड़ा से कम" जैसे शब्दों का प्रयोग पक्षपात दर्शाता है और उससे अलग रहना चाहिए।
- xviii. प्राधिकारी को कीमत कटौती और क्षति मार्जिन के लिए पाटनरोधी शुल्क जोड़ने के बाद आयात कीमतों की तुलना करनी चाहिए। जब पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देशों के पहुँच मूल्य में जोड़ा जाएगा तो यह सिद्ध हो जाता है कि संबद्ध सामानों का कीमत स्तर अन्य सभी स्रोतों से आयातों के कीमत स्तरों से तुलनीय है और यहां तक कि याचिकाकर्ताओं की एनआईपी से तुलनीय/अधिक है।

- xix. संयुक्त राज्य अमेरिका और थाइलैंड के संबंध में क्षति मार्जिन जांच की अवधि में 63.19 रुपए के कीमत स्तरों पर नकारात्मक है। अतः, यह स्पष्ट है कि 61.09 रुपए के कीमत स्तर पर चीन से आयातों का लगभग 1 प्रतिशत क्षति मार्जिन है। चीन से आयातों के कारण वर्तमान में कोई क्षति अथवा क्षति की संभावना नहीं है।
- xx. प्राधिकारी को क्षति रहित कीमत के परिकलन का सिद्धांत प्रकट करना चाहिए और साथ ही उस पर विचार करना चाहिए।
- xxi. कुल मांग में चीन का हिस्सा 2014-15 में 12.7 प्रतिशत था और जांच की अवधि में वह 7.41 प्रतिशत तक कम हो गया तथा उसके बाद जांच की अवधि के बाद वह 4.84 प्रतिशत तक कम हो गया। इसे प्राधिकारी द्वारा "काफी" नहीं माना जा सकता। विशेष रूप से उस समय जब भारत मांग में गैर संबद्ध देशों का हिस्सा जांच की अवधि के बाद 43.15 प्रतिशत हो।
- xxii. आईएचएस रिपोर्ट के आधार पर आंकड़े गलत हैं क्योंकि थाइलेंड में संबद्ध सामानों के पूर्ण उत्पादन के लिए उत्पादकों ने भाग लिया और सिद्ध किया है कि कोई अधिशेष क्षमता नहीं है। इस प्रकार, वह अन्य देशों के लिए गलत होने की संभावना है।
- xxiii. प्राधिकारी ने भारतीय बाजार की "कीमत आकर्षकता" पर विचार करने के लिए नए सिद्धांत को अपनाने का आधार प्रकट नहीं किया है।
- xxiv. यह विवरण कि "प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा दिये गये व्यापार मानचित्र के आंकड़े विभिन्न देशों को वैश्विक निर्यात के मासिक आंकड़े हैं, ने घरेलू उद्योग के आंकड़ों को उपयुक्त रूप से अपनाने पर विचार करने के लिए जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के बाद की अवधि के आधार पर कुल रूप में डीजीटीआर के पास उपलब्ध डब्ल्यूटीए आंकड़ों के साथ घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए व्यापार मानचित्र आंकड़ों को वैध बनाया है।", पूर्णतः स्पष्ट नहीं है।
- xxv. अलग-अलग लेन-देन जो उनके "कम" मूल्य के लिए उठाए और चुने गए हैं, कम ऋण अवधियों, संबंधित कंपनी के लेन-देन, उत्पादकों/निर्यातकों तथा तीसरे पक्षकार आयातक के बीच विशिष्ट व्यवस्था के भाग के अध्यधीन दीर्घावधि संविदा का भाग बनने जैसे विशिष्ट संविदागत कारणों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में विशेष लेन-देन की कीमतों के पक्ष में औसत कीमतों की उपेक्षा करना औचित्य के बिना प्रतीत होता है।
- xxvi. चीन द्वारा आयातों के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ये अतिरिक्त प्रशुल्क लगाने से भारत को चीन से कोई बढ़े हुए आयात नहीं हुए।
- xxvii. यद्यपि, कीमत आकर्षकता के लिए विभिन्न सिद्धांत अपनाने का प्रस्ताव है, तथापि उससे संबंधित कोई आंकड़े अथवा तथ्य नहीं दिए गए हैं। सिद्धांत का प्रावधान एक अनिवार्य तथ्य है, परंतु इस संबंध में प्राधिकारी के समक्ष आंकड़े तथा प्रवृत्तियां भी अनिवार्य तथ्य हैं।

ञ. घरेलू उद्योग की टिप्पणियों का सार

- 105. i. संबंधित दृष्टि से आयात में 2015-16 तक गिरावट आई और उसके बाद जांच की अवधि में उनमें वृद्धि हुई। आयातों ने जांच की अवधि के बाद कुछ गिरावट दर्शाई क्योंकि अन्य स्नोतों से आयातों में वृद्धि हुई तथापि, वह काफी रही। इसके अतिरिक्त, संबंधित दृष्टि से आयातों में 2015-16 तक गिरावट आई और उसके बाद जांच की अवधि में वृद्धि हुई।
 - ii. लागू पाटनरोधी शुल्क से घरेलू बाजार में कीमत न्यूनीकरण अथवा ह्रास रुका है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद में काफी कीमत कटौती पर विचार करते हुए यह सिद्ध है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने से बाजार में काफी कीमत न्यूनीकरण/ह्रास होगा।
 - iii. विचाराधीन उत्पाद में 500 रुपए प्रति मी. टन का छोटा सा अंतर भी इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि उपभोक्ता द्वारा 500 रुपए प्रति मी. टन के क्षेत्र में कीमत अंतर पाया जाता है तो उत्पादक अपना आदेश खो सकता है।

- iv. लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय ने क्षति की अवधि में वृद्धि दर्शाई है। घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ का वर्तमान स्तर उस स्थिति में है जब विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लागू है।
- यदि पिछले पांच वर्षों पर विचार किया जाए तो यह देखा जाएगा कि घरेलू उद्योग की निवेश पर आय उस स्थिति में भी प्राधिकारी द्वारा माने गए उपयुक्त स्तरों से काफी कम है जब प्राधिकारी निवेशों के निवल वर्तमान मूल्य पर निवेश पर आय निर्धारित करते हैं (पिछले दो वर्षों को छोड़कर)।
- vi. जांच से यह बात सामने आई है कि क्षितिकारक निर्यातों जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में भेजे जाने की संभावना है, की प्रतिशतता घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए प्रतिशत से कहीं अधिक है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने उल्लेख किया है कि कीमत आकर्षकता विश्लेषण बढ़ाया हुआ नहीं है और केवल पारंपरिक अनुमान ही आकर्षकता का मूल्यांकन करने के लिए लागू किए गए हैं। यह दर्शाता है कि वास्तविक मात्रा काफी अधिक होनी चाहिए जो शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में क्षिति का खतरा पैदा करेगी।
- vii. संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यातों पर चीन और तुर्की में पाटनरोधी शुल्क लग रहा है। पाटनरोधी शुल्क 15 से अधिक वर्षों से लागू रहे हैं। शुल्क पाटन और क्षति की संभावना के आधार पर बढ़ाए गए हैं।
- viii. पाकिस्तान ने थाइलैंड पर पाटनरोधी शुल्क लगाए हैं। पाकिस्तान ने भारत को निर्यातों की मात्रा की तुलना में आयातों की काफी कम मात्रा पर पाटनरोधी शुल्क लगाए हैं।
- ix. चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक-दूसरे पर 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त सीमा प्रशुल्क लगाया है जिसका दोनों बाजारों में पीवीसी के आयातों पर प्रभाव है।
- x. अप्रैल, 2008 से मार्च, 2018 तक (अर्थात 120 माह) माह दर माह आयात कीमतों पर विचार करते हुए संबद्ध देशों की कीमतों का व्यवहार यह दर्शाता है कि कुल 120 माह में से चीनी कीमतें 28 माह में न्यूनतम थीं जबिक संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात कीमतें 59 माह में कम थीं और थाइलैंड से आयात कीमत 38 माह में कम थी।
- xi. संबद्ध देश इस समय भारतीय उद्योग की घरेलू कीमतों से कम कीमतों पर भारत को अपना अधिकतर निर्यात कर रहे हैं।
- xii. चूंिक, घरेलू उद्योग को क्षिति घरेलू उद्योग को क्षिति के बार-बार होने की संभावना के आधार पर है, अतः शुल्क की मात्रा में कोई संशोधन करना उपयुक्त नहीं होगा। केवल क्षिति मार्जिन हो सकता है जब कोई क्षिति हो। यदि कोई क्षिति नहीं है तो कोई क्षिति मार्जिन नहीं हो सकता। मौजूदा पाटनरोधी शुल्क बढ़ाना भी धारा 9क(5) के अभिप्राय से पूर्णतः अनुमत्य है।
- xiii. पाटनरोधी शुल्क केवल पाटनरोधी शुल्क की मात्रा (शुल्क की निर्धारित मात्रा) में लगाया जा सकता है जिसे अमेरिकी डॉलर/मी. टन में शुल्क के रूप में व्यक्त किया जाए।

ट. प्राधिकारी द्वारा जांच

106. क. प्राधिकारी मेसर्ज श्रीराम अक्सियल द्वारा आयातों पर किए गए निवेदनों की जांच करने के बाद पुन: निवेदन करते हैं कि उनके द्वारा किए गए आयात अत्यंत नगण्य हैं, जिसके कारण मेसर्ज डी.सी.एम. श्रीराम लिमिटेड को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। किसी भी अन्य भारतीय उत्पादक ने याचिका का उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी का मानना है कि याचिकादाता कंपनियां आधार की अवसीमा को पूरा करती हैं। मेसर्ज आरआईएल और मेसर्ज फिनोलेक्स द्वारा जांच में भाग नहीं लेने को जांच अवधि में आर्थिक क्षति होने और जांच अवधि पश्चात संभावित विश्लेषण दोनों के लिए क्षति का मूल्यांकन करने के लिए बाध्यकारी कारक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि क्षति के मूल्यांकन में मात्रा प्रभाव और कीमत प्रभाव दोनों पर विचार करना अपेक्षित होता है। मेसर्ज आरआईएल और मेसर्ज फिनोलेक्स द्वारा जांच में भाग नहीं लेने से मात्रा प्रभाव के रूप में भारत को तृतीय देश के निर्यातों के विचलन की संभावना पर प्रभाव नहीं पडता है। प्राधिकारी याचिकादाता घरेलू उद्योग द्वारा प्रारंभ में याचिका के साथ जांच अवधि पश्चात के आंकडों को प्रस्तुत नहीं किए जाने और बाद में दिनांक 25.02.2019 को उन्हें प्रस्तुत किए जाने के संबंध में दिए गए निवेदनों को नोट करते हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उत्पादकों/निर्यातकों ने भी वही आंकडे, मौखिक सुनवाई होने के बाद प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण की संभावना पर विचार शुरू करने के समय संबद्ध वस्तुओं पर मूल सीमा-शुल्क में हाल ही में

हुई वृद्धि में प्रकटन कारक पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद जुलाई, 2019 में कुछ पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार किया है और उनका निदान किया है।

ख.

- (i) प्राधिकारी मेसर्जईटोचू (थाईलैंड) लिमिटेड और मेसर्ज ईटोचू प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर के निवेदनों को नोट करते हैं और उन्होंने यह माना है कि उत्पादक के लिए पाटन मार्जिन का मूल्यांकन करते समय उपरोक्त प्रयोज्यताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकडों पर विचार किया गया है। इस संबंध में प्राधिकारी उत्पादक विशिष्ट पाटन मार्जिन स्वीकृत करते समय हाल ही में अपनाई गई पद्धित को महत्व देते हैं, जिसे इस मामले में भी अपनाया गया है।
- (ii) प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्ज वेस्टलेक विनायल कंपनी एलपी (उत्पादक और निर्यातक) ने दावा किया है कि संबंधित क्रेताओं को उनकी बिक्रियों को गलत तरीके से अस्वीकृत किया गया है। पूर्ववर्ती अंतिम जांच परिणाम-1 में संबंधित और गैर-संबंधित दोनों प्रयोज्यताओं को की गई घरेलू बिक्रियों पर उनके लिए पाटन मार्जिन का मूल्यांकन करते समय विचार किया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में संबंधित और गैर-संबंधित प्रयोज्यताओं की कीमतों में व्यापक अंतर विद्यमान है और इसलिए वर्तमान मामले के तथ्य, अंतिम जांच परिणाम-1 के तथ्यों के समान नहीं हैं। चूंकि निर्यातक द्वारा इस संबंध में कोई यथोचित तर्क नहीं दिया गया है कि संबंधित क्रेताओं को को दी गई कीमतें निम्नतर हैं, प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन का मूल्यांकन करने के लिए गैर-संबंधित पक्षकारों को दी गई कीमतों पर विचार किया है क्योंकि इन कारोबारों पर निकटस्थ दूरी पर विचार किया जाता है। अंतरण कीमत के मुद्दे पर मेसर्ज वेस्टलेक विनायल कंपनी एलपी के निवदेनों के संबंध में प्राधिकारी ने कंपनी के समग्र लाभ प्रतिशत के आधार पर अंतरण कीमत का समायोजन किया है।
- (iii) प्राधिकारी कारखाना-गत निर्यात कीमत के परिकलन पर गलती होने के संबंध में मेसर्ज टीपीसी/एससीजी के निवेदनों को नोट करते हैं। प्राधिकारी ने उसकी पुन:जांच की है और एक संवर्धन के रूप में निर्यात छूट पर विचार किया है और न कि कटौती के रूप में तथा समस्त स्वीकृत समायोजनों पर उचित ढंग से विचार करने के बाद कारखाना-गत निर्यात कीमत का पुन:परिकलन किया है, जो कि ***भाट/मी.टन (*** डालर/मी.टन) बनती है। तदनुसार पुन:परिकलित किया गया पाटन मार्जिन ***% है। मेसर्ज टीपीसी/एससीजी द्वारा प्रस्तुत किए गए सामान्य मूल्य और कारखाना-गत निर्यात कीमत पर कुछ समायोजन स्वीकार्य नहीं किए जाने के संबंध में प्राधिकारी का मानना है कि जैसा कि गोपनीय प्रकटन में निर्दिष्ट किया गया है, सामान्य मूल्य और कारखाना-गत निर्यात कीमत को उचित ढंग से मूल्यांकन करने के लिए केवल उन्हीं समायोजनों पर विचार किया गया था, जिनके साक्ष्य और यथोचित तथ्य मौके पर जांच करने पर प्रस्तुत किए गए थे।
- (iv) प्राधिकारी ऐसे सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों को विशिष्ठ पृथक पाटन मार्जिन स्वीकृत करने के संबंध में किए गए निवेदनों को नोट करते हैं, जिन्होंने अब जांच में भाग लिया है और जिन्होंने जांच में पहले भाग नहींलिया था। पाटन के तथ्य को सिद्ध करने के लिए सहभागी उत्पादकों/निर्यातकों का पाटन मार्जिन का मूल्यांकन जांच अवधि के लिए किया गया है, जो कि मौजूदा उपाय को निरंतर जारी रखने पर विचार करने के एक अनिवार्य प्राचल है। प्राधिकारी का मानना है कि सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए संभावना की जांच सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों से उपलब्ध पृथक कारोबार-वार आंकडों के आधार पर की गई है और मौजूदा पाटन-रोधी शुल्कों को जारी रखने पर उचित रूप से विचार किया गया है।

ग.

(i) प्राधिकारी संभावित विश्लेषण पर विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को नोट करते हैं और उनका मानना है कि भारतीय बाजार के आकर्षक होने और पाटन-रोधी शुल्क को हटाने पर किस सीमा तक कारोबार नुकसान दायक होंगे, इन पर विचार करते हुए भारत से भिन्न देशों को निर्यातों के विपथन की सीमा का मूल्यांकन करने के लिए सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत कारोबार-वार आंकडों का उल्लेख गया है। इस कार्य-प्रणाली का उल्लेख प्रकटन विवरण में करने के साथ-साथ उपरोक्त पैराओं में भी किया गया है। प्राधिकारी का मानना है कि वास्तव में यह निवेदन घरेलू उद्योग ने भी स्वीकार किया है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है और वे लाभप्रद हैं तथा प्राधिकारी ने भी प्रकटन विवरण में इस तथ्य का उल्लेख किया है। प्राधिकारी ने पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थित में घरेलू उद्योग को होने वाली संभावित क्षति का मुल्यांकन किया है।

- (ii) विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने बताया है कि ऐसी संभावना नहीं है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में तृतीय देशों के समस्त निर्यात, जो कि भारत की कीमत से कमतर कीमतों पर होते हैं, अपवर्तित हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त कीमत का निर्धारण करने के लिए व्यापार की शर्तें भी एक महत्वपूर्ण प्राचल होती हैं। यह भी निवेदन किया गया है कि जांच अविध पश्चात क्षिति मार्जिन नकारात्मक है, इसलिए ऐसी कोई निश्चित संभावना नहीं है कि परिवर्तित निर्यात नुकसान दायक हो सकते हैं। प्राधिकारी ने एक संबद्ध देश से निर्यात कीमत पर विचार करते हुए और जांच अविध पश्चात पहुंच मूल्य, सूचक क्षित रहित कीमत से कम होने की स्थिति में नुकसान दायक हो सकता है, भारत को निर्यात के विपथन का संभावित विश्लेषण शुरू किया है। इसके अतिरिक्त जैसा कि बाद के पैरा में उल्लेख किया गया है, मूल सीमा-शुल्क में हाल ही में हुई वृद्धि को भी संभावना की जांच करने का एक कारक माना गया है।
- (iii) प्राधिकारी मेसर्ज विनथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) और मेसर्ज टीपीसी/एससीजी के भारत को उनके निर्यातों और ऐसे निर्यातों के कारण होने वाली घरेलू उद्योग की क्षिति पर प्रकटन पश्चात किए गए निवेदनों को नोट करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों सहयोगी निर्यातकों के आंकडों और याचिकादाता द्वारा प्रदत्त व्यापार मानचित्र के आंकडों के आधार पर यह देखा गया है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में जांच अविध के पश्चात भारत से भिन्न देशों से थाईलैंड के निर्यातों का भारत की ओर परिवर्तन होने से भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग ***% से भी कम होती है। क्षिति पूर्ण विपथन की मात्रा, घरेलू उद्योग को क्षिति की पुनरावृति निर्दिष्ट नहीं करती है। इसलिए थाईलैंड से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क को आगे बढाने की आवश्यकता नहीं है।
- हांलाकि चीन और यू एस ए से तीसरे देश को किये गए निर्यात की सीमा बहुत अधिक है और अत्यधिक निर्यात की (iv) ऐसी तीव्रता के साथ. निर्यातों के विपथन और इस प्रकार के विपथन के क्षतिकारक होने की संभावना भारत में मांग की बहुत अधिक मात्रा होगी यदि उस पर अपरिवर्तनशील परिदृश्य के रुप में विचार किया जाये। प्राधिकारी नोट करते है कि जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि संबद्ध देशों से उत्पादकों / निर्यातकों को दर्शाने वाले मैसर्स एल के एस और मैसर्स ई एल पी द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि पी वी सी पर बी सी डी की हाल में वृद्धि को क्षति के विश्लेषण की संभावना के लिए विचार किया जाये। इस प्रकार का विश्लेषण करते हुए, परिणाम अभी भी यह दर्शाते है कि क्षतिकारक निर्यात की सीमा बहुत अधिक है । क्षति के विश्लेषण की पहुंच मृल्य की गणना के लिए बी सी डी में वृद्धि के संबंध में अनुरोधों पर विचार करते हुए, यह नोट किया जाता है कि मांग में क्षतिकारक निर्यात के हिस्से की सीमा को कम किया गया है। चीन के लिए जांच की अवधि में और जांच की अवधि के बाद की अवधि में सहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के आंकड़ों के अनुसार विपथित क्षतिकारक निर्यात का प्रतिशत क्रमश: ***और क्रमश *** और यू एस ए के लिए क्रमश: ***और क्रमश ***हो जाता है । घरेलू उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, यह हिस्सा चीन के लिए क्रमश: *** और क्रमश: *** तथा यू एस ए के लिए क्रमश: *** और क्रमश: ***हो जाता है। इस कारण से विपथन पर क्षतिकारक निर्यात की मात्रा को घटाये जाने के लिए नोट किया जाता है। हालांकि अभी भी भारत में सबसे अधिक निराशावादी परिदृश्य के अनुसार कुल आयातों में चीन और यु एस ए का संभावित हिस्सा क्रमश 10 % और 20% होगा । किसी भी स्थिति में मात्रा से संबंधित क्षति की संभावना अब भी बहुत अधिक रहेगी । नीचे तालिका एच -3 और एच-4 इस परिदश्य को दर्शाता है।

जांच अवधि और जांच अवधि पश्चात् भारत को अपवर्तित ऐसे निर्यातों में से आकर्षक और हानिकर निर्यातों का उल्लेख निम्नानुसार है:-

तालिका-एच	T 1	- सहयोगी उ	पादक/निर्यातक
(11171741-6.)	1 1	יט וויודקוי –	. 71 4 7 7 1 1 1 9 1 1 1 7 7

	जांच अवधि											
क्रमांक	देश	प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा भारत को निर्यात की मात्रा	प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा तृतीय देशों को निर्यात की मात्रा	तृतीय देशों को निर्यात की आकर्षक मात्राओं का %	आकर्षक मात्राओं पर स्रति मात्राओं का %	देश की मात्रा का आकर्षण *	देश की स्नति की मात्रा **	भारतीय मांग के % के रूप में मात्रा का आकर्षण	भारतीय मांग के % के रूप में क्षतिकी			
		मी.टन	मी.टन	%	%			%	%			

1.	चीन	***	***	55-65%	85-95%	***	***	14.20%	12.71%
2.	थाईलैंड	***	***	50-60%	45-55%	***	***	5.34%	2.49%
3.	यूएसए	***	***	50-60%	65-75%	***	***	51.25%	35.79%
				जांच अवधि	पश्चात	•		1	
1.	चीन	***	***	75-85%	50-60%	***	***	13.35%	7.48%
2.	थाईलैंड	***	***	45-55%	15-25%	***	***	4.31%	0.87%
3.	यूएसए	***	***	70-80%	85-95%	***	***	90.59%	79.29%

तालिका-एच 2 - याचिकादाता का व्यापारिक मानचित्र के आंकडे

				जांच अ	वधि				
क्रमांक	देश	प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा भारत को निर्यात की मात्रा	प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा तृतीय देशों को निर्यात की मात्रा	तृतीय देशों को निर्यात की आकर्षक मात्राओं का %	आकर्षक मात्राओं पर क्षति मात्राओं का %	देश की मात्रा का आकर्षण *	देश की स्नति की मात्रा **	भारतीय मांग के % के रूप में मात्रा का आकर्षण	भारतीय मांग के % के रूप में स्नतिकी
		मी.टन	मी.टन	%	%			%	%
1.	चीन	***	***	80%	69%	***	***	19.66%	13.51%
2.	थाईलैंड	***	***	60%	68%	***	***	7.53%	5.16%
3.	यूएसए	***	***	12%	79%	***	***	12.37%	9.74%
	•	•		जांच अवधि	पश्चात				
1.	चीन	***	***	57%	67%	***	***	9.37%	6.26%
2.	थाईलैंड	***	***	61%	10%	***	***	6.86%	0.67%
3.	यूएसए	***	***	43%	30%	***	***	51.41%	15.36%

बीसीडी में हाल ही में हुई 7.5% से 10% तक की वृद्धि के विपथन सहित संभावित क्षति पर मूल्यांकन निम्नानुसार है:-

तालिका-एच 3 - सहयोगी उत्पादक/निर्यातक

	जांच अवधि											
क्रमांक	देश	प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा भारत को निर्यात की मात्रा	प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा तृतीय देशों को निर्यात की मात्रा	तृतीय देशों को निर्यात की आकर्षक मात्राओं का %	आकर्षक मात्राओं पर स्रति मात्राओं का %	देश की मात्रा का आकर्षण *	देश की क्षति की मात्रा **	भारतीय मांग के % के रूप में मात्रा का आकर्षण	भारतीय मांग के % के रूप में क्षतिकी			
		मी.टन	मी.टन	%	%			%	%			
1.	चीन	***	***	58%	55%	***	***	14.20%	10.41%			

2.	थाईलैंड	***	***	58%	68%	***	***	5.34%	2.49%			
3.	यूएसए	***	***	52%	31%	***	***	51.25%	30.18%			
	जांच अवधि पश्चात											
1.	चीन	***	***	80%	30%	***	***	13.35%	4.06%			
2.	थाईलैंड	***	***	45%	20%	***	***	4.31%	0.87%			
3.	यूएसए	***	***	76%	78%	***	***	90.59%	70.84%			

तालिका-एच 4 - याचिकादाता का व्यापारिक मानचित्र के आंकडे

				जांच ड	विधि				
क्रमांक	देश	प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा भारत को निर्यात की मात्रा	प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा तृतीय देशों को निर्यात की मात्रा	तृतीय देशों को निर्वात की आकर्षक मात्राओं का %	आकर्षक मात्राओं पर स्रति मात्राओं का %	देश की मात्रा का आकर्षण *	देश की क्षति की मात्रा	भारतीय मांग के % के रूप में मात्रा का आकर्षण	भारतीय मांग के % के रूप में स्नतिकी
		मी.टन	मी.टन	%	%			%	%
1.	चीन	***	***	80%	55%	***	***	19.66%	10.79%
2.	थाईलैंड	***	***	60%	68%	***	***	7.53%	5.16%
3.	यूएसए	***	***	12%	31%	***	***	12.37%	3.81%
	-	-		जांच अवधि	प्रश्चात			<u> </u>	
1.	चीन	***	***	37%	41%	***	***	9.37%	3.81%
2.	थाईलैंड	***	***	61%	10%	***	***	6.86%	0.67%
3.	यूएसए	***	***	43%	16%	***	***	51.41%	8.13%

B. निष्कर्ष

- 107. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों और किए गए निवेदनों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों की जांच करने के बाद जैसा कि इस जांच परिणाम में दर्ज किया गया है, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि -
 - (1) जांच अवधि के दौरान पाटित कीमतों पर संबद्ध देशों से भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात किए गए हैं।
 - (2) लागू पाटन-रोधी शुल्क के उपाय के साथ कीमत अथवा मात्रा में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को आर्थिकक्षति नहीं हुई है। लेकिन पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संयुक्त राज्य अमरीका और चीन से आयातों के कारण क्षति होने की संभावना विद्यमान है। थाईलैंड से आयातों से क्षति होने की संभावना बहुत कम महत्त्व की है।
 - (3) संभावित विश्लेषण से पता चलता है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संयुक्त राज्य अमरीका और चीन से भारत से भिन्न अन्य देशों को निर्यातों के अपवर्तित होने की संभावना है। यदि ऐसे अपवर्तित निर्यातों की अत्यधिक मात्रा के पहुंच मूल्य की तुलना, जांच अवधि पश्चात क्षति रहित कीमत के साथ करें तो ये घरेलू उद्योग की क्षति के कारण होंगे।

ड. सिफारिशें

108. (i) प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मै. वेस्टलेक को छोड़कर सभी सहयोगी उत्पादक/निर्यातक मूल अथवा पहली अंतिम निर्णायक समीक्षा जांच परिणाम में या तो नमूने न लिए गए/ अथवा श्रेष्ठ श्रेणी के अंतर्गत आएंगे । चीन के 7 सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों में से, 5 सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए जांच की अवधि में क्षिति का मार्जिन सकारात्मक है। चीन के शेष 2 उत्पादकों/निर्यातकों तथा यू एस ए के 2 सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षिति मार्जिन निम्न से लेकर औसत तक है। कुल मिलाकर पाटनरोधी शुल्क पाटन के बढ़े हुए मार्जिन और/ अथवा क्षिति के आधार पर मूल जांच परिणाम की तुलना में पहली अंतिम निर्णायक समीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक थी।

- ii. हालांकि प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में क्षित की संभावना का दावा घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है । संभावित क्षित विश्लेषण केवल चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात पर स्थापित है । हालांकि क्षित की सीमा पूर्व के पैराओं में यथाउल्लिखित बी सी डी में 10 प्रतिशत तक हाल में की गई वृद्धि के कारण कुछ हद तक कम हो सकती है । इसको देखते हुए, इस मामले में जांच की अवधि में क्षित मार्जिन संगत नहीं होगा और पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क जो लागू है जारी रह सकती है । हालांकि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि क्षित की संभावना है जो बढ़े हुए मूल सीमा शुल्क के बाद कुछ कमी को दर्शाता है, प्रथम अंतिम निर्णायक समीक्षा के बजाए मूल जांच परिणाम में लगाई गई शुलक की मात्रा मै. वेस्टलेक जिसके लिए सहयोग के कारण पहली निर्णायक समीक्षा में विशेष मार्जिन दिया गया है, को छोड़कर सभी सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए उपयुक्त होगी।
- iii. इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि यह दूसरी निर्णायक समीक्षा है, नीचे दी गई सिफारिशों के अनुसार, शुलक लगाए जाने की तिथि से लगातार शुल्क की 30 माह की अवधि उचित होगी ।
 - iv. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी दिनांक 11 जून, 2019 की मौजूदा सीमाशुल्क अधिसूचना सं.23/2019- सीमाशुल्क (एडीडी) को प्रतिस्थापित करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से 30 माह की अविध के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम (7) में दर्शाए गए अनुसार, चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

<u>शुल्क तालिका</u>

क्रमांक	शीर्ष	विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	3904	विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंसन ग्रेड) का होमो पॉलीमर	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	 मेसर्ज तियानजिन डगु केमिकल कंपनी लिमिटेड मेसर्ज तियाननेंग केमिकल कं., लि. मेसर्ज तियानजिन डगु केमिकल कंपनी लिमिटेड मेसर्ज क्सिनजियांग शेंगलोंग क्लोरो अल्काईल कंपनी लिमिटेड मेसर्ज चिपिंग किस्नफा पीवीसी कंपनी लिमिटेड मेसर्ज सीएनएसजी जिलेन्टाई सॉल्ट क्लोरी अल्काली केमिकल कंपनी लिमिटेड मेसर्ज यिविन हेईफेंग हेरूई कंपनी लिमिटेड 	61.14	मी.टन	अमरीकी डालर
2.	3904	विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंसन ग्रेड) का होमो	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कॉलम संख्या (6) में निर्दिघ्ट 1 से 7 को छोड कर कोई अन्य उत्पादक	147.96	मी.टन	अमरीकी डालर

		पॉलीमर						
3.	3904	विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंसन ग्रेड) का होमो पॉलीमर	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई अन्य देश	कोई भी	147.96	मी.टन	अमरीकी डालर
4.	3904	विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंसन ग्रेड) का होमो पॉलीमर	संयुक्त राज्य अमरीका	संयुक्त राज्य अमरीका	मेसर्ज वेस्टलेक विनायल एलपी	29.99	मी.टन	अमरीकी डालर
5.	3904	विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंसन ग्रेड) का होमो पॉलीमर	संयुक्त राज्य अमरीका	संयुक्त राज्य अमरीका	मेसर्ज ओक्सी विनायल्स एलपी	49.10	मी.टन	अमरीकी डालर
6.	3904	विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंसन ग्रेड) का होमो पॉलीमर	संयुक्त राज्य अमरीका	संयुक्त राज्य अमरीका	मेसर्ज वेस्टलेक विनायल एलपी और मेसर्ज ओक्सी विनायल्स एलपी को छोड कर कोई अन्य उत्पादक	115.54	मी.टन	अमरीकी डालर
7.	3904	विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंसन ग्रेड) का होमो पॉलीमर	संयुक्त राज्य अमरीका	संयुक्त राज्य अमरीका से भिन्न कोई अन्य देश	कोई भी	115.54	मी.टन	अमरीकी डालर

नोट: विचाराधीन उत्पाद विनायल क्लोराइड मोनोमर (पीवीसी) (सस्पेंशन ग्रेड) का होमोपालीमर है जहां विभिन्न पालीमर श्रृंखलाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, जिसमें हालांकि क्रॉस लिंक्ड पाली विनायल क्लोराइड, क्लोरीनेटेड पाली विनायल क्लोराइ (सी पी वी सी), विनायल क्लोराइड- विनायल एसीटेड कोपालीमर (वी सी – वी ए सी),पाली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन और पाली विनायल क्लोराइड ब्लेंडिंग रेजिन जैसे विशिष्ट पाली विनायल क्लोराइड सस्पेंशन रेजिन शामिल नहीं है।

ढ. आगे की प्रक्रिया

109. इस अधिसूचना के विरूद्ध कोई भी अपील, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2019

FINAL FINDINGS

Subject: Sunset review Investigation concerning imports of PVC Suspension Grade Resin from China PR, Thailand and USA.

F. No.7/34/2018-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

A. Background of the case

- 1. WHEREAS, the original investigation concerning imports of the subject goods from the Taiwan, China PR, Indonesia, Japan, Malaysia, Thailand, USA and Korea RP was initiated by the Authority and thereafter Final Finding Notification was issued by the Authority vide Notification No. 14/8/2006-DGAD dated 26th December, 2007 recommending imposition of definitive duty. On the basis of recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed with w.e.f. 23rd January, 2008 through Notification No. 11/2008. Post issuance of the final finding, the Authority issued a corrigendum dated 14th February, 2008 through Notification No. 14/8/2006-DGAD making modification in the duty table and the same was imposed accordingly by the Customs Authorities through Notification no. 38/2008 dated 24th March, 2008. Aggrieved by the order; interested parties approached the CESTAT and the matter was remanded back to the Authority. Post investigation, the Authority re-affirmed the decision passed by the Authority on 26th December, 2007. An expiry review investigation was conducted and the Authority recommended continued imposition of duty on the subject countries excluding Korea. The Ministry of Finance extended definitive anti-dumping duty vide notification No. 27/2014 dated 13th June, 2014.
- 2. WHEREAS, an investigation was initiated against the imports of subject goods from EU and Mexico through Notification No. 14/1012/2012-DGAD dated 5th October, 2012. The Authority recommended imposition of definitive anti-dumping duty through notification No. 14/1012/2012-DGAD, dated 4th April, 2014. Ministry of Finance imposed definitive antidumping duties on imports of subject goods from EU and Mexico through Notification No. 26/2014, dated 13th June, 2014.
- 3. WHEREAS, DCW Limited, DCM Shriram Ltd., and Chemplast Sanmar Limited, now known as Chemplast Cuddalore Vinyls Limited filed a combined application seeking extension of ADD on imports from EU, Mexico, Taiwan, China PR, Indonesia, Japan, Malaysia, Thailand and USA, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry in case of cessation of existing ADD.
- 4. The Authority upon satisfying itself on the basis of the prima facie evidence, considered that there is insufficient justification for conducting review investigations in respect of imports from EU, Mexico, Indonesia, Taiwan, Japan and Malaysia. The Authority therefore on the basis of prima facie evidence submitted by the applicants initiated sunset review investigation through public notice No. 7/34/2018-DGAD dated 29th October, 2018 to examine whether the expiry of the said duties on the import of the subject goods originating in or exported from the China PR, Thailand and USA (Hereinafter referred to as subject countries) are likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The Ministry of Finance extended the definitive Anti-dumping duty vide Notification No. 23/2019-Customs (ADD) dated 11th June, 2019.
- 5. The scope of the present review covers all aspects of the original investigations concerning imports of the above goods, originating in or exported from the subject countries.

B. Procedure

- 6. Procedure described herein below has been followed with regard to this investigation, after issuance of the public notice notifying the initiation of the above investigation by the Authority:
 - i. The Authority notified the Embassy/Representatives of the subject countries in India about the receipt of the Sunset Review application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
 - ii. The Authority issued a public notice dated 29th October, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject Sunset Review investigation
 - iii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users in India, other Indian producers and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
 - iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject countries and known importers/users in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
 - v. The Embassy of the subject countries in India was also requested to advise the exporters/producers from the subject countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to the Embassies along with the names and addresses of the known producers/ exporters from the subject countries.
 - vi. The Authority sent Exporter's Questionnaire and Market Economy Treatment Questionnaire (only for China) to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - FPC USA
 - Shintech
 - Westlake Vinyls Inc.
 - Westlake Vinyls Company LP
 - LG Dagu
 - Vinythai Public Ltd
 - Tianjin Dagu Chemical Co., Ltd
 - Georgia Gulf
 - OXY VINYLS
 - Thai Plastic and Chemicals Public Company Limited.
 - Apex Petrochemical Ltd
 - Sinopec
 - Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.
 - China Haohua Chemical (Group) Corporation (CHC)
 - Yibin Tianyuan Group Co. Ltd.
 - SINOPEC Qilu Company
 - Suzhou Huasu Plastics Co. Ltd.
 - Yichang Yihua Pacific Cogen Co. Ltd
 - Ningxia Yinglite Chemicals Co.,Ltd

- Shandong Haihua Chlor-Alkali Rosin Co. Ltd.
- Qingdao Haijing Chemical (Group) Co., Ltd
- Inner Mongolia Sanlian Chemical Corporation Limited
- Xinjiang Shihezi Zhongfa Chemical Co. Ltd
- Hubei Yihua Group Co. Ltd.
- vii. In response to the initiation of the subject investigation, following producers/exporters from the subject countries have responded by filing questionnaire response:
 - Thai Plastics and Chemicals PLC
 - SCG Plastics Co., Ltd.
 - SCG Performance Chemicals Co., Ltd.
 - Shintech Inc
 - Polymer Marketing DMCC
 - ITOCHU Plastics Pte. Ltd.
 - ITOCHU Thailand Ltd.
 - Oxy Vinyls Export Sales, LLC
 - ICC Chemical Corporation
 - Oxyde Chemicals Inc
 - Oxy Vinyls, LP
 - Tricon Dry Chemicals LLC, Tricon Energy UK Ltd. and Tricon Overseas Inc
 - Westlake Vinyls Inc
 - Westlake Vinyls Company LP
 - Axial LLC
 - Chiping Xinfa PVC Co., Ltd.
 - Shandong Xinfa Import & Export Co., Ltd.
 - CNSG Jilantai Salt Chemical (Group) Co., Ltd.
 - CNSG Jilantai Salt Chlori-Alkali Chemical Co., Ltd.
 - Yibin Tianyuan Group Co., Ltd.
 - Yibin Haifeng Herui Co., Ltd.
 - Vinythai Public Company Limited
 - Tianneng LG Bohai Chemical Co., Ltd.
 - Tianneng Chemical Co., Ltd.
 - Xinjiang Tianye(Group) Co., Ltd.
 - Tianjin Dagu Chemical Co., Ltd.
 - Bohai Chemical (HK) Limited
 - Xinjiang Shengxiong Chlor-Alkali Co., Ltd.

- Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd.
- viii. Further, submissions were also made by the following parties-
 - Thai Plastic and Chemicals PLC
 - China Chlor Alkali Industry Association filed by M/s LKS
 - ITOCHU (Thailand) Ltd.
- ix. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

•	Shalimar Rexine India Ltd.	•	Signet Overseas Ltd.
•	Finolex Group	•	Veekay Polycoats Ltd.
•	The Supreme Industries	•	Avon Plastics Group
•	Krishna Vinyls Group	•	KlJ Group
•	Prince Group	•	Caprihans India Ltd.
•	Jain Irrigation Systems	•	Par Petrochem Ltd.
•	Kalpana Industries	•	Sudharkar Group
•	Cosmos Corporation	•	Surender Commercial
•	Polytrusions Private Ltd.	•	MM Plastics
•	Polycab Cables Pvt. Ltd.	•	K S Plastics
•	Chandubai Group	•	Deluxe Kaaran Imort Pvt. Ltd.
•	J P Group	•	Aasu Chempoplast
•	Royal Cushion Vinyl Product	•	Dutron Plastics
•	Kisan Group Tex Centre	•	Prfintcrafts
•	Golden Group	•	Aditya Industries
•	Premier Polyfilm Ltd.	•	Jewel Polymers
•	V.K.Gandhi Group	•	Fancy Polymers Pvt Ltd
•	Omega Udyog	•	Varsha Corporation Ltd.
•	Fine Flow Plastic Industries	•	Maxx Impex
•	Kriti Industries (India) Ltd.	•	Oriplast Ltd.
•	Amisha Vinyls Pvt Ltd	•	Incom Cables Pvt Ltd
•	Nouvelle Credits Pvt.Ltd.	•	Diamond Pipes & Tubes
•	D.R.Polymers Ltd	•	Chaitanya Impogenex
•	Sintex Industries Ltd.	•	Tirupati Group
•	Sankhla Industries	•	Apollo Pipes
•	Shantilal Mahendrakumar	•	Havells India
•	Sam Polymers	•	Oswal Cable Products Ltd

Prakash Industries

- Megha Industry
- R.S. Overseas Pvt.Ltd.
- Associated Capsules Ltd
- x. The following importer of the subject goods has responded by filing an Importer questionnaire response.
 - Oxyde Chemicals & Polymers India Pvt. Ltd.
- xi. Further submissions were also filed by the following importers/associations -
 - Plastics Export promotion Council (PLEXCONCIL)
 - All India Plastics Manufacturers Association (AIPMA)
- xii. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;
- xiii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period and period prior to it, and also the period of investigation, and post POI. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions. The Authority also obtained data from DG-System for POI to correlate quantum of exports from specified exporters to validate the responses filed to the extent feasible.
- xiv. The Non-injurious Price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xv. The Authority held an oral hearing on 12th February, 2019 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance to Rule 6 (6), which was attended by the representatives of domestic industry and other interested parties. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of their views expressed orally. The parties were also advised to collect written submissions made by the opposing parties and were requested to submit their rejoinders thereafter.
- xvi. The verification of the information provided by the domestic industry was carried out to the extent considered necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon.
- xvii. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review investigation is April, 2017 to March, 2018 (12 months). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2014-15, 2015-16, 2016-17 and the POI and post POI (6 months) for likelihood analysis.
- xviii. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this disclosure statement.
- xix. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.
- XX. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.

- xxi. '***' in this document represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxii. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.65.33 = 1 US\$ and for Post POI (1/4/2018 to 30/9/2018) is reference as Rs. 69.15 per USD.

C.Scope of product under consideration and like article

C.1 Views of the domestic industry

- 7. Following submissions were made by the domestic industry with regards to the product under consideration
 - i. The product under consideration in the present investigation is PVC Suspension Resin, which is homo-polymer of vinyl chloride monomer (suspension grade) which is the same as was examined and concluded upon by the Authority in the original investigation. Since there are no major developments since the previous investigations with regard to the product under consideration, the scope of the product under consideration is required to be kept same as that of original investigations.
 - ii. Petitioners had agreed for exclusion in the previous investigations of certain products for the reason that these are totally different products as compared to suspension PVC and the domestic industry was not even producing these products earlier. Even when some of these products such as CPVC are now made in India, the same in any case are entirely different products, produced in different plants and after making significant investments. These products constitute totally different products as compared to the product under consideration. The scope of the product under consideration is limited to PVC Suspension Resin.
- iii. The subject goods are classified under chapter 39 of Customs Tariff Act, 1975 under the sub-heading 39041020 but have also been imported under other subheadings 39041090, 39042120, 39042190, 39042210, 39042290, 39049000. The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.
- iv. The use of multiple HS codes is very widespread and continues even after the Govt. has specified HS code for the product under consideration. Petitioners are unable to ascertain whether ADD has been collected on all such imports in the past or not. Therefore, the petitioners request the Authority to kindly consider extension of ADD for product falling under 3904 classification.

C.2 Views of the other interested parties

- 8. Following submissions were made by the domestic industry with regards to the product under consideration:
 - i. The customs classification is only indicative and not binding. Further, this issue is for the CBIC to address. Domestic Industry's request to impose ADD on all imports under 3904 classification is untenable as the said tariff heading extends to other products not within the scope of PUC.
 - ii. The DGTR in its Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations (at page 38) has already specified that, "The application of sunset review, in terms of Rule 23(1B) of the Rules can only be brought against the defined scope of PUC in the original investigation. Neither the applicant nor the Authority on its own can alter the scope of the PUC during the sunset review." Thus, the Authority must refrain from any amendment to the scope of the PUC in the present sunset review investigation even in terms of expanding the classification of the PUC

C.3 Examination by the Authority:

9. The product under consideration in the present investigation is "homo-polymer of vinyl chloride monomer (suspension grade), where various polymer chains are not linked to each other, falling under Customs Classification No. 3904". The product under consideration excludes specialty PVC suspension resins such as cross-linked PVC, chlorinated PVC (CPVC), vinyl chloride – vinyl acetate copolymer (VC-VAc), PVC paste resin and PVC blending resin. The product under consideration has also been referred to as "Poly Vinyl Chloride (PVC) Resin", "Suspension Grade" or "PVC Suspension Resin".

- 10. The subject goods are classified into different grades based on their K-value. Main applications of the subject goods depend upon their K-value; higher the K-value, higher the molecular weight. Low molecular weight PVC suspension finds main application in rigid film & sheet, blow moulded bottle and other injection moulding articles. Higher molecular weight PVC suspension finds major application in extrusion pipes and profiles. Still higher PVC suspension along with high porosity finds typical applications in wires & cables and other flexible applications such as shoe lasts, flexible films, etc.
- 11. The present investigation being a sunset review investigation and anti-dumping duties being in force on the imports of the subject goods from the subject countries, the Authority considers that the scope of the PUC in the present investigation remains the same as that in the original and subsequent review investigation. Moreover, none of the interested parties have made any quantified submission requesting modification (including curtailment) in the scope of the review. In this regard the last concluded SSR finding issued vide Notification No. 21/29/2011-DGAD dated 4th April, 2014 is relied upon, wherein the product under consideration was considered as follows:
 - "7. The product under consideration in the present investigation is "homopolymer of vinyl chloride monomer (suspension grade), where various polymer chains are not linked to each other, falling under customs classification no. 3904.21. The product under consideration however, excludes the specialty PVC suspension resins such as cross-linked PVC, chlorinated PVC (CPVC), vinyl chloride vinyl acetate copolymer (VC-VAc), PVC paste resin and PVC blending resin". The product under consideration is the same as considered in the original investigation.
 - 8. The product under consideration does not have dedicated HS Code and the imports are cleared under different HS Codes falling under 3904. The customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation and proposed measures.
 - 10. Having regard to the evidence on record and initiation notification, the Authority considers it appropriate to keep the scope of the product under consideration to the same as was considered in the original findings."
- 12. The Authority notes the submissions made in response to the disclosure regarding stipulation of the ITCHS at 4 digit level. The Authority in this regard notes that while different ITCHS may be quoted by producers/exporters, the product description assumes primary over the ITCHS as the same is indicative, keeping in view such concerns, classification of the PUC is mentioned at 4 digit level as was the case earlier. It is also clarified that the custom classification is only indicative in nature and not binding.
- 13. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules provides as under:
 - "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;
- 14. After considering the information on record, the Authority holds that there is no known difference in product under consideration exported from subject countries and the subject product produced by the Indian industry. The subject goods produced by the domestic industry is comparable to the subject goods exported from subject countries in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.
- 15. Thus, the Authority holds that the subject goods produced by the petitioners are like article to the product under consideration exported from the subject countries, in accordance with the Antidumping Rules.

D.Scope of domestic industry & standing

D.1 Views of the domestic industry

16. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard—

- i. M/s Chemplast Sanmar Limited, M/s DCW Limited and M/s DCM Shriram Ltd. are the petitioners in the present investigation, who command "a major proportion" of total India production.
- ii. M/s Chemplast Sanmar Limited, the suspension poly vinyl chloride Business/Undertaking of the Sanmar group has been transferred to and vested in M/s Chemplast Cuddalore Vinyls Limited. This has been approved under a composite scheme of Arrangement / de-merger by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Single Bench, Chennai ("NCLT"), under section 230 and 232 of Companies Act, 2013, vide its order dated 29th April, 2019.
- iii. M/s DCM Shriram Limited has a joint venture company, namely M/s Shriram Axiall Private Limited (now known as Westlake), which is involved in production of PVC compounds. The company has imported an insignificant volume of product under consideration from its related company, namely, Axiall LLC (Westlake), in USA. Details of which are on record. The imports made by this related company are insignificant in terms of production, consumption and imports in India.
- iv. Even if there is a related company in USA engaged in production of PUC and exporting it to India, the same should not imply ineligibility of a domestic producer in India. While Axiall LLC has exported the PUC to India, Shriram Axiall Private Limited has not imported product under consideration from Axiall LLC. Statement of imports by Shriram Axiall Private Limited shows that there is small (negligible) volume of imports from Thailand.
- v. While Axiall LLC (Westlake) has exported to India, DCM Shriram should not be treated as ineligible since Shriram has no direct or indirect control over Axiall. DCM itself has brought request for extension of ADD on imports from USA (which implies that DCM has sought duty on such exporter).
- vi. Petitioner companies with the exception of DCM Shriram certified that none of them is related to any importer of the subject goods into India, that none of them has imported the subject goods into India and that none of them is related to any exporter of the subject goods from the subject countries.
- vii. There are two more producers of the subject goods in India namely; Reliance Industries Limited and Finolex Industries Limited. The fact that petitioning companies constitute major proportion in the Indian production cannot be denied on the ground that one of the major producers of the subject goods RIL is not participating in the present investigation. The petitioners should not be penalized for non-participation by RIL.
- viii. The share of petitioning companies in Indian production collectively is 30.14%. While production of Reliance Industries Limited is also quite significant, the same does not imply that production of the petitioning companies does not constitute "a major proportion" in Indian production.
- ix. There can be more than one major proportion in any industry. In a situation where there is more than one proportion in India, the authority is required to consider whether the industry before the authority constitute "a major proportion" even when another industry before the authority may also constitute "a major proportion". Under present circumstances, the industry before the authority clearly constitutes a major proportion.
- x. The petitioners have not claimed continued injury but have claimed likelihood of recurrence of injury. While continued injury to the domestic industry is largely determined based on performance of the domestic industry and therefore constitution and composition of domestic industry assumes greater relevance and importance, in a case where the request for extension of duty is based on likelihood or recurrence of injury, what is relevant to the authority is the parameters impacting the determination of likelihood of recurrence.
- xi. There is no information on record to show that information of non-participating Indian producers is such that the same will establish absence of likelihood of recurrence of injury. There is no claim of interested parties that exclusion of data of non-participating producers will lead to material distortion in the analysis. It is only a conjecture of the interested parties.
- xii. The Authority has issued several determinations where the share of petitioners was much below 50% threshold. It is not even mandatory for Authority to determine injury within the meaning of Article 3

of the WTO Agreement. Petitioners have not claimed that dumped imports have caused continued injury. Such being the case, assessment of injury within the meaning of Article 3 in any case is neither relevant nor necessary.

D.2 Views of the other interested parties

- 17. The following submissions have been made by the other interested parties in this regard
 - i. There should be a strong support for continuation of duty. The domestic industry represents only 30% production of DI. The companies having major proportion are not supporting the petition.
- ii. No source of information is given for arriving at the production of the other Indian Producers.
- iii. DCM Shriram is not eligible domestic industry as it is related to one of the exporters in USA and has imported the PUC over the injury period.
- iv. Petition is silent on the source of information obtained for Reliance Industries and Finolex as well as the computation of the eligibility of the petitioners as regards standing. The production of RIL and Finolex has to be proved by the domestic producers themselves unless it can be proved by some other document.
- v. Reliance is also placed on 'Seamless Tubes and Pipes from China PR' wherein the applicant accounted for only 27% Despite the petition containing letters of support, Authority held that in absence of information from the supporters, injury and causal link could not be carried out and terminated the investigation. Further the legitimacy of the claim of the petitioner as regard to 30% production has not been proved through credible evidence.
- vi. As per Rule 2(b), DCM Shriram is ineligible for being within Domestic Industry as it is related to an exporter viz. Axiall LLC, having partnered together with it to form a 50:50 joint venture viz. Shriram Axiall Pvt Ltd.
- vii. DCM Shriram and Axiall LLC are in a position to legally and operationally exercise restraint over Shriram Axiall. Shriram Axiall has made imports from the subject countries resulting in it behaving differently from non-related producers. The standing of the Domestic industry be reassessed by discounting the production of DCM Shriram to assess if the other applicants constitute the threshold of 25%.
- viii. RIL operations must be analysed to determine state of Domestic Industry.
- ix. The standing of applicants as 'domestic industry' is suspect as they allegedly account for only 30% of production of subject goods, a claim not substantiated by any evidence except a mere statement to the effect and production figures whose source has not been disclosed. No information provided by RIL and Finolex, who constitute a major proportion of production in India, regarding their production during POI. Furthermore, as RIL and Finolex, participated in the previous investigations but have abstained from this sunset review, the applicants do not constitute major proportion any longer.
- x. Imports by Shriram Axiall should be compared with DCM Shriram's own production and consumption which will correctly reflect the proportion of imports made by it and whether the same is significant. Standing of Domestic Industry should be reassessed after exclusion of DCM Shriram.

D.3 Examination by the Authority:

- 18. The petition was filed by Chemplast Sanmar Limited, now known as, M/s Chemplast Cuddalore Vinyls Limited, DCW Limited and DCM Shriram Ltd. Apart from the petitioners, there are two other producers of the subject goods in India namely Reliance Industries Limited and Finolex Industries Limited.
- 19. It is noted that the petitioning companies have not imported the subject goods from the subject countries. However, related party of M/s DCM Shriram Limited, i.e., M/s Shriram Axiall Private Limited which is involved in production of PVC compound has imported the subject goods from Thailand and other countries. It is noted that imports made by Shriram Axiall Private Limited from subject country (Thailand) is merely 62 MT which extremely negligible in relation to imports of the product in India, Indian production & consumption and production of DCM Shriram Limited.

- 20. It has been contended that DCM Shriram Limited is related to a producer in USA. The Authority notes that the explanation to Rule 2 (b) provides that the domestic producers shall be deemed to be related to exporters or importers only if (a) one of them directly or indirectly controls the other; or (b) both of them are directly or indirectly controlled by a third person; or (c) together they directly or indirectly control a third person subject to the condition that are grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such as to cause the producers to behave differently from non-related producers. It has not been shown that there are grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such as to cause the producers to behave differently from non-related producers.
- 21. It is noted that Shriram Axiall Private Limited has not imported product under consideration from Axiall LLC, despite the fact that the company is partly owned by the US producer. The collaboration is of technical nature. As noted earlier, Shriram Axiall Private Limited, has imported goods from other countries which is insignificant in relation to imports of the product in India, Indian production & consumption and production. The Authority therefore considers that these imports do not render DCM Shriram Ltd. as ineligible domestic industry under the Rules.
- 22. As regards the contention that the production of the petitioners occupies only 30% of the total Indian production, information from other domestic producers were sought. However these producers have not responded to the present investigation. It is further noted that in a sunset review investigation where the request for extension of anti-dumping duties is not based on continued injury to the domestic industry and is rather based on likelihood of recurrence of injury, it is the information of exporters that is more pertinent to examine whether or not there exists likelihood of recurrence of injury. The Authority notes that in response to the disclosure, various interested parties have submitted that M/s Shriram Axiall LLC be excluded, M/s RIL has not participated and in event of its participation being an efficient unit, the NIP would be covered and thereby the likelihood of injury being impacted.
- 23. In view of the above, the Authority holds that the production by the petitioning companies constitutes 'a major proportion' of total Indian production of the like product and that the application satisfies the requirements of 'standing' under Rule 5 of the AD Rules (even though the same was not applicable at the stage of sunset review) and constitute 'Domestic Industry' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

E. Miscellaneous submissions

E.1. Views of the Domestic Industry

- 24. The following miscellaneous submissions have been made by the Domestic industry:
 - i. Domestic industry filed an application seeking extension of ADD against imports from EU, Mexico, Taiwan, China PR, Indonesia, Japan, Malaysia, Thailand and USA on the basis of their consideration that extension of ADD in respect of these countries is appropriate. The authority on the basis of prima facie evidence considered it appropriate to initiate the investigation only against China, Thailand and the USA. In any case it is for the authority to decide against who the investigation should be initiated. The other interested can refer the initiation notification in this regard.
 - ii. As regards the argument that Indian producers as a business tool to further increase market share in various products, it may be seen that list given by the interested parties itself shows that they are referring to only caustic soda (where the petitions are filed by AMAI, and there are more than 36 producers for the product in the country, and where DCW, DCM and Chemplast are only some of the producers in India), Soda Ash (the leading producers of soda ash in the country are GHCL, Nirma and Tata Chemicals). Petitioner's production constitutes hardly 10% of Indian production, Methylene Chloride (where production of Chemplast Sanmar is again much lower than Indian production. Gujarat Flurochemical is the leading producer of the product in the country). It is only PVC paste resin where Chemplast Sanmar is the only producer and who has taken relief under anti-dumping law.
- iii. Other interested parties have attempted to present misleading position before the authority. What is relevant for the purpose of this investigation or other investigations is whether the PUC is being exported to India at dumped prices and whether the same is causing injury to Indian industry. The

- fact that the Indian industry has taken relief under the law for a number of other products is entirely immaterial to the process.
- iv. There is no specific methodology involved in identifying the PUC. All transactions where description states "suspension" has been considered as product under consideration. The present case being a sunset review, and the product not holding varied descriptions, there is no necessity of clarifying the import methodology.
- v. The information that can be procured from MCA is totally different from the vast information that is available in the annual report. Thus, the annual report is confidential in nature. However, petitioners downloaded information from MCA has been filed separately.
- vi. Aspect of public interest cannot be limited to mere demand supply gap. Considering that significant fresh investments are in the pipeline, imposition of ADD is vital in order to ensure that these investments remain viable. GOI has earlier imposed ADD and extended the same which in itself establishes that imposition of ADD on the PUC shall be in public interest.
- vii. The petitioners have already disclosed all such information that is required to be disclosed as per the practice followed by the authority.
- viii. The petitioners are unable to make any submissions on the dumping margin for the reason that the exporters' have claimed almost entirety of the questionnaire response as confidential. The NCV of the questionnaire response are nothing but only empty formality.
- ix. Confidentiality claimed by exporters is not as per the trade notice. The EQRs filed are deficient and are devoid of any critical information.

E.2 Views of the other interested parties

- 25. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:
 - i. The duty has been in force for more than 11 years and has served its intended purpose.
 - ii. Cumulation of imports from the USA is not possible with the imports from China and Thailand. Imports from USA are less than 3% and do not warrant cumulation with the imports from China and Thailand
- iii. The investigation should not have been initiated considering the information contained in the petition or in fact, the lack thereof. Excessive confidentiality has been claimed without sufficient reasoning. Further it does not also contain sufficient/adequate evidence on dumping and/or injury and likelihood to justify initiation of the investigation.
- iv. Reasons for the exclusion of subject countries not given in the initiation notification.
- v. ADD has been used by the Indian producers as a business tool to further increase market share in various products. Company-wise list of ADD cases has been provided.
- vi. The determination made by the authority in Soda Ash (Turkey and Russia) case are relevant, where case was not initiated on the ground of good performance of domestic industry.
- vii. Excessive confidentiality has been claimed. Import methodology has been unduly claimed confidential. Chemplast Annual Report can be produced by paying the fees to MCA still the Annual Report has been claimed confidential.
- viii. The "test" studying the behaviour of the subject countries on a month by month basis for a period of 10 years as suggested by the Petitioner is not part of the prescribed analysis for assessment of likelihood of dumping and injury. It is also noted that the price of some country being the lowest was a given in the said study. The Petitioners failed to observe that that the Chinese prices were not the lowest price in 92 instances out of 120.
- ix. Authority must clarify the basis of its determination that there existed prima facie sufficient justification for initiation of investigation only against China PR, Thailand and USA. The Authority is requested to disclose the reasons for non-selection of certain other countries regarding which

- similar information was provided by the Petitioners (as for the subject countries) for seeking initiation of investigation.
- x. The Authority has excluded five countries out of eight countries without providing appropriate reasons for exclusion of the same. The Director General should give speaking order as why the other countries are excluded. In the past, during 1st sunset review investigation, the Authority itself had excluded Korea RP from the scope of subject countries and reasons for the exclusion of the same were explicitly explained as per Para 155 of the Final Findings No.21/29/2011-DGAD dated 4th April 2014. The same analogy should be applied herewith.
- xi. As per information available with us, Chemplast has no plans for capacity addition in India. Reliance Industries has issued the project report for debottlenecking and expansion of Petrochemical Plant in March 2016. It got approved during April 2017, however, it has not started the expansion till date. Thus, Indian industry cannot solely depend on the domestic producers to fulfil the demand.
- xii. The Petitioners have made averments regarding their investments which create suspicions of disclosing false information to the Hon'ble Designated Authority.
- xiii. Petitioners have made various allegations of excessive confidentiality claimed by the Exporters. The Exporters submit their own allegations of excessive confidentiality claimed by the Petitioners
- xiv. Non confidential version of the application is not as per Rule-7 and the trade notice.
- xv. Only the Authority can seek information under the Rules. Further, the rules also prohibit delegation. Shri J.M. Bishnoi was appointed by the central govt. to assist the Authority. In view of the rules, the direction calling for post Post-POI data could not have been issued by any other person except for the Designated Authority. Further, it has been wrongly stated in the letter dated 9.4.2019 that such information was sought and intimated at the time of the oral hearing. Direction to provide information is without jurisdiction due to not being issued by the competent authority;
- xvi. Post-POI information submitted by the interested parties pursuant to the subject letter ought to be discarded by the Designated Authority for purposes of its final determination.
- xvii. In view of Trade Notice 5/2018, transaction wise third country data is not to be seen in case normal value has been claimed by the producer/exporter on the basis of their sales in the home market and in such cases, "format set out in this questionnaire with respect to exports to third countries may be ignored". The Trade Notice mentions that it is in supersession of all previous instructions and trade notices issued earlier.
- xviii. Directions cannot be given to provide information which is beyond the POI defined by the Authority since there is no provision under municipal law or AD agreement for considering data beyond the POI. The POI defined forms the basis for objective and unbiased determination whereas adoption of post POI data in selective cases introduces subjectivity would be inconsistent as well arbitrary.
- xix. In case the Authority is of the opinion that post POI data may be relevant then it has the power to extend the POI. Unless the POI is extended, any information not within the period covered does not have any legal sanctity and would be extraneous for purposes of dumping and injury determination.
- xx. Even assuming that the seeking of post POI data implies extension of the POI the same has reduced the time given to interested parties for furnishing the information to 3 weeks which is outside the scope of Rule 6(4) that allows minimum 30 days. In such a case even the domestic industry be directed to furnish the required data and the interested parties be given an opportunity to present their views which would imply another hearing, fresh submissions and rejoinders.

E.3 Examination by the Authority

- 26. The various miscellaneous submissions considered relevant have been examined as under:
 - i. As regards to contentions raised on the reasoning for the exclusion of some countries, the Authority notes that the initiation notification specified that there was insufficient justification for conducting review investigations in respect of imports from EU, Mexico, Indonesia, Taiwan, Japan and

- Malaysia, thus the scope of the review investigation is restricted to imports of the product under consideration from China PR, Thailand and USA only.
- ii. As regards the contention of non-disclosure of import methodology, it is noted that the all transactions where description states "suspension" have been considered as product under consideration in the present investigation. Further, the domestic industry had filed hard copy of the transaction wise import data which shows that all the transactions considered by the domestic industry as PUC involves "suspension" in the description. However, none of the interested party sought sorted transaction wise data in the form and manner prescribed.
- iii. As regards the contention that the demand in the country is more than the supply ability of the producers, it is noted that the demand supply gap in country should not justify dumping. The dumping margin determined for all the subject countries during POI are positive despite imposition of anti-dumping duty.
- iv. As regards the contention with regard to confidentiality of information, it is noted that information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The information related to imports, performance parameters and injury parameters of domestic industry has been made available in the public file. Business sensitive information has been kept Confidential as per practice. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.
- v. As regard the argument that cumulation of USA imports with the imports from China and Thailand, it is noted that the Designated Authority has not found that the domestic industry is suffering continued injury. Separate information for the three countries is on record with likelihood analysis separately undertaken for each country.
- vi. As regard the contention that the antidumping duty being in force for 11 years now and having served its intended purpose, the Authority notes that it proposed to examine the evidence of likelihood of recurrence of dumping and injury, as per rules.

F. Market Economy Treatment (MET), Normal Value, Export Price and Determination of Dumping Margin

F.1. Views of the Domestic industry

- 27. The domestic industry inter alia submitted as follows:
 - The Authority is requested to kindly consider the price of the product under consideration from market economy third country to India. Significant exports in this period have been made from Taiwan and Korea. The Authority may therefore kindly consider adopting import price from Taiwan or Korea or an average of Taiwan and Korea into India for the purpose of determination of normal value.
 - ii. The petitioners for the purpose of determining normal value in market economy have referred to the prices of the subject goods quoted in leading trade journals i.e.; IHS Chemical publication. The details regarding the IHS Chemicals are on record.
- iii. Published prices mentioned in well established trade journals clearly shows that the price of product in US market is significantly higher than the price at which goods have been exported to India.
- iv. The normal value in Thailand has been claimed on the basis of the prices published in IHS Report for South East Asia.
- v. Export price has been determined on the basis of weighted average price of imports of all known imports into India. Export price has been determined as the per unit import price from subject

- countries. The export prices have been, therefore, adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and handling charges.
- vi. The calculations of normal value and export price shows that the dumping margins are positive and significant. The Authority is requested to kindly determine monthly dumping margin because of the significant price variations in VCM and PVC prices.
- vii. Increase in imports is higher from other countries, however, the price at which goods have come in from other countries is far higher than the price at which goods have come in from subject countries. Import volumes per-se cannot be considered as decisive factor for deciding the scope for subject countries. The other relevant consideration is price at which goods have come in from various countries.
- viii. The prices published in IHS are treated very reliable by PVC producers and consumers globally. Most of the global trade happens after looking at the prices mentioned by I.H.S. Any argument that prices mentions in I.H.S. are unreliable is required to be rejected.
- ix. In case of China, and considering provisions of Para 7 to Annexure I, normal value is required to be determined on the basis of price from a third country to other countries, including India. Accordingly, the import price from Taiwan or Korea or Taiwan & Korea can be considered for determination of normal value in case of China.
- x. Reference is laid on final findings notified by the authority in more than 60 cases after Dec. 2015, wherein, authority has consistently determined normal value after following the provisions laid down under Para 7 of Annexure I. There is no change in the legal position or the facts of the present case which justify a different consideration in this regard.
- xi. The information provided by I.H.S. bears the qualification "For Use by Licensed Subscribers Only". In view of the same, petitioners are not in a position to make I.H.S report public. I.H.S report is one which is mostly used by leading producers of PVC resin globally. The respondents could have bought their own copy of the IHS reports relied on by the petitioners. IHS report is available for anyone who is willing to subscribe for same.

F.2 Views of the interested parties

- 28. The following submissions have been made by the other interested parties
 - i. Imports from third countries have increased at much faster rate than import from subject countries. Dumping is happening from other countries.
 - ii. There are various inconsistencies with respect to the construction of normal value and export price, which impact the dumping margins projected by the Petitioners.
- iii. Petitioners, belatedly in their Written Submissions, suggested that the Normal Value of the subject goods in China PR, in terms of paragraph 7 of Annexure I of the Indian AD Rules, may be constructed on the basis of the PUC from market economy third countries to India, such as Taiwan and Korea RP. Such selection of a surrogate country must follow due process. Firstly, proposal for selection of an appropriate surrogate country must flow from the Authority rather than the parties to the investigation. Secondly, once such a proposal has been made by the Designated Authority, due opportunity must be given to comment upon the appropriateness of the chosen surrogate country. Finally, it is only after such comments have been evaluated that the Designated Authority can proceed to finalize the surrogate country for the purpose of an investigation.
- iv. Apart from the process for selection of a surrogate country, it is also critical that the Authority must receive response from the producers in the selected surrogate countries, providing information pertaining to their functioning, cost of production and selling prices. Specifically, in many previous investigations, the Authority refused to consider some countries as appropriate surrogate countries only due to non-availability of responses from producers in those countries.

- v. Petitioners made adjustments to the import prices from Taiwan and Korea RP on an unsubstantiated basis. No sources were provided for the import prices or the freight, insurance and other charges or adjustments
- vi. Consumption norms of participating exporters must be considered for determination of normal value even if normal value is constructed.
- vii. There is no reason or basis to "construct" export price. The Authority has the EQRs filed by the producers / exporters from China PR and the same may be referred, as verified by it, for the establishment of Net Export Price for each of the participating Chinese producer / exporter.
- viii. Names of the Chinese traders as reproduced by the Petitioners and the names of the participating members of the Association do not match. It appears that the Petitioners have compared prices of exports to India with prices of exports to rest of the world
- ix. Petitioners appear to have provided data pertaining to traders who are not party to the current investigation, with the exception of Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd., Shandong Xinfa Import & Export Co., Ltd. and Yibin Tianyuan Group Co., Ltd. In the case of all three traders, price comparison between prices for exports to India vis-à-vis prices for exports to rest of the world show a difference of merely 2%, with Indian prices being 2% lower. The Petitioners' parallel claim that the exporters' price to third countries is lower than their prices to India (and that therefore there is a likelihood of diversion to India) is totally defeated.
- x. It was submitted that the normal value and dumping margin concerning the US producers referred in the petition for this investigation was based on prices published in IHS Report (IHS) for the North American market, according to the petition. The Normal Value during the POI was 80-100 Indian Rupees per KG, and the Dumping Margin was shown as 70-80%, depending on the month. However, the details of the calculation were not provided.
- xi. The calculation of appropriate Normal Value relies on the accuracy of the published price index. SHINTECH argues that IHS price index for North America is not a suitable source of information to be used for such purpose.
- xii. IHS contract price index is clearly not the representative of absolute values of actual prices in the PVC market in the United States and their use would lead to an unfair comparison of Normal Value and Net export price under WTO and Indian regulation. Petition states that the petitioners used the price information from IHS Report for the US market, which is clearly not appropriate for the purpose of the investigation.
- xiii. Instead, ICIS spot price index offers a sounder alternative for the calculation of Normal Value, and one which can be justified and checked against public sources and the other information available on record in the present investigation.
- xiv. The prices considered by the Petitioners for determination of Normal Value are unreliable and inadmissible. There is no evidence that these rates are at ex-factory level. Petitioners have claimed arbitrary adjustments.
- xv. Article 11.3 of WTO: ADA and Rule 23(1B) of the AD Rules 1995 mandates that initiation of sunset review must be upon a duly substantiated request by the domestic industry. In the Petition, Domestic Industry has determined NV for China based on cost of production of an efficient petitioner company without specifically mentioning which company. For MET countries, data provided in a trade journal viz. IHS Chemical Publication has been relied upon to construct NV.
- xvi. Prices mentioned in trade journals are not admissible evidence or judicially noticeable facts unless based on public documents of the country for whom NV is being calculated as held in Dye Stuff Manufacturers Association of India: 2003(157) ELT 154 (Tri Del) wherein it was also observed that journal data do not constitute "facts" and are irrelevant. Domestic Industry has not stated that data in IHS Chemical Publication has been sourced from public documents or proved such information to be reliable or accurate. Therefore, NV based on trade journals cannot be relied upon. Similarly, no evidence was provided by Domestic Industry with respect to adjustments in export price. Though Final Findings are issued on verified data, initiation of investigation should also be based on

- admissible evidence as otherwise, legal requirements regarding the same would be rendered superfluous
- xvii. Normal value constructed by Domestic Industry cannot be relied upon because (i) average of highest price and lowest price considered for each month, (ii) unsubstantiated 'delivery cost' has been added to artificially inflate NV, (iii) prices in IHS publication are region wise, not country-wise (iv) it is not known whether data in IHS publication covers all types of PVC Suspension Resin or only PUC, (v) while NV is determined at ex-factory level, IHS publication does not indicate level at which NV has been arrived at, what adjustments were taken into consideration, whether the prices were at bulk or retail level, whether any discounts were included, etc. Unless such adjustments are taken into account, NV will remain inflated.
- xviii. Normal value constructed for China cannot be relied upon because (i) it is not known which petitioner company's data has been used to derive costs of production, (ii) standard of 'efficiency' itself is doubtful (iii) assuming that cost of Indian producers is same as that of China is not correct, (iv) Domestic Industry's failure to determine NV of China on price /constructed value in appropriate MET third country by stating that "the normal value in China of the product under consideration could not be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available" contradicts Domestic Industry's own claim that prices reported in IHS Publication constitute "reasonable, accurate and adequate information for determination of NV".
 - xix. Despite the expiry of China's accession protocol, the Indian authorities have wrongly supplied the MET Questionnaire.

F.3 Examination by the Authority

China

F.3.1 <u>Determination of normal value and export price</u>

Examination of Market economy claims, and normal value computation

- 29. At the stage of initiation, the petitioner proceeded with the presumption by treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of whether their data/information could be adopted for the purpose of normal value determination. The Authority sent copies of market economy treatment questionnaire to all the known producers/ exporters for providing relevant information in this regard. However, none of the Chinese producers/exporters have filed response claiming MET.
- 30. The Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:
 - (a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:
 - (i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;
 - (ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to

manufacture, production and sale of that product.

- (b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.
- (c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.
- (d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."
- 31. The Authority notes that on 11.12.2016 the provisions of 15 (a) (ii) have though expired, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure 1 of India's AD Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the MET status. The Authority notes that since none of the responding producers, exporters from China have submitted market economy treatment questionnaire response, the normal value computation is required to be dealt as per provisions of para 7 of Annexure-1 of AD Rules.
- 32. The Authority notes that no submission on normal value approach to be adopted as contained in para 7 of the annexure 1 to AD rules have been made. Further AD duty on imports of the subject goods has existed on a number of countries except South Korea which appears to be feasible option as its volume is comparable with China. The Authority has constructed normal value on the basis of Cost of Production of domestic industry with appropriate normation of various cost elements, adopting best practices and international raw material prices as considered appropriate. The normal value so computed is also broadly corroborated with the import price from Korea (at exfactory level).

Determination of Export Price for China PR

- 33. The following producers/exporters filed exporter's questionnaire (EQ) response in the present investigation:
 - a. Chiping Xinfa PVC Co. Ltd and Shandong Xinfa Import & Export Co.Ltd. (exporter)
 - b. CNSG Jilantai Salt Chlori Alkali Chemical Co.Ltd. (producer) and its related exporter CNSG Jilantai Salt Chemical (Group) Co. Ltd
 - c. Yibin Haifeng Herui Co. Ltd. (producer) and its related exporter Yibin Tianyuan Group Co. Ltd.
 - d. Tianjin LG Bohai Chemical Co. Ltd. (producer)
 - e. Tianneng Chemical Co. Ltd (producer) and Xinjiang Tianye (Group) Co.Ltd (exporter)
 - f. Tianjin Dagu Chemical Co. Ltd (producer and exporter) and Bohai Chemical HK Limited
 - g. Xinjiang Shengxiong Chlor-Alkali Co. Ltd (producer) and Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd (exporter)

The exfactory export price for the aforesaid cooperative producers/exporters is evaluated as under:

34. Yibin Haifeng Herui Co., Ltd. ("Haifeng Herui") and Yibin Tianyuan Group Co., Ltd. ("Yibin Tianyuan")

The producer/exporter has exported *** MT of Subject goods to India during POI at a Gross invoice value of *** USD at a equivalent CIF price of *** \$/MT. The Authority has considered adjustments (in \$/MT) on Ocean freight, Ocean insurance, Port Charges and Bank Charges to an extent of ***, ***, *** and *** respectively. The exfactory export price after allowing above adjustments is considered as *** \$/MT. The landed value is considered as *** \$/MT.

35. CNSG Jilantai Salt Chemical (Group) Co., Ltd. and CNSG Jilantai Salt Chlori-Alkali Chemical Co., Ltd.

The Producer/exporter has exported *** MT of subject goods to India during POI at a Gross invoice value of *** USD at a equivalent CIF price of *** \$/MT. The Authority has considered adjustments (in \$/MT) on Ocean freight, Ocean insurance, Port Charges and Bank Charges to an extent of ***, ***, *** and *** respectively. The exfactory export price after allowing above adjustments is considered as *** \$/MT. The landed value is considered as *** \$/MT.

36. Chiping Xinfa PVC Co Ltd. and Shandong Xinfa Import & Export Co. Ltd.

The producer/exporter has exported *** MT of subject goods to India during POI at a invoice value of *** USD at a equivalent CIF price of *** \$/MT. The Authority has considered adjustments (in \$/MT) on Ocean freight, Ocean insurance, Port Charges and Bank Charges to an extent of ***, ***, *** and *** respectively. The exfactory export price after allowing above adjustments is considered as *** \$/MT. The landed value is considered as *** \$/MT.

37. Tianneng Chemical Co., Ltd. and Xinjiang Tianye (Group) Co., Ltd.

The above producer/exporter has exported *** MT of subject goods to India during POI at a Gross invoice value of *** USD at a equivalent CIF price of *** \$/MT. The Authority has considered adjustments (in \$/MT) on Ocean freight, Ocean insurance, Port Charges and Bank Charges to an extent of ***, ***, *** and *** respectively. The exfactory export price after allowing above adjustments is considered as *** \$/MT. The landed value is considered as *** \$/MT.

38. Tianjin LG Bohai Chemical Co., Ltd.

The above producer/exporter has exported *** MT of subject goods to India during POI at a Gross invoice value of *** USD at a equivalent CIF price of *** \$/MT. The Authority has considered adjustments (in \$/MT) on Ocean freight, Ocean insurance, Commission, Inland Freight, Port Charges Credit Cost and Bank Charges to an extent of ***, ***, ***, ***, ***, *** and *** respectively. The exfactory export price after allowing above adjustments is considered as *** \$/MT. The landed value is considered as *** \$/MT.

39. Tianjin Dagu Chemical Co., Ltd. and Bohai Chemical (HK) Limited.

The above producer/exporter has exported *** MT of subject goods to India during POI at a Gross invoice value of *** USD at a equivalent CIF price of *** \$/MT. The Authority has considered adjustments (in \$/MT) on Ocean freight, Ocean insurance, Inland Freight, Port Charges, Credit Cost and Bank Charges to an extent of ***, ***, ***, ***, *** and *** respectively. The exfactory export price after allowing above adjustments is considered as *** \$/MT. The landed value is considered as *** \$/MT.

40. Xinjiang Shengxiong Chlor – Alkali Co., Ltd. and Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd.

The above producer/exporter has exported *** MT of subject goods to India during POI at a Gross invoice value of *** USD at a equivalent CIF price of *** \$/MT. The Authority has considered adjustments (in \$/MT) on Ocean freight and Insurance, Inland Freight and Port, Commission, Credit Cost and Bank Charges to an extent of ***, ***, ***, *** and *** respectively. The exfactory export price after allowing above adjustments is considered as *** \$/MT. The landed value is considered as *** \$/MT.

41. Residual Category

The Authority has referenced the least export price i.e ex-factory export price and as well as landed value for

residual category.

F.3.2 USA

42. <u>Determination of Normal value and ex-factory export price for USA-Cooperating producers/exporters</u> and residual

Cooperating producers/exporters

M/s Westlake Vinyls Company LP (Producer and Exporter); M/s Axial, LLC(Related Producer); M/s Westlake Vinyls Inc. (Related Producer)

Normal Value

M/s Westlake Vinyls Company LP (producer and exporter), comprising of M/s Axial LLC (Related Producer) and M/s Westlake Vinyls Inc. (related producer) have filed EQR. Only M/s Westlake Vinyls Company LP has exported *** MT of K 65 grade only to India during POI.

The Authority notes that since the three entities are related, for the purpose of normal value, the domestic sales of all these three entities are to be considered. However for an apple to apple comparison the domestic sales of grade exported to India is being considered. Also the Authority notes that the producer/exporter has sold in the domestic market both to affiliated and non-affiliated buyers. Noting the price variations to these two groups, the Authority has considered domestic sales of K 65 grade by all the 3 entities only to unrelated buyers since prices to affiliated buyers and those to unaffiliated vary quite a lot. The domestic sales meet the significant quantity test and for the purpose of OCT test the Authority has referenced the weighted average exfactory cost of production as *** \$/MT. On the basis of this test ***% sales are noted to be profitable. Accordingly with adjustments (in \$/MT) on the domestic sales to the unaffiliated customers of K 65 grade for discount (all three types), rebates, freight, and credit cost to an extent of ***, ***, *** and *** respectively, the normal value is considered as *** \$/MT.

The exfactory export price

The Authority notes that only M/s Westlake Vinyls Company LP (producer/exporter) has exported to an extent of *** MT of K 65 grade to India at a CIF of *** \$/MT. The Authority has allowed adjustments (in \$/MT) on packing, ocean freight, insurance, inland freight, port, credit cost, bank charge to an extent of ***, ***, ***, ***, ***, *** respectively. The exfactory export price and landed value are adopted as *** \$/MT and *** \$/MT respectively.

43. M/s Oxy Vinyls LP (Producer); and M/s Oxy Vinyls Export Sales LLC (Affiliated Trader in USA)

Cooperating producers/exporters

Determination of Normal Value and Export Price

Oxy Vinyls, LP ("OVLP"), is the producer of the product under consideration from USA. OVLP has made sales to export markets (including India) through its affiliated exporter, namely Oxy Vinyls Export Sales, LLC ("OVLLC"). OVLLC in turn made sales to various export markets in the period of investigation through unaffiliated traders. For India, sales were made through two particular unaffiliated traders, namely Tricon Dry Chemicals LLC and ICC Chemical Corporation ("ICC").

The Authority has undertaken a table verification of data filed by both OVLP, OVLLC, Tricon and ICC on various aspects of cost of production, domestic selling price, export price to India and other countries and adjustments claimed on export price to India.

The Authority considered the normal value, ex-factory export price and landed value as under:

Normal Value

During the POI, OVLP sold only one grade to India in the period of investigation i.e. OxyVinyls 225. OVLP submitted that this grade is not comparable to the other grades that fall under the purview of the product under consideration. OVLP has reported domestic sales and cost pertaining to only grade 225. The Authority notes that since this grade constitutes significant part of the sales in the domestic market, and comparison is to be

undertaken on an apple to apple basis for grades exported to India, the response filed by the producer/exporter has been considered to evaluate the dumping margin. The Authority has computed the exfactory cost of production as *** \$/MT. Oct test conducted on domestic sales indicate that *** % of transactions are profitable and therefore the Authority has accordingly referenced the overall domestic selling price.

OVLP's sales of the product to unaffiliated customers (directly), of quantity of *** MT. To arrive at the exfactory price, post-factory expenses pertaining to inland freight, storage and credit cost are proposed to be to the extent of *** USD/MT, *** USD/MT and *** USD/MT respectively. The exfactory price i.e normal value comes to *** \$/MT.

Export Price

In the POI, OVLP and OVLLC sold the PUC to India through two unaffiliated traders, namely ICC and Tricon. In the post-POI period, sales were made through another unaffiliated trader, i.e. Oxyde Chemicals Inc., USA ("Oxyde USA"), which sold the PUC to its related importer, namely Oxyde Chemicals & Polymers India Pvt Ltd ("Oxyde India"). All six companies filed their relevant questionnaire responses, and also filed post-POI sales data to India and other countries.

44. Residual Category

Highest normal value and least ex-factory export price are referenced.

M/s Shintech who have only filed submission and no data as per exporter questionnaire response, for the prepare of dumping margin and injury margin assessment, they are treated in residual category.

F.3.3 Thailand

<u>Determination of Normal value and exfactory export price for Thailand-Cooperating</u> producers/exporters and residual

Cooperating producers/exporters

45. Thai Plastic and Chemicals PLC (Producer), SCG Plastic Co. Ltd. (Related Exporter), SCG Performance Chemical Co. Ltd. (Related Exporter)

M/s Thai Plastic and Chemicals PLC (TPC) , the producer has sold the subject goods through its two related marketing entities i.e M/s SCG Plastics Co. Ltd. and M/s SCG Performance Chemical Co. Ltd. during POI and post POI in the domestic market and as well as to India and countries other than India. The channel and grade wise details of domestic sales and exports to India are as under:

TPC sold *** MT to SCG Plastics in POI, who further exported *** MT to India, sold *** MT in their domestic market and exported *** MT to countries other than India.

The Authority notes that since M/s SCG Plastics Co. Ltd. and M/s SCG Performance Chemical Co. Ltd. are related to Thai Plastic and Chemicals PLC, the 'normal value' is computed on the basis of combined domestic sales of the two entities. SCG performance Chemical Co. Ltd. has sold only to a related entity in domestic market and therefore domestic sales of SCG Plastics Co. Ltd. of same grades (as exported to India) to unrelated entities which is *** MT have been referenced to compute the normal value.

The Authority notes that M/s SCG plastics has claimed adjustments inland freight, credit cost, bank charges, direct marketing, technical support, and RIL. The Authority notes that the producer/exporter has submitted that expenses on technical support and RIL charges (for training on domestic sales effort) are only incurred for domestic sales which could not be justified during the onsite verification. Subsequently though the producer/exporter has provided some data, it has not been established that the expenses are dedicated for

domestic sales only. SGA expenses and profit are considered @ *** % and *** % for SCG Plastics and *** % and *** % for SCG Performance respectively both for domestic and export sales. Therefore adjustments (in Bhat/MT) on Inland freight (*** Bhat/MT); credit cost (*** Bhat/MT); bank charges (*** Bhat/MT), Direct marketing/SGA (*** Bhat/MT); profit (*** Bhat/MT).

After considering above adjustments on the domestic sales, the exfactory domestic selling price at the TPC level is compared with the exfactory cost of production of TPC considered as *** Bhat/MT. The OCT test on the domestic sales (at exfactory level) of exported grades to unrelated entities in domestic market indicate that all domestic sales are profitable. The normal value is thus computed as exfactory domestic selling price of all the transactions considered in the OCT test, which comes to *** US\$/MT.

Exfactory export selling price

The Authority notes that both M/s SCG plastics and M/s SCG performance have exported to an extent of*** MT included *** MT of SCG Plastics. The grades exported are 258, 261, 286, SP 660, SG 660, SF 580, SG 701, SG 500, SG 585, SG 610 at a gross value of *** Bhat/MT. The Authority notes that the adjustment claimed as FE adjustment to an extent of *** Bhat/MT was not justified during the onsite verification and subsequently only internal memos of the marketing division and others have been provided. With no supportive conclusive justification, the Authority has not granted this adjustment. The Authority also notes that direct marketing expenses have been claimed for both domestic and export sales separately without any breakup of the same. The Authority has therefore applied the average SGA expenses (*** Bhat/MT) on both domestic and export sales for both the marketing entities as an adjustment. Also profitability (*** Bhat/MT) have been considered as an adjustment both on domestic and export sales. The Authority has considered adjustments. On ocean freight (*** Bhat/MT); Ocean insurance (*** Bhat/MT); Inland freight (*** Bhat/MT); Port (*** Bhat/MT); Credit cost (*** Bhat/MT); Bank charges (*** Bhat/MT); Export rebate (*** Bhat/MT); Commission (*** Bhat/MT).

The weighted average ex-factory export price, and landed value comes to *** Bhat/MT (*** \$/MT) and *** \$/MT respectively.

46. Determination of Normal Value and Export Price

M/s Vinythai Public Co. Ltd, Thailand

M/s Vinythai Public Co. Ltd, Thailand has sold three grades i.e 258, 261 and 266 in the domestic market as also exported to India during POI. The total quantity of domestic sales of these grades is *** MT. This quantity meets sufficient quantity test and further the OCT test was also conducted adopting the exfactory cost of subject goods as *** Bhat/Kg. (*** \$/MT). More than ***% sales are noted to be profitable and hence the normal value is referenced on the basis of entire domestic sales of the above three grades. The adjustments (in \$/MT) are considered on gross domestic price of *** \$/MT for rebate, Inland freight, credit cost, port charge, to an extent of ***, ***, *** and *** \$/MT respectively. The weighted average normal value for 3 grades is considered as *** \$/MT.

Ex-factory export price

The producer/exporter has exported *** MT comprising of above 3 grades which includes *** MT (directly), *** MT (through ITOCHU), *** MT (through Marubeni) and *** MT (through DMCC). M/s Itochu and M/s DMCC have also filed response. For computing the exfactory export price the Authority has considered adjustments (in \$/MT) on Ocean freight, ocean inland, Inland freight, port, credit cost, port charge, bank charge and commission to an extent of ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** and *** respectively on the weighted average CIF of *** \$/MT which leads to exfactory export price of *** \$/MT. The Authority has verified the exports by M/s Itochu to India and notes that the export sales made by them are profitable and also the export sales made by DMCC filed through the questionnaire response were reconciled with the exports volume reported by the producer. In this regard the export price by Marubeni (trader) has been referenced from DG-Systems data to evaluate the weighted average landed value for the responding producer. The weighted average LV for the four channels of producer's exports to India are as under:

Channel	CIF (\$/MT)	LV (\$/MT)
Direct	***	***

Itochu	***	***
DMCC	***	***
Marubeni	***	***

The Authority notes that Itochu has exported goods of both TPC and Vinythai. The Authority has considered the CIF price to India of Itochu for both the producers appropriately for evaluating the overall landed value to determine the injury margin. The profitability in respect of Vinythai's goods is *** % while for TPC is ***% at CIF of *** \$/MT and *** \$/MT respectively. The Authority has referenced DMCC's CIF price of *** \$/MT appropriately for determination of landed value of goods exported by Vinythai during POI.

The Weighted average landed value comes to *** \$/MT.

47. Residual Category

The highest dumping margin amongst the two cooperating producers/exporters is referenced.

F.3.4 <u>Dumping Margin</u>

48. Based on the above the dumping margin are as under:

Producer/exporter	NV	EX-EP	DM	DM%	DM%
China (Cooperative)	(\$/MT)	(\$/MT)	(\$/MT)		range
Yibin Haifeng Herui Co. ("Haifeng Herui") and Yibin Tianyuan Group Co., Ltd. ("Yibin Tianyuan")	***	***	***	***	15-20
CNSG Jilantai Salt Chemical (Group) Co. Ltd. and CNSG Jilantai Salt Chlori-Alkali Chemical Co. Ltd.	***	***	***	***	25-30
Chiping Xinfa Pvc Co. Ltd. and Shandong Xinfa Import & Export Co. Ltd.	***	***	***	***	30-35
Tianneng Chemical Co., Ltd. and Xinjiang Tianye (Group) Co., Ltd.	***	***	***	***	20-25
Tianjin LG Bohai Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	5-10
Tianjin Dagu Chemical Co., Ltd. and Bohai Chemical HK Limited	***	***	***	***	10-15
Xinjiang Sengxiong Chlor-Alkali Co., Ltd. and Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	35-40
Non-Cooperative Residual (Highest)	***	***	***	***	35-40
USA (Cooperative)	***	***	***	***	
Oxy Vinyls LP and Oxy Vinyls Export Sales LLC	***	***	***	***	5-10
Westlake Vinyls Company LP, Axial LLC and Westlake Vinyls Inc.	***	***	***	***	10-15
Non-cooperative/Residual	***	***	***	***	10-15

Thailand (Highest)	***	***	***	***	
Vinythai Public Company Limited	***	***	***	***	5-10
Thai Plastic and Chemicals SCG Performance Chemical Co. Ltd. and SCG Plastic Co. Ltd.	***	***	***	***	5-10
Non Cooperative Residual			***		5-10

49. It is seen that the dumping margins are more than the de-minimis limits prescribed under the Rules.

G. DETERMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

50. The views on injury, likelihood and causality are as under:

G.1 Views of the Domestic industry

- i. Petitioners have not claimed deterioration in performance as a result of imports. Petitioners have not claimed continued injury either. Performance in respect of various economic parameters has improved as a result of ADD in force. Request for extension of ADD is based on likelihood of recurrence of injury in the event of cessation of present ADD.
- ii. Demand has increased over the injury period. Volume of imports from the subject countries as a whole increased over the injury period except the decline in 2015-16. Share of subject imports declined over the injury period with some increase in POI.
- iii. Price undercutting from all subject countries is significantly positive without ADD. ADD in place has prevented any price suppression or depression of the PUC. Considering significant price undercutting, it is evident that cessation of ADD will lead to significant price suppression/depression in the market. Even a small difference in prices becomes significant that a producer can lose an order because of the difference.
- iv. Current level of profits earned by domestic industry is when ADD is in place. Should present ADD cease, profitability would steeply decline as is evident from the level of price undercutting in case of imports from China.
- v. Authority is requested to consider ROI that was earned in the past. If last 15 years are considered, ROI is far below reasonable levels even when the Authority determines ROI on the net present value of the investments (barring last two years). Investments made for PUC are quite old. In case of DCM Shriram and DCW, original plants are largely depreciated. High level of ROI is only because of low level of investments.
- vi. Significant and positive dumping margin implies that profits earned by foreign producers are higher. As far as US is concerned, cost of production is materially lower as compared to producers globally in view of availability of shale gas in US. Despite selling at low prices they earn significant profits.
- vii. On the previous two occasions, the authority found that domestic industry suffered injury. It found material injury in the original investigation and continued injury in the previous sunset review. It is only in the present sunset review that the domestic industry has recovered from injury and has been able to post some profits in last two years.
- viii. Import price from Thailand is lower than the selling price of domestic industry. The price undercutting in case of Thailand is positive. Imports from Thailand are also subjected to a lower BCD of 5% against MFN rate of 7.5% and thus, the impact of lower import price from Thailand is that much higher.
- ix. Post POI data was not provided only because the authority has not called for such information. However, the same has been provided in written submissions.
- x. Price suppression/depression did not exist over the injury period due to ADD in place. Continued injury has also not been claimed. Absence of suppression or depression over the injury period does not imply absence of likely suppression/depression in the event of cessation of ADD.

- xi. Requirement under Para ii of Annexure II and Para vii of Annexure II with regard to suppressing and depressing effects are different. Para ii of Annexure II requires the authority to consider suppressing/depressing effect in the POI having regard to the past i.e. over the injury period; in likelihood of injury examination, the authority is required to consider the prices in the POI and determine whether imports are likely to have suppressing or depressing effects on the prices i.e. potential.
- xii. When petitioners themselves have not claimed continued injury, any submissions with regard to absence of continued injury is of no relevance. The request for extension of ADD is based only on the grounds of likelihood of recurrence of injury.
- xiii. Position with regard to comparison of NIP and NSR is well established. NIP is required to be determined only where the authority is fixing quantum of duty. Present investigation is not an original investigation and therefore quantum of duty is not required to be determined. Comparison of NIP with NSR is entirely immaterial in the present case.
- xiv. Significant capacities are being made by the domestic industry only as a result of the duties imposed. It clearly shows the positive impact of the last two years performance of the product under consideration. The confidence gained by the domestic industry in just two years of reasonable performance shall be totally shattered if the present ADD is completely withdrawn.

G.2 Views of other interested parties

- i. The reason for growth of subject goods from subject goods is the demand for the downstream industry.
- ii. There is no correlation between the cost of sales and the selling price of the domestic industry. The landed price from the subject countries is relatively higher than the other subject countries.
- iii. Price undercutting has no relevance in the present investigation as despite undercutting the domestic industry has improved its profits.
- iv. Capacity, production, utilization as well as sales have increased.
- v. As per the trade notice 10/2018, the petitioners have failed to provide sales value data.
- vi. The profitability has also increased. Since RIL is operating at the highest margins, RIL should also be included in the examination. Injury being suffered is due to other factors as is evident from the annual reports. Even the ROCE is significantly higher than what is usually allowed for by the authority.
- vii. Employment with the domestic industry has increased and the productivity has also shown an increase.
- viii. NSR is more than NIP. All the economic parameters show rising trend. Inventory has increased and increase in inventory does not have any meaning if other economic parameters show improvement. In the present case, price undercutting is not relevant as in spite of positive price undercutting, DI performance has improved a lot.
- ix. In the present case, price undercutting is not relevant as in spite of positive price undercutting, Domestic industry performance has improved a lot. Landed price with ADD from Thailand is higher than highest range of selling price.
- x. No post POI data provided by the Petitioner and no verifiable post POI evidence relating to injury.
- xi. There is no price suppression and depression claimed by Domestic industry.
- xii. Petitioners have claimed to have suffered continued injury. It is the imports from the non-subject countries that have been feeding the increasing demand in the country. Thus the competition of the domestic products is with the subject goods imported from the non-subject countries and not with those being imported from the subject countries.
- xiii. While the import prices declined, petitioners have not been compelled to decrease their prices despite their cost of sales also having reduced. The petitioners were able to increase their prices. This indicates that import prices were not dictating the prices of the petitioners and the increase in profit

- with average ROCE was 50-60% during POI. Subject countries' import prices have not had a price effect on the Domestic industry.
- xiv. The petitioners have shown a significant increase in production with their capacity utilization also being significant. Sales as well as sales realization of the petitioners also increased. In fact the production of other domestic producers also increased.
- xv. Inventories have increased but they are not the sole factors affecting the Domestic industry. They would have mattered if inventories would have increased with no increase in sales. Petitioners have also not suffered injury with respect to employment and productivity.
- xvi. Imports from the subject countries have had no effect on the prices of the Domestic industry and the domestic industry has seen healthy growth in all parameters. Further, even the profits, cash flow and the ROI of the Domestic industry has increased significantly and it is earning significant profits.

G.3 Examination by the Authority

- 51. The injury analysis made by the Authority here under addresses the various relevant submissions made by the interested parties.
- 52. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure–II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, ".... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
- 53. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
- 54. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.
- 55. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.
- 56. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proposes to examine the current injury, if any, to the domestic industry before undertaking to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject countries.

G.3.1 Volume Effect of dumped imports and impact on domestic industry

i. Assessment of Demand/Apparent Consumption

57. The Authority proposes to consider, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources as under:

SN	Particulars (in MT)	2014-15	2015-16	2016-17	POI	Post POI-A
1	Sales of Domestic Industry	3,84,878	3,99,740	4,14,871	4,24,166	3,96,004
2	Sales of Other Indian Producers	7,76,038	8,31,580	7,88,357	7,87,562	7,90,728
3	Imports from Subject Countries	3,40,890	2,01,402	3,29,366	3,51,297	2,45,054
4	Import from Other Countries	8,82,293	12,12,964	12,60,085	12,34,889	11,02,677
5	Total Demand	23,84,098	26,45,686	27,92,680	27,97,914	25,34,463

58. The demand has continued to be increasing and stable at a level of about 28 million MT.

ii. Volume Effect of Dumped Imports and Impact on Domestic Industry Import volume and Market Share

SN	Particulars	2014-15	2015-16	2016-17	POI	Post POI-A
1	Subject Countries (in MT)					
2	China	2,90,122	1,69,114	2,47,949	2,07,289	1,22,724
3	Thailand	35,687	18,100	33,505	1,17,154	50,126
4	USA	15,082	14,188	47,912	26,853	72,204
5	Subtotal	3,40,890	2,01,402	3,29,366	3,51,297	2,45,054
6	Other Countries	8,82,293	12,12,964	12,60,085	12,34,889	11,02,677
7	Total	12,23,183	14,14,366	15,89,452	15,86,186	13,47,731
8	Subject Countries (in %)					
9	China	24%	12%	16%	13%	9%
10	Thailand	3%	1%	2%	7%	4%
11	USA	1%	1%	3%	2%	5%
12	Subtotal	28%	14%	21%	22%	18%
13	Other Countries (in %)	72%	86%	79%	78%	82%
14	Total	100%	100%	100%	100%	100%
15	Subject countries imports in relation to (in %)					
A	Indian Production	26.89%	14.68%	23.59%	25.17%	17.03%
В	Indian Demand	14.30%	7.61%	11.79%	12.56%	9.67%

59. The volume of import from subject countries have increased in absolute term while in relative terms compared with overall imports, production and demand have been slightly lowered. The share of non-subject countries in overall imports have increased.

G.3.2 Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

a. Price Undercutting

SN	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI	Post POI-A
1	China						
A	Landed Price	Rs/Kg	65.59	56.17	57.12	61.09	66.54
В	Net Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***	***
С	Price Undercutting	Rs/Kg	***	***	***	***	***
D	Price Undercutting	%	0-10%	10-20%	15-25%	10-20%	5-15%
2	Thailand						

A	Landed Price	Rs/Kg	69.52	58.36	63.05	63.49	69.61
В	Net Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***	***
С	Price Undercutting	Rs/Kg	***	***	***	***	***
D	Price Undercutting	%	(0-10)%	0-10%	5-15%	5-15%	0-10%
3	USA						
A	Landed Price	Rs/Kg	69.49	55.92	62.33	63.19	68.57
В	Net Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***	***
С	Price Undercutting	Rs/Kg	***	***	***	***	***
D	Price Undercutting	%	(0-10)%	10-20%	10-20%	5-15%	5-15%
4	Subject countries as whole						
A	Landed Price	Rs/Kg	66.17	56.35	58.48	62.05	67.77
В	Net Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***	***
С	Price Undercutting	Rs/Kg	***	***	***	***	***
D	Price Undercutting	%	0-10%	5-15%	15-25%	5-15%	5-15%

60. The price undercutting by imports from the Subject Country is positive without anti-dumping duty both in POI and post POI. The landed price of non-subject countries is higher than the subject countries.

SN	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
1	NSR	Rs/Kg	***	***	***	***
2	Subject countries landed prices					
A	China	Rs/Kg	65.59	56.17	57.12	61.09
В	Thailand	Rs/Kg	69.52	58.36	63.05	63.49
C	USA	Rs/Kg	69.49	55.92	62.33	63.19
3	Other countries landed prices					
A	Taiwan	Rs/Kg	69.00	62.09	65.75	67.42
В	Japan	Rs/Kg	66.14	56.61	61.09	65.64
A	European Union	Rs/Kg	70.59	64.15	66.66	78.86
В	Mexico	Rs/Kg	71.55	37.56	75.11	46.06
A	Indonesia	Rs/Kg	69.39	-	59.10	-
В	Malaysia	Rs/Kg	63.76	-	-	-
A	Korea RP	Rs/Kg	68.10	58.48	63.02	68.48

b. Price Suppression/ Depression

SN	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI	Post POI
1	Cost of sales	Rs./Kg	***	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	89	92	89	99
3	Selling price	Rs./Kg	***	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	92	101	101	108
5	Landed Price	Rs./Kg	66.17	56.35	58.48	62.05	67.77
6	Trend	Indexed	100	85	88	94	102

The selling prices continue be above the cost of sales, in POI and part Post POI.

G.3.3 Economic Parameters relating to the Domestic Industry

- 61. Annexure II to the AD Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.
- 62. Accordingly, various economic parameters of the Domestic Industry are analyzed herein below:

a. Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales Volume

SN	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI	Post POI
1	Capacity	MT	420,000	460,000	460,000	460,000	460,000
2	Trend	Indexed	100	110	110	110	110
3	Production	MT	383,738	403,147	425,679	420,567	416,120
4	Trend	Indexed	100	105	111	110	108
5	Capacity Utilization	%	91.37%	87.64%	92.54%	91.43%	90.46%
6	Trend	Indexed	100	96	101	100	99
7	Domestic Sales Volume	MT	384,878	399,740	414,871	424,166	396,004
8	Trend	Indexed	100	104	108	110	103

63. The domestic sales, capacity and CU show stable and rising to and domestic sales, production and CU are slightly lowered in post POI.

Market Share in Demand

64. The market share of the domestic industry moved as shown below:

SN	Market Share in Demand (in %)	2014-15	2015-16	2016-17	POI	Post POI
1	Domestic Industry	16.14%	15.11%	14.86%	15.16%	15.62%
2	Other Indian producers	32.55%	31.43%	28.23%	28.15%	31.20%
3	Subject countries	14.30%	7.61%	11.79%	12.56%	9.67%
4	Other Countries	37.01%	45.85%	45.12%	44.14%	43.51%
5	Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

65. The domestic industry's market share in demand has remained by and large stable in POI and Post POI. The share of Indian Industry as a whole has lowered in POI being with subject countries share slightly lowered in POI.

Profitability, return on investment and cash profits

66. Performance of the domestic industry with regard to profits, return on investment and cash flow is as follows:

SN	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI	Post POI-A
1	Cost of sales	Rs./Kg	***	***	***	***	***

2	Trend	Indexed	100	89	92	89	99
3	Selling price	Rs./Kg	***	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	92	101	101	108
5	Profit/(Loss)	Rs./Kg	***	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	752	2,810	3,513	2,709
7	Profit/(Loss)	Rs.Lacs	***	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	781	3,029	3,872	2,787
9	PBIT	Rs.Lacs	***	***	***	***	***
10	Trend	Indexed	100	167	368	439	310
11	Cash Profits	Rs.Lacs	***	***	***	***	***
12	Trend	Indexed	100	338	1,104	1,404	1,032
13	ROCE	%	***	***	***	***	***
14	Trend	Indexed	0-10%	5-15%	40-50%	50-60%	35-45%

67. The profitability are quite stable and ROCE, upward looking, during the injury period.

Inventories

68. Inventories with the domestic industry is as follows:

Particulars	2014 15	2015 16	2016-17	POI	Post POI
(in MT)	2014-15	2015-16	2010-17	POI	Post POI
Opening	***	***	***	***	***
Closing	***	***	***	***	***
Average	5,970	4,770	9,022	9,216	9,591
Trend	100	80	151	154	161

Inventories are increased in POI and Post POI but as % of production are not high.

Employment and productivity

69. Performance of the domestic industry with regard to employment, productivity and wages is as follows:

SN	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI	Post POI-
1	Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	105	111	110	108
3	Employment	Nos	***	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	106	109	108	108

70. Productivity and employment show stable trend.

Magnitude of Dumping

71. The Authority has undertaken evaluation of dumping margin for cooperating producers/exporters during POI as stated in the earlier paras.

The dumping during POI from the subject countries both for cooperative and residual producer/exporters are

above deminimis.

Ability to raise Capital Investment

72. Investments being made or planned by the domestic industry as well as other Indian producers as a result of the anti-dumping duties being in force, may be jeopardized if the present duties are allowed to cease.

Magnitude of Injury and injury margin

73. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during the POI and Post POI, and the injury margin are as under:

SN	Particulars	Unit	POI	Post POI
A	China			
1	Non Injurious Price	Rs/Kg	***	***
2	Landed Price	Rs/Kg	61.09	66.54
3	Injury Margin	Rs/Kg	***	***
4	Injury Margin	%	0-10%	0-10%
В	Thailand			
1	Non Injurious Price	Rs/Kg	***	***
2	Landed Price	Rs/Kg	63.49	69.61
3	Injury Margin	Rs/Kg	***	***
4	Injury Margin	%	(0-10)%	(0-10)%
C	USA			
1	Non Injurious Price	Rs/Kg	***	***
2	Landed Price	Rs/Kg	63.19	68.57
3	Injury Margin	Rs/Kg	***	***
4	Injury Margin	%	(0-10)%	(0-10)%

It is noted that injury margin is positive for China for POI and Post POI on overall basis but, negative for Thailand and USA, on overall basis.

G.3.4 Injury margin for cooperative producer/exporter –

74. The injury margin for cooperative producers/exporters are evaluated as under:

Producer/exporter (POI)/NIP = *** \$/MT	LV	IM	IM%	IM% range
China (Cooperative)	(\$/MT)	(\$/MT)	(\$/MT)	
Yibin Haifeng Herui Co. ("Haifeng Herui") and Yibin Tianyuan Group Co., Ltd. ("Yibin Tianyuan")	***	***	***	(0 to 5)
CNSG Jilantai Salt Chemical (Group) Co. Ltd. and CNSG Jilantai Salt Chlori-Alkali Chemical Co. Ltd.	***	***	***	0-5
Chiping Xinfa Pvc Co. Ltd. and Shandong Xinfa Import & Export Co. Ltd.	***	***	***	5-10
Tianneng Chemical Co., Ltd. and Xinjiang Tianye (Group) Co., Ltd.	***	***	***	0-5

Tianjin LG Bohai Chemical Co., Ltd.	***	***	***	(0-5)
Tianjin Dagu Chemical Co., Ltd. and Bohai Chemical (HK) Limited	***	***	***	0-5
Xinjiang Shengxiong Chlor-Alkali Co., Ltd. and Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd.	***	***	***	0-5
Non-Cooperative/ (Highest)	***	***	***	5-10
Residual				
USA	***	***	***	
Oxy Vinyls LP and Oxy Vinyls Export Sales LLC	***	***	***	(0-5)
Westlake Vinyls Company LP, Axial LLC and Westlake Vinyls Inc.	***	***	***	(0-5)
Non-cooperative/ Residual (least CIF of 830 \$/MT)	***	***	***	0-5
Thailand (Cooperative)	***	***	***	
Vinythai Public Company Limited	***	***	***	0-5
Thai Plastic and Chemicals SCG Performance Chemical Co. Ltd. and SCG Plastic Co. Ltd.	***	***	***	(0-5)
Residual / Non Cooperative (Highest – as per best available information) (least export price of 840\$/MT)	***	***	***	5-10

Concluding remarks on Injury

75. It is seen that there has been an increase in the volume of dumped imports from subject countries at dumped prices. Imports are undercutting the prices of the domestic industry. The domestic industry has been able to improve its performance in terms of production, sales, profits, cash profit and ROCE. The Authority holds that the domestic industry is not suffering material injury.

G.3.5 LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

76. The Authority observed that this is a sunset review investigation and the focus of this investigation is to examine the likely scenario of continued dumping and consequent injury if the anti-dumping duties were to be allowed to expire even if there is no current injury.

Views of the Domestic Industry:

- 77. Following are the submissions made by the Domestic Industry with regard to likelihood of continuation of dumping and consequent recurrence of injury
 - i. PUC has a long history of dumping in various markets, including India and countries such as China, Australia, Turkey and Pakistan, where it is currently attracting duties from various countries. The petitioners are recovering from the adverse effects of dumping and are in a vulnerable state.
 - ii. There are significant capacities in China, much higher than their domestic demand. Average operating rate is in the range of 57% to 72% in the last 5 years which clearly indicates that there are significant unutilised capacities in China which can be easily diverted to India, in case of revocation of duties.
- iii. There is a further plan for enhancing capacities by a number of producers in China and there are significant exports from China over the injury period. There are more than 150 producers of PVC Suspension Resin in China. Only seven Chinese producers have filed the questionnaire response of which four are attracting individual duty and three are attracting residual duty. Since the duty amount on residual category of producers/exporters from China is higher than others, a number of producers in

- China are not even exporting the product to India at present. However, after revocation of duties, there is a likelihood that these other producers will also start exporting.
- iv. As per IHS Market (Vinyls) Report, 2017, Chinese producers will likely be forced to divert products into International market to ease pressure from their oversupplied domestic market. Along with the restriction of US market, China would divert its produce further to Indian market and it would keep coming at prices lower in comparison to domestic price of the Indian Industry and the price of imports from other subject countries.
- v. On comparison of imports from China to India in original case, 1st review investigation and present investigation PO show that the share of China in Indian demand has increased from 2% to 7%. Increase in imports from China is far higher than increase in demand. Imports from China have increased in spite of ADD in force for last 10 years and, so there is greater possibility that after revocation of duties, imports from China will increase at a higher rate.
- vi. Exports from China are attracting ADD in various jurisdictions. Measures have been invoked by Pakistan Authorities also. Pakistan imposed duty on basis of exports of 33,097 MT whereas China is exporting much higher volumes to India.
- vii. Price comparison of Indian prices with third countries reveal significant dumping and injury margin and price undercutting on third country basis which clearly shows that the low-priced exports to third countries can easily be diverted to India after revocation of ADD. India has been the top export destination for China in last 5 years.
- viii. Petitioners compared export price to India and third country prices for each Chinese exporter. This has been done separately for producers/exporters who have filed questionnaire response and those who have not filed questionnaire response. Third country prices of responding Chinese exporters are lower than Indian prices. Exporters who account for more than 70% export volumes to India have filed questionnaire response.
- ix. Current level of demand and future likely imports show that India is a major buyer of the subject goods. India commands top position in exports from China.
- x. Prices prevailing in Indian market are attractive for producers in China, as established by (a) current export price to India, and (b) current export price to rest of the world. Every business enterprise is doing business to optimize its top and bottom line, it is evident that foreign producers would not hesitate to divert their third countries low priced sales to Indian market. In the event of cessation of ADD it is evident that Indian consumers would be motivated to switch over to imported product. In PVC suspension market, a price difference of Rs. 500/mt is sufficient for a consumer to switch sources.
- xi. Behaviour of subject countries' month by month import prices from April 2008 till March, 2018 (i.e., 120 months) examined. The entire exercise was undertaken for 120 months from April 2008-March, 2018. It was seen that out of total 120 months, Chinese prices were lowest in 28 months.
- xii. China is currently exporting majority of their exports to India at prices lower than the domestic prices of the Indian Industry. One of the significant exporters of the subject goods is selling at the lowest price in comparison to the prices offered by exporters from other subject countries.
- xiii. Significant capacities are in USA, much higher than the domestic demand in the country. Average operating rate in range of 80% to 86% in last 5 years which clearly indicates there is significant thrust on exports and there are significant unutilised capacities.
- xiv. Comparison of imports shows imports increased in the POI of 1st SSR as the original duty was low. When the duty was increased in the 1st SSR the imports came down in the POI of the present investigation which implies that the duty imposed acts as a deterrent against unfair imports. Further, exports from USA are attracting ADD in various jurisdictions.
- xv. Westlake having lowest duty exported highest quantity to India. Other producers having significant capacities are not exporting to India in significant volumes because of higher amount of ADD imposed on them. Landed price of the imports with highest amount of duty is much higher than the prevailing

- prices in India. There is a strong likelihood that the producers whose prices are uncompetitive in India because of ADD in force will become competitive after revocation of duties.
- xvi. Out of 6 US producers, 4 producers have responded against 2 participating in the previous review investigation. It shows that producers have plans to export in future and so they have participated in the current investigation. Category of 19% non-responding exporters accounts for 1457 KT capacities which is almost half of Indian demand.
- xvii. USA prices to other countries are higher than India, however, export volumes 59,409 MT are at the prices lower than India. There is significant dumping and injury margin and price undercutting on third country basis which clearly shows that low priced exports to third countries can easily be diverted to India after revocation of ADD.
- xviii. Behaviour of subject countries' month by month import prices from April 2008 till March, 2018 (i.e., 120 months) examined. The entire exercise was undertaken for 120 months from April 2008-March, 2018. It was seen that out of total 120 months, prices were lowest among all countries in 49 months. Further, import price from USA were lower than import prices from China in 59 months. USA is exporting the product to India at a price lower than the domestic selling price.
- xix. In a recent development both China and US have imposed additional custom tariffs on each other upto 25%. The same has implications on imports of PVC in both the markets i.e.; China's PVC exports to USA and USA's PVC exports to China. The problem is likely to be compounded for India for the reasons that there are significant exports from US to China (to the extent of about 10% of Indian demand) and export price from US to China is materially lower (by about 90 US\$/MT) as compared to export price from US to rest of the world.
- xx. As regards Thailand, there are significant capacities much higher than the domestic demand in the country.
- xxi. Average operating rate is in range of 83% to 89% in the last 5 years which clearly indicates that there are significant unutilised capacities in Thailand which can be easily diverted to India, in case of cessation of duties. There are significant freely disposable capacities in Thailand.
- xxii. Comparison of the imports from Thailand to India in original case, 1st review investigation and present investigation POI shows that the imports from Thailand increased by 1058% in the current investigation POI. It indicates behaviour of producers that they are continuously exporting even after duty in force for last 10 years. Reduction in duty by USD 6.93/MT in 1st review investigation resulted in increased imports by 1058%.
- xxiii. Exports from Thailand were subject to ADD in various jurisdictions and at present are attracting ADD in Pakistan. Pakistan has imposed ADD on much lower volume of imports as compared to volume of exports to India.
- xxiv. There are two producers who produce PVC suspension in Thailand. In spite of duties in force for last 10 years, export from Thailand has increased significantly because of the reduction in amount of antidumping duties in first review investigations. Further, since both the producers have responded it shows there are future plans for exporting to India.
- xxv. Thailand prices to other countries are higher than India. Significant export volumes are at prices lower than India. There is a significant dumping and injury margin and price undercutting on third country basis which show that the low priced exports to third countries can easily be diverted to India.
- xxvi. Behaviour of subject countries' month by month prices from April 2008 till March, 2018 (i.e., 120 months) show that out of total 120 months, prices were lowest in 17 months. Import price from Thailand was lower than that from China in 38 months. Further, they are also selling at prices below their domestic prices. India commands top position in exports from Thailand with 28% of global exports.
- xxvii. Authority has issued several findings wherein it has considered existence of surplus capacities as one of the parameters showing likelihood. Even the practice adopted globally supports that the investigating authorities consider surplus capacities as one of the major evidences of likelihood of recurrence of injury. This is directly supported by legal provisions relating to threat of material injury.

- xxviii. "Freely disposable production capacities" means much higher capacities than the unutilized capacities. Any capacity beyond domestic demand implies "freely disposable production capacities". Requirement thereafter is to consider the volume of exports being made to other countries.
- xxix. It is evident that Chinese producers are operating at 72-79% capacity utilization and therefore are suffering from significantly under-utilized production capacities.
- xxx. While demand in US has increased and resultantly exports from US have declined from 43% to 39%, US has still exported 27,89,397 MT PVC globally in 2017. Absolute volume of exports from USA is significantly high. USA has exported about 3 lac MT PVC to China. Proposed tariff measures by China is in region of 25% which will make these exports completely unviable. Under these circumstances, the producers in US will certainly face loss of market to the extent of 3 lac MT which constitutes about 10% of Indian demand.
- xxxi. Cost of production of US producers is materially lower as compared to any other country globally because US producers use share gas for production of PVC. The cash cost of producers in US are in the region of 500-660USD. This does not include only the depreciation amount.
- xxxii. Chinese Association has provided no supporting evidence for high utilization. It has not even stated how it represents all Chinese manufacturers of the PUC, whether the statement pertains only to select few companies, or only their members or entire Chinese PVC industry. This association does not represent all Chinese producers. No information on record to show that it is representative of entirety of PVC Suspension Resin producers in China.
- xxxiii. Petitioners' information considers all Chinese producers of PVC Suspension Resin. The evidence shows unutilised production capacities. The interested parties have not been able to establish absence of unutilised capacities in China.
- extiv. Petitioners have not been able to provide relevant information on inventories in view of absence of any public information. However, even the association has not established that the Chinese producers are not faced with significant inventories. Chinese plants are grossly underutilised which in itself is sufficient to show that they can increase their inventories at a short notice.
- xxxv. Petitioners have claimed existence of likelihood on basis of quantified factors, including factors prescribed under the law, and additional factors duly supported with positive evidence in the form of verifiable information; the claim of absence of likelihood by interested parties is based on mere statements. Meaning of positive evidence should be taken in accordance with law and WTO appellate body report in the matter of United States Anti-Dumping Measures On Certain Hot-Rolled Steel Products From Japan.

Views of the Other Interested Parties

- 78. Following are the submissions made by the other interested parties with regard to likelihood of continuation of dumping and consequent recurrence of injury
 - i. The Petitioners themselves have admitted that there is no price suppression or depression. The Petitioners have also admitted that 99% of USA exports to other markets are at a price above the claimed NIP. In other words, even if it is assumed (without conceding) that the removal of duties could lead to USA redirecting its third country exports towards India, it appears likely that those imports would be priced non-injuriously.
 - ii. The concept of surplus capacities as claimed by the domestic industry is wrong. The Indian market is not treated as a favorable destination for exports. Indian market is huge and the domestic capacity alone is not sufficient for meeting such a demand. The population of India is similar to that of China but the demand for polymer is only one-fifth.
- iii. The authority in the past has also declined initiation or terminated the sunset review investigations because of absence of injury/ likelihood of injury. Further, the continuation of the ADD will also not be in public interest.
- iv. The reasons for the continuation of the duty in the previous SSR are no longer applicable in the present scenario.

- v. The data presented by the petitioner on the likelihood of recurrence of injury and dumping is flawed and inappropriate.
- vi. The export orientation of China has been wrongly assessed by the petitioner and there is no basis to their claims. The data is unsourced and thus not reliable. The same is also contradictory to the data of members of the Chlor-alkali industry association.
- vii. The claims on price attractiveness are also flawed. Prices to India and other countries are at par. Declining imports from China indicates their disinterest in the Indian market. Thai and US exporters have higher volumes to third countries at prices higher than what they are being sold at in the Indian Market.
- viii. The claim of India being an export destination is also flawed and false. Again the data provided is unreliable. Further, with the duties being in force for more than 11 years, the trade channels have been realigned and there is no reason to presume that the same would be revised upon cessation of duties.
- ix. In view of the profitability reported by the Petitioners, their extremely high ROCE, the lack of any underselling (based on data provided by the Petitioners), and various other positive economic parameters, there is no case made out for continued or likelihood of recurrence of injury to the domestic industry. In this regard, it is also relevant to note that the import volume from China PR shows a declining trend in absolute as well as relative terms and that the imports from none of the subject countries indicates any price pressure on the domestic producers.
- x. No data pertaining to post-POI period has been brought out even though the 6-month post-POI data was easily available. It is suspected that the Petitioners have procured post-POI data but the same does not support their claims.
- xi. Petitioners compared volume of imports from China with imports from China PR 10 years ago. The methodology fails to consider the overall increase in demand in the last 10 years, which the imports from China have matched. Imports from China PR have shown a declining trend over the period of injury and in the POI and have continued to decline in the post-POI period, based on data of China Customs.
- xii. There are no excess capacities in China and the information of the producers is already on record with the authority. Authority must note relevance of data of the participating members of the Association. The same is representative of Chinese capacities and utilization relevant for the purpose of the present investigation.
- xiii. On basis of the data of participating members of the Association Substantial sales (about 95%) of most members participating are made in the Chinese domestic market or to third country export markets, rather than to Indian market; In the POI, more than 90% of the capacity of most of the members who are participating in the present review investigation was fully utilized with only a minor part remaining unused; There is no "idle" or excess capacity held by the Members of the China Chlor Alkali Industry Association participating in the investigation
- xiv. It is not appropriate to presume that small scale producers in China have been waiting, for 11 years, for duties to be revoked in India so that they can utilize their small-scale operations fully.
- xv. Pricing trends of subject countries run parallel to cost trends of the petitioners, showing that the price variation during the injury investigation period for the subject countries is based on the trends of cost rather than any other factor.
- xvi. China PR is itself the largest consumer of PVC. More than 90% of PVC is consumed domestically by China PR and applied in various fields. China has restricted its supply side capacities and there are restrictions in place against expansion of Chinese PVC capacities, therefore, the growing local demand in China would require it to be more domestic market oriented than export market oriented.
- xvii. Production capacity in China has not increased much over the period of injury. It will be not expanded in the future owing to a recent government policy of "energy conservation and emission reduction". Reference laid on the Government of China notice dated July 23, 2016 by the General Office of the State Council of the PRC Public No (2016) 57, Guidelines on the Restructuring, Promoting Transformation and Increasing Profits of the Petrochemical Industry in support of the same.

- xviii. According to IHS Markit Forecast, the PVC production capacity in the USA will not be growing fast in the coming years, and this year's operating rate is expected to be above 90%. US producers do not have excess capacity to export significantly additional volumes to India for the time being.
- xix. As regards USA, Petitioners have relied on unreliable sources. "significantly excessive capacities" is not part of the analysis of likelihood under the AD rules and therefore untenable.
- xx. As per Petitioners submission, exporters and producers subject to higher duties would export lesser to India and vice versa. However, this does not stand true in the current factual matrix as Formosa Plastic Corporation has a much lower duty than the residual rate and has not increased its exports to India throughout the injury period and in fact has not exported during the POI at all.
- xxi. The Petitioners have admitted that nearly 80% of USA's third country export markets command a price higher than the price at which USA exports to India. The revocation of duties would have no effect in the prices in India nor would it lead to diversion of imports.
- xxii. The Exporters submit that the duties imposed by the sovereign third country is retaliatory in nature and each of the nations have also imposed duties of their own.
- xxiii. Domestic Industry conceded that it is not suffering injury and has recovered from past effects of dumping. The claim that likelihood of dumping and injury exists if ADD is removed is based on rhetorical statements and not backed by supporting evidence.
- xxiv. Reliance on previous investigation does not indicate that injury will continue as the facts and data in the present case have undergone significant changes compared to earlier period. Domestic producers increased capacities continuously during the past 15 years and are in the process of further increasing them.
- xxv. DI claimed that surplus capacities exist in Thailand which outweigh its domestic demand. Firstly, such data being based on IHS Publication, the same is not admissible evidence. Secondly, the data provided therein also includes non-PUC. Thirdly, presence of excess capacities does not indicate that the same would be diverted to India.
- xxvi. Though, DI contended that imports from Thailand increased continuously in last 10 years, the said increase cannot be seen in a vacuum but in the context of proportionate increase in demand which the domestic producers were not capable of fulfilling and secondly, since ADD was in force on such imports, the increase happened notwithstanding the fact that landed value was above NIP of DI.
- xxvii. The allegation that imports from Thailand increased due to reduction in ADD is incorrect as the same is benchmarked against the NIP of the DI. Therefore, imports prices from Thailand would either be equivalent to or above NIP of Domestic industry during the subsistence of the levy in India.
- xxviii. Domestic industry claimed exports to other countries from Thailand were made at higher prices and at lower volumes compared to India with data showing calculations of export price, dumping margin at Annexure 19. Such calculations cannot be relied upon as the source and basis of arriving at such calculations has not been provided and Domestic industry has claimed excessive adjustments without any basis or supporting documents while determining export price.
- xxix. Domestic industry claimed that imports prices from Thailand were lower than China for 38 months in the past 120 months. However, such analysis based on Chinese prices is irrelevant as firstly, it should be based on current injury analysis period and secondly, comparison should be with that of prices prevailing in India.
- xxx. Although Domestic Industry submitted that likelihood of continuation/recurrence of injury entails counter-factual analysis of future events, it failed to provide any information in support such as post-POI information or future projections based on current or planned capacity additions in subject countries, change in pattern of trade etc.
- xxxi. There is no excess capacity in USA. As per World Analysis IHS Markit Report for the year 2018, the producers/exporters in USA are operating at more than 85% of the capacity utilization. The report further states that the capacity of USA producers, specifically SHINTECH, will not increase in coming five years. Thus, there is no excess capacity in USA.

Domestic Industry failed to substantiate likelihood of recurrence of dumping and injury as (i) no xxxii. significant rate of increase (only 3% over injury analysis period) in dumped imports as required under Annexure II Para (vii). Rather, increase in imports of PUC is from non-subject countries viz. Japan despite price being higher than subject countries which establishes that increase/decrease in imports is not dependent on price as a factor; (ii) Domestic industry claimed that capacity in China PR, Thailand, USA increased by 13%, 0% and 9% compared to 2013 which is outside the injury analysis period and therefore, untenable. Rather, rate of increase in capacity over actual injury analysis period is only 2%, 0% and 6% respectively; (iii) increase in capacities and availability of unutilized capacities in no way indicates a likelihood of increased exports to India as data in Domestic Industry's own petition shows that capacities remained the same for countries whose exports to India had increased significantly viz. Japan, Thailand, whereas exports from China and USA went down despite an increase in their capacity; (v) range of surplus capacities is too wide to be meaningfully commented upon and furthermore, no correlation between surplus capacities allegedly held in subject said countries and exports to India in view of data provided in Petition by Domestic Industry; (vii) the Domestic Industry has not substantiated how it is still vulnerable despite earning huge profits (vii) price attractiveness of Indian market as claimed by Domestic Industry is not correct as 81% exports from remaining subject countries to third countries are at prices higher than that to Indian market and neither has source been provided for data furnished by Domestic Industry in their Petition.

xxxiii. Likelihood analysis also entails an objective consideration of current data and whether such data demonstrates that imports are entering India at suppressing/depressing prices. In this regard, even without inclusion of ADD to landed value, imports are entering India above NIP of Domestic Industry (which is around 943 USD) and therefore, no likelihood of recurrence of injury.

xxxiv. Claim of freely disposable capacities in subject countries is baseless for being based on IHS publication which is inadmissible evidence for the reasons stated in the written submissions. Capacities in subject countries have mostly remained constant with only a negligible increase. Nothing on record to suggest that export orientation of exporters and existence of excess capacity would automatically lead to diversion of exports to India

G.3.6 Examination by Authority

79. The Authority notes that the present investigation is a sunset review of antidumping duty imposed on the imports of subject goods and the Authority has to examine likelihood of dumping and injury in the event of cessation of anti-dumping duty. The Authority examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the Rules. Clause (vii) of Annexure II to the rules provides for the following factors:

The injury margin is slightly positive for China for POI and Post POI while negative for USA and Thailand on an overall basis.

Significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation

80. The trend of imports is as follows-

SN	Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI	Post POI (A)
1	Subject countries						
a	China	MT	2,90,122	1,69,114	2,47,949	2,07,289	1,22,724
b	Thailand	MT	35,687	18,100	33,505	1,17,154	50,126
С	USA	MT	15,082	14,188	47,912	26,853	72,204
2	Subtotal	MT	3,40,890	2,01,402	3,29,366	3,51,297	2,45,054
3	Other Countries	MT	8,82,293	12,12,964	12,60,085	12,34,889	11,02,677
4	Total	MT	12,23,183	14,14,366	15,89,452	15,86,186	13,47,731

81. The Authority notes the imports from the subject countries declined in 2015-16 and increased thereafter in the POI. Imports from China and Thailand declined in the post POI. However, imports from China remain significant. Imports from USA have increased significantly and have more than doubled in the post POI. The Authority finds that there is no consistent pattern in the imports, but level of imports continued to be significant.

sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports

82. This parameter for ascertaining the threat of material injury requires evaluation of freely disposable capacities and capacity addition, if any, to explore the possibility of diversion of disposable quantity to Indian market. Domestic industry has claimed that the producers in subject countries are already faced with significant surplus capacities as tabulated below and that these producers are exporting the product to a large number of countries, a very significant proportion of which is being exported at a price below the prices in respect of India, thus showing likelihood of diversion of these exports to India in the event of withdrawal of anti-dumping duty

(Particulars) UNIT: KT/Y	Unit	2012	2013	2014	2015	2016
<u>China</u>			l .	l .	<u> </u>	
Capacity	KT/Y	23,410	24,760	23,890	23,480	23,260
Production	KT/Y	13,416	15,295	16,296	16,092	16,691
Capacity Utilization	KT/Y	57%	62%	68%	69%	72%
Import	KT/Y	1,060	915	808	820	752
Export	KT/Y	395	662	1,111	780	1,117
Demand	KT/Y	14,081	15,548	15,993	16,132	16,326
Growth Rate	%	3%	10%	3%	0.90%	1.20%
Freely disposable capacity	KT/Y	8,934	8,550	6,786	6,568	5,817
<u>USA</u>	1					
Capacity	KT/Y	7,779	7,794	7,884	7,884	8,184
Production	KT/Y	6,719	6,716	6,574	6,622	6,949
Export	KT/Y	3,015	2,903	2,641	2,618	2,776
Demand	KT/Y	3,960	4,071	4,174	4,229	4,373
Growth Rate	%	8.30%	2.80%	2.50%	1.30%	3.40%
Freely disposable capacity	KT/Y	804	820	1,069	1,037	1,035
Exports as % of production	%	45%	43%	40%	40%	40%
Thailand	1					
Capacity	KT/Y	890	890	890	890	890
Production	KT/Y	783	774	792	739	792
Domestic demand	KT/Y	284	289	281	228	177
Exports to World	KT/Y	344	302	339	333	494
Exports to India	KT/Y	47	45	25	45	137
Freely disposable capacity	KT/Y	262	299	270	329	219
Exports as % of production	%	44%	39%	43%	45%	62%

83. The Authority notes that response in respect of Thailand has been filed by both the producers who account for entire production of Subject Goods in Thailand. It is noted that since there is no surplus capacity, for disposal, likelihood has been examined with respect of trade diversion only.

whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports

84. The Authority notes that at the current landed price in India, there is positive price undercutting during POI without considering ADD in place. It is also observed that because of the existence of the present ADD the imports are not resulting in price suppression/depression of the prices of the domestic industry.

Antidumping measures imposed on subject goods and trade restrictive measures being invoked by China and USA

- 85. Domestic industry has submitted that exports from USA are attracting ADD in China and Turkey. The anti-dumping duties have been in force for more than 15 years. The duties have been extended on the grounds of likelihood of dumping and injury. Further, Pakistan has also imposed anti-dumping duties on Thailand. China and US have imposed additional custom tariffs on each other upto 25% which has implications on imports of PVC in both the markets. The Authority has examined attractiveness of Indian market and diversion of third country exports in event of cessation of the Anti-dumping duty as under, considering the comments filed in response to the disclosure.
- 86. The Authority notes that not with standing existing surplus capacities and capacity addition, if any, by the exporters of the subject goods, to determine possibility of diversion of third Country exports being diverted to India, analysis of attractiveness of Indian market and thereby its injurious impact on the Domestic Industry has been carried out as per the methodology stated in the disclosure statement.

H. Price attractiveness of Indian Market- A Likelihood analysis

- 87. The Authority notes that the dumping margin for all co-operative producers/exporters during POI are above deminimis as stated in foregoing para. The Authority notes that the injury margin in respect of cooperative producers/exporters from USA during POI and post POI are negative, while for Thailand, the injury margin is negative for TPC/SCG group and positive for Vinythai in POI and post POI. In case of China, on an overall basis the injury margin is slightly positive both for POI and Post POI. Therefore Authority has examined likelihood of injury only after taking into account comments of other Interested parties on aspects of dumping and likelihood of injury including the post disclosure comments.
- 88. The Authority notes that the petitioner had provided global export data from trade map for the POI and post POI for the three subject countries. The other interested parties have submitted that the data provided by the petitioners is an aggregate data and not transaction wise. Therefore this data is not realistic and cannot be adopted for likelihood analysis.
- 89. The Authority notes that the petitioners have submitted that the third country transaction wise data for POI and post POI provided by cooperating producers/exporters in a non- confidential version is not meaningful and that all is kept confidential and they can not react to the same. Petitioners have further provided monthly aggregate data for POI and post POI for all the subject countries and producer wise data in case of China, vide letter dated 14-06-19. The Authority notes that this data is correlated on gross basis with the trade map data provided by them as was stated in the disclosure. However the data of cooperating producers/exporters and trade map has only been adopted. As regards contention of one of the interested party as to why WTA's data has not been adopted the Authority clarified that WTA is not transaction wise data and Authority has correlated the trade map data on a gross basis with the WTA data to validate the trade map data.
- 90. The Authority notes that the trade map data provided by the petitioner is monthly data of global export to various destinations has validated the trade map data provided by Domestic industry with the WTA data available with DGTR on an aggregate basis POI and post POI to justify adopting the trade map data.
- 91. To validate if the monthly aggregated data of trade map adopted by the petitioners is credible and representative, the Authority undertook the analysis of third country transaction wise data for cooperating producers/exporters during POI and post POI. Since the cooperating producers/exporters represent about 50% of exported volume to India from China, 80% from USA and 100% from Thailand during POI, their

- analysis is considered as representative even for the non-cooperating producers/exporters from respective subject countries as well.
- 92. Keeping in view the above and observation of various interested parties that the trade map data adopted by the domestic industry is at monthly aggregate level, the Authority has undertaken the analysis on the third country transaction wise export data provided by the cooperating producers/exporters, both during POI and post POI.
- 93. The Analysis is undertaken firstly to evaluate extent of attractiveness of the Indian market in event of cessation of existing anti-dumping duty and thereafter which all transactions would be injurious to the domestic industry in India. For this purpose, the Authority has considered the following as was stated in the disclosure statement.
 - a. Exports by cooperating producers/exporters to countries other than India during POI and their likely diversion to India on cessation of existing measures and thereby adverse impact on the DI. For analyzing the extent of diversion, the export prices to countries other than India which are lower than export prices to India would find Indian market attractive for diversion and if the landed values of such diverted exports are lower than the NIP they have been considered injurious.
 - b. The aforesaid methodology is also applied on the third country exports by cooperating producers/exporters during the post POI in addition to the analysis undertaken for POI.
- 94. The analysis of likelihood is undertaken only for 'likelihood of injury' since existence of dumping has been established during POI for the cooperative producers/exporters as stated above. The residual/non cooperative producers/exporters by application of best available information are also evaluated as dumped. The attractiveness and diverted exports which may be injurious is evaluated at the country level though the same has also been considered individually at the cooperating producer/exporter level. The extent of attractiveness and likely to be diverted exports which are injurious evaluated for a subject country for the cooperating producer/exporter is applied to the global exports (excluding India) of the subject country as per the trade map data. The trade map data has been appropriately correlated on an overall basis with the WTA data as stated above. However since in Thailand there are only 2 producers both of whom have cooperated, the consolidated data of these 2 cooperating producers/exporters have only been referenced without recourse to trade map or WTA data.
- 95. To evaluate market attractiveness for India the following has been considered as stated in the disclosure statement.

A.

- 1. Transaction wise FoB export price of a cooperating producer/exporter to countries other than India.
- 2. The available FoB price is adopted or else FoB is computed from the CIF price with the freight as claimed or else by considering average freight of all third country transaction of the cooperating producer/exporter.
- 3. Further the aforesaid average freight is compared with average freight to India from that subject country and the lower of the two is adopted. This is to ensure that extent of attractiveness of diversion is not inflated and only conservative estimates are applied to evaluate attractiveness.
- 4. The FoB price of a cooperating producer/exporter so referenced above is compared with FoB price to India for that particular month.
- **B.** In the second stage of analysis, to evaluate injurious exports from the likely to be diverted exports from the third country, the 'landed value' of such third country's FoB export price of a producer/exporter is computed by adding ocean freight as reported by the cooperating producer/exporter and thereafter adding 0.05 % ocean insurance to India and also the BCD and cess on the assessable value.
- 96. The landed value has been then compared with NIP of POI and also during post POI. The proportion of injurious exports as evaluated for cooperating producer/exporter has then been applied at the global level as done for evaluating attractiveness at global level as stated in paras above.

- 97. On the basis of the above, the likely injurious imports evaluated as the proportion of total demand of subject goods in India during POI and post POI are; 10-20%, 30-40% and 0-10% respectively for China, USA and Thailand. For Post POI these proportions are 5-15%, 70-80% and 0-10% respectively.
- 98. On the basis of the domestic industry's data, the likely injurious imports evaluated as the proportion of total demand of subject goods in India during POI and post POI are; 10-20%, 5-15% and 0-10% respectively for China, USA and Thailand during POI. For Post POI these proportions are 5-15%, 10-20% and 0-10% respectively.

I. Post Disclosure Comments

- 99. M/s Westlake Vinyls Company LP (Producer and Exporter); M/s Axial, LLC(Related Producer); M/s Westlake Vinyls Inc. (Related Producer) represented by M/s Seetharaman & Associates
 - i. DA has wrongly rejected the domestic sales made by the Respondents to their affiliated buyers for the purpose of the OCT test. There is no prescription in law which either mandates or allows for rejection of sales to affiliated buyers simply on the basis of price variation. In the previous SSR-I, domestic sales to both affiliated and unaffiliated customers were considered together for calculating the normal value. The variation in selling price between affiliated and unaffiliated buyers is in the range of ***% which is nominal and under no circumstances can it be considered as high or abnormal leading to rejection of the same.
 - ii. The cost of VCM, SGA has been increased 'suo moto' by the authority without assigning any reasons whatsoever and also without disclosing the basis for the revisions made. There is no universal principle that SGA costs shall be allocated based on 'sales turnover'.
 - iii. The costs presented by an exporter or producer shall be accepted so long as they are based on the records maintained by the exporter and such records are in accordance with the GAAPP. A number of working sheets and statements including extracts from accounting records resented earlier shows that the cost presented our reasonable.
 - iv. Ethylene and Chlorine in their Chlor-Alkali division and when the said items are transferred to 'PVC division', it is recorded at transfer price. The profit is notional and thus needed to be adjusted however the same have been rejected.
 - v. Authority has divided total cost of sales of M/s Westlake Vinyls Company and Axiall LLC by total production instead of total sales quantity to arrive at per unit cost. Production quantity is lesser than sales quantity due to which per unit cost arrived by the Authority is higher.
 - vi. Authority has stated the weighted average ex-factory cost of production to be USD *** per MT which seems to be a typographical error. It seems the DA has actually adopted weighted average ex-factory cost of production as USD *** per MT. This has resulted in ***% of domestic sales to unaffiliated traders being considered as profitable. Secondly, the figure of USD *** per MT is incorrect as the correct figure should be USD *** per MT, which will result in approximately *** profitable domestic sales to unaffiliated traders.
 - vii. For trade diversion of low priced subject goods from their existing markets to India, the price capable of being fetched in India must be substantially higher that the price fetched in third countries which has no relationship with NIP. Further, the market size should be large enough and must also have potential for further growth. in so far as the producers and exporters from USA are concerned, the possibility of trade diversion in case of revocation of anti-dumping duty does not arise as they have other important, larger and established markets for export in which demand is still growing whereas India, which accounts for only a very small portion of its exports, is stagnating.
 - viii. The propensity for trade diversion does not depend upon prices being lower than the NIP rather, it depends on factors such as quality of the product and delivery times. Otherwise, imports from countries not subject to the investigation would not have entered the domestic market in such significant volumes.
 - ix. The production quantity of Reliance and Finolex assumed by the DA based upon which it has determined that the Petitioners qualify as Domestic Industry have to be proved by Reliance and Finolex themselves or on the basis of some other public documents.

- x. Several earlier observations of the Authority held that in view of the upturn in trend of profitability and other parameters, the ability of the Domestic Industry to raise capital investments was not marred. However the Authority has observed the contrary in this case.
- xi. Considering the fact that freely disposable capacities determined for USA are not much higher than that of Thailand, the DA is requested to observe that no surplus capacity exists with producers in USA as it has held for Thailand.
- xii. Through letter dated 5/7/2019 M/s Seetharaman Associates have stated that Since as per the union Budget 2019-20, the pre-budget effective rate of BCD on PUC (3904 and further 8 digit classification thereunder) has been increased to 10 % from 7.5%, DA should revise the landed value w.r.t increased BCD of 2.5% while determining injury margin and possibilities of likelihood.

100. M/s Oxy Vinyl/Oxyde Chemicals/Tricon/ICC Chemical Corporation represented by ELP

- i. The Petitioners should have filed updated import data specifically for the post Period of Investigation either at the time of the initiation or within 40 days post initiation and not at such a belated stage of the investigation. Non-provision of said post-POI information by Petitioners in initial stages of the investigation has impacted the rights of the interested parties under Rule 6.
- ii. As regards the inclusion of the complete Chapter 3904 to be considered, the same would be irrational as validly of the duty remains payable on the product and not based on classification and further there are other products which are not within the scope of the present review) which fall under the classification.
- iii. it is unfair that the Authority expects participating producers and exporters to represent 70-80% of their sales to India for determining the dumping margin but does not require the maximum participation of the Domestic Producers in India to determine the Domestic Industry. This is considering the observation made by the Supreme Court in *Designated Authority vs. Haldor Topsoe*, wherein it has been noted that Designated Authority can draw an adverse inference if the information sought is not filed by an interested party.
- iv. Further, even in case of an assessment of likelihood, there are various factors where the cost, price and performance of the domestic industry is relevant thus the standing and scope of domestic industry becomes relevant even in likelihood of recurrence of injury.
- v. If the domestic industry is constituted after excluding parties whose inclusion would otherwise reflect a lower NIP and cost, the assessment of likelihood is bound to be distorted.
- vi. The lack of interest by RIL and FIL likewise supports the conclusion that such imports are not likely in the future to threaten injury to the domestic industry.
- vii. It is unfair to levy duties on imports from USA when POI imports from the USA account for less than two percent of total imports and various other sources of imports are coming in at substantially higher volumes and comparable or lower prices.
- viii. Inclusion of USA and the exclusion of the other countries while in the context of similar market and economic facts is untenable.
- ix. Authority has stated that all the involved companies have filed "their relevant questionnaire responses, and also filed post-POI sales data to India and other countries." In this behalf, it may be noted that the Exporters also filed data pertaining to sales to third countries for the period of investigation.
- x. The post-POI injury data of the Petitioners clearly indicates that even though imports from USA have increased, there has been no adverse impact on the Petitioners' performance.
- xi. The injury margin is negative for USA in the POI and post-POI period. Therefore, even though there is an increase in import volumes, these imports are non-injurious to the Petitioners.
- xii. The decline in the market share of the Petitioners is the result of an increase in imports from "other" countries not subject to this investigation.

- xiii. Even if duties on USA as a whole are continued, the Exporters should be accorded an individual rate of duty based on the dumping or injury margins (whichever is lower). Since the present case is a sunset review, the *mutatis mutandis* incorporation of Rule 17 of AD Rules under Rule 23(3) of AD Rules must also be borne in mind. In the alternative, even if the duties are extended based on recurrence of dumping or injury, the duties for the Exporters should be zero as per the injury margin.
- xiv. the product under consideration is a chemical product, and it is well understood that a capacity utilization rate of 85-90% is considered well above optimal. Thus there is no capacity kept idle to be utilised for exports to India.
- xv. It is not clear why the Hon'ble Designated Authority did not use the World Trade Atlas data itself.
- xvi. The source of the data filed by petitioners on 14-06-2019 has not been provided so as to conclude the authenticity of the same. The Incoterms of these exports (whether CIF, FOB or any others) are not indicated anywhere in the said filing, the data provided appears to be selected based on broad HS Code headings at the 6-digit levels, whereby it is not clear how the data has been sorted to exclude non-PUC details. Thus for lack of clarity such data should be rejected.
- xvii. The price attractiveness analysis forms an "essential fact" in the present review investigation, whereby the same should be disclosed at least in a non-confidential format. Non disclosure of this is in violation of Rule 16 and principles of natural justice.
- xviii. Authority has concluded that 30-40% of the demand in India can be met by injurious imports from USA producers as per the period of investigation data and for the post-POI period, the range increases to 70-80%. However, the price at which USA producers / exporters are selling to India are clearly well above the Petitioners' non-injurious price for the POI as well as the post-POI period.
- xix. Price attractiveness is merely one of the parameters to be considered for likelihood. A holistic view of the parameters of likelihood needs to be taken. USA diverted the trade to India in post POI however increased its price which is non injurious thus even if export is diverted to India it will be at non injurious price. The increase in exports to India came as a result of decreasing exports to other countries where prices were lower than price to India.
- xx. The Exporters would only benefit from switching their market if they could sell the product to India at a higher price.
- xxi. The long-standing duties from USA and China does not have any impact on the factors of likelihood.
- xxii. Annexure referred by petitioners also states "Impact Seen Limited for PVC" and that "the impact of China's tariffs would be limited for PVC, even though the US is a key PVC exporter to China." Thus, the USA-China tariffs have not had a major impact on PVC trade.
- xxiii. M/s ELP through letter dated 9/7/2019 have stated that Since as per the union Budget 2019-20, the pre-budget effective rate of BCD on PUC (3904 and further 8 digit classification thereunder) has been increased to 10 % from 7.5, DA should revise the landed value w.r.t increased BCD of 2.5% while determining injury margin and possibilities of likelihood. The impact on likelihood and injury margin may be undertaken accordingly.

101. M/s Vinythai Public Co Ltd, Thailand represented by M/s Seetharaman & Associates

- i. There is a typo at first line of para 46 (in relation to normal value), wherein one of the grades is mentioned as grade 201, instead of 261 which may be corrected.
- ii. Relevant data in respect of calculations relating to 'market attractiveness' analysis, details of 'Insufficient justification' found by the authority to not initiate the investigation in respect of EU, Mexico, Indonesia, Taiwan, Japan and Malaysia, data supporting the observation that subject countries possess 'free disposable capacities', details supporting the observation that China and USA have imposed additional tariffs of upto 25% on each other, have not been disclosed.

- iii. The Authority is not just supposed to disclose methodology but is also required to provide price attractive calculations (in a confidential manner to the respective parties concerned in respect of their data and in a non-confidential manner in respect of data of other parties). Not disclosing the detailed calculations for 'market attractiveness' analysis, is against the provisions of Rule 16 of AD Rules.
- iv. Imports from Thailand during POI was only 7% of the total demand and during post-POI, it was 4% of total demand. The observation of the authority that injurious imports from Thailand account for 0-10% of total demand (both POI and post POI) would indicate that almost all imports from Thailand are injurious. This appears to be erroneous as the injury margin is negative for the major exporter from Thailand as well as for the country as a whole.
- v. The Authority has not examined whether all the exports at lower prices would be diverted to India. There is no reason why a country would shift volumes from one low-priced country to another low-priced country. The propensity for diversion of volumes from other countries to India would not depend on just the price.
- vi. It is not appropriate to assume that all volumes of exports to other countries that are below NIP would be diverted from those countries to India.
- vii. Trade diversion analysis or market attractiveness analysis should take into account, at the least, the factors such as
 - a. Capacity, including excess capacity in the export market(s) from where the possibility of diversion is being considered.
 - b. Demand, including likely growth in demand for the product in the market(s).
 - c. Low priced imports as a percentage of total imports of the product in the market(s) concerned.
 - d. why Indian market is more attractive compared to the existing third country market or vice versa given that the prices are low in both markets.
- viii. The Authority cannot merely state that there was insufficient justification, without providing the actual reasons for not initiating cases against certain countries which are similarly placed to Thailand.
- ix. It is not known whether imposition of additional customs tariffs by US and China covers subject product or not.
- x. It appears that petitioner's lowest possible net sales realization (derived based on disclosure made), i.e., Rs. 66.7/kg, was also higher by 5% as compared to the highest possible NIP (Rs. 63.5/kg) during the POI. Thus, petitioners were earning much more than their own cost to make and sell and hence were not suffering any injury.
- xi. The situation gets better during post-POI as petitioner's lowest possible net sales realization (Rs. 69.4/kg) was higher almost by around 10% as compared to the highest possible NIP (Rs. 62.5/kg) during the post-POI period.
- xii. The price underselling or injury margin for Thailand was negative during POI as well as post-POI.
- xiii. There is no support from the 70% of the total Indian industry who were participating in the original investigations.
- xiv. In Seamless Tubes and Pipes from China PR is applicable in the present case, domestic industry held only 27% of total Indian production, in absence of any information received from the supporters, the injury and causal link analysis could not be carried out by the Authority.
- xv. It is not clear whether the 62MT stated in the disclosure statement relates to POI or entire injury period. Further, assuming the volume to be negligible it may be considered that since the applicants were aware of the fact that they would be filing a petition for continuation of anti-dumping duty, it is possible that Axiall Shriram stopped or restricted imports during the POI. It is not discernible from the disclosure statement whether DA examined the post-POI trend of imports made by Axiall Shriram or not.

- xvi. Authority has not explained as to what is meant by the term 'technical nature' in relationship. It appears that the Authority has not undertaken any further examination in respect of the fact whether the relationship between two entities did cause the producers to behave differently from non-related producers.
- xvii. All imports made by Shriram Axiall should be removed while considering the volume and price effect as well as market share of imports for a fair analysis.
- xviii. Sunset review was not initiated by the Authority on suo moto basis rather has been initiated on the basis of application submitted by domestic producers who claim to be Domestic Industry within the meaning of Rule 2(b) and on the Authority determining the jurisdictional fact that applicants constituted major proportion at the stage of initiation. Thus, while issuing final findings, it must be ascertained whether the applicants actually constitute a major proportion.
- xix. Respondents differ with the determination that in examining the likelihood of recurrence of injury, the information of exporters is more pertinent. in order to examine likelihood of recurrence of injury to the domestic industry, it is pertinent to examine the existing and forecasted performance of the entire domestic industry of PVC in India.
- xx. The volumes from other countries, which are causing adverse volume effect to the petitioners, if any.
- xxi. There has been a steep decline in exports to India by Vynthai between POI and post-POI period. Exports to India have almost stopped during the post-POI period. Ex-factory export price to India during the post-POI period is higher than the price in POI, there is no likelihood of dumping.
- xxii. Vynthai have a significant established market in other countries, while India is a very small market. The small Indian market further shrunk even more post-POI as exports to India reduced by almost 91% as compared to POI, thus Indian market is not attractive.
- xxiii. DA has undertaken extensive analysis of exports made by the exporters from subject countries, however, no similar exercise has been undertaken in respect of determining whether petitioners are in themselves likely to suffer any injury or not however have not examined the projections and further developments in the Indian industry. When trade diversion from subject countries is not only limited to participating producers and exporters, then the same standard should be applicable in case of Indian industry as well.
- xxiv. Authority has sufficient powers to request requisite excise/GST Commissionerate/MCA to provide information about each of the Indian domestic producers in terms of their production, sales as well as annual accounts. Further, companies after crossing a certain threshold limit as provided in Section 148 of Companies Act 2013 read with relevant rules are required to file cost audit reports with Ministry of Corporate Affairs. Since the filing is made to a statutory authority, the DA has enough powers to request for the said data and examine the same.
- xxv. DCM Shriram has had a profitable post POI period insofar as Chlor-vinyl segment is concerned as not only their profits increased on year-to-year basis, but also on quarterly basis.
- xxvi. Chemplast Sanmar, recently (post-POI) began trial production at its new plant in Cuddalore, which has a 170,000-tonne capacity PVC project.
- xxvii. RIL achieved the highest ever quarterly production of PVC, that too, around 190Kton in one quarter, which is almost 45% of total production achieved by all petitioner companies put together for the entire year.
- xxviii. Production achieved by RIL in one quarter is more than total imports from Thailand during the POI as well as post-POI put together. With such gigantic producer existing in India itself, which is also making profits, it is surprising to note that the DA wishes to undertake elaborate examination in respect of relatively paltry percentage of exports from subject countries to determine trade diversion and resultant likely injury to the petitioners.
- 102. M/s Itochu (Thailand) Ltd. and M/s Itochu Plastics Pte. Ltd represented by M/s WTC Consultants

i. Authority has not granted separate rate of dumping margin and injury margin to participating cooperating exporters. though the questionnaire response is required to be filed by both the exporters and producers for calculating the Net Export Price (NEP). The interest of the exporters is not taken into consideration which avert them to file the questionnaire response. The producer specific practice needs to be modified/changed keeping in view the interest of the exporters.

103. M/s Thai Plastic and Chemicals PLC (Producer); M/s SCG Plastic Co. Ltd. (Related Exporter) and M/s SCG Performance Chemical Co. Ltd (Related Exporter), Thailand

- i. There is an unintentional typographical error and that the normal value ex-factory should read (xxx) and not in Thai Baht per MT for TPC.
- ii. Rejection of allownaces is disagreed upon. There is no training expense involved. On the issue of foreign exchange gains (commercially sensitive and it reveals the marketing strategy of SCG Plastics Co., Ltd. & SCG Performance Co., Ltd.). Export rebate represents a duty draw back system and it is reimbursed on exports. As such, the rebate should be added on to export price to ensure a fair comparison and not deducted.
- iii. TPC is unable to reconcile the export ex -factory prices in that if we based on the spread sheets sent in the confidential disclosure.
- iv. The policy of TPC is to remain present on our core markets which precludes moving their exports from another market to India as can be seen from the volume of sales from 2014 to present which shows that their exports to third markets has remained stable over the years with relatively minor increases in the period 2018 onwards. They will not sacrifice customers in other countries simply to export more to India.
- v. Post POI exports have declined with negative injury margin. ADD must be terminated against Thailand as none of the parameters indicate that there exists likelihood of dumping and injury by Thailand exports.
- 104. M/s Tianjin LG Bohai Chemical Co. Ltd.(Producer), M/s Tianneng Chemical Co., Ltd (Producer), M/s Xinjiang Tianye (Group) Co., Ltd (Related Trader), M/s Tianjin Dagu Chemical Co., Ltd (Producer), M/s Bohai Chemical (HK) Limited (Related Trader), M/s Xinjiang Shengxiong Chlor-Alkali Co., Ltd (Producer) and M/s Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd (Related Trader) represented by LKS
 - i. Authority has noted the names of Bohai Chemical (HK) Limited and Xinjiang Shengxiong Chlor-Alkali Co. Ltd. have been noted incorrectly.
 - ii. If the Authority recommends for continuation of duties, then the Authority must follow the lesser duty rule and recommend continuation of duties based on the lesser of the dumping or injury margin as determined in the present sunset review investigation.
 - iii. In the First SSR duties were modified upwards based on the determinations made. Thus, the Authority in the present investigation cannot simply continue the same duties.
 - iv. The participating producers in the present review investigation and those in the previous sunset review are different and individual margins must be assigned to those parties which have participated in the present investigation.
 - v. The parties named at serial number 15 and 16 in the previous SSR investigation notification have undergone change in name and have participated in the present investigation as well. Continuation of the previous customs notification would bind the participants to residual rates of duty, despite active participation in the previous sunset review investigation as well as the present one.
 - vi. Despite DCM Shriram having a related importer who is importing from Thailand and other countries as well as a related producer who is a significant exporter from USA and in collaboration with whom it owns the related importer, the DA has disregarded all imports and exports by related parties and held the petitioner as an "eligible" constituent of domestic industry.

- vii. In case DCM Shriram Limited is discarded as an eligible domestic producer, the remaining producers would not be able to establish 25% standing because of which DCM Shriram have been included in the scope of DI.
- viii. The identification of a holistic domestic industry is a critical starting point for assessing injurywhether continued or likely to recur.
- ix. In the original investigation, the Authority had noted that RIL is a major producer and had insisted on the inclusion of its data for the purposes of injury assessment, which it had to file later on. It also participated in subsequent review investigations, thus this sudden lack of investment in the ongoing investigation merits consideration by the Authority.
- x. RIL is the most efficient of the domestic producers, and inclusion of RIL's data would significantly impact NIP. Thus its participation is critical.
- xi. Even in SSR cases Domestic industry participation becomes relevant at SSR stage as NIP determined is being used for likelihood analysis which is based on inefficient domestic producers.
- xii. It is possible that the reasons for which investigation was not initiated *qua* other countries may be equally applicable to the subject countries also, but such assessment is not possible in view of non-disclosure of the reasons by the Authority for non-inclusion of other countries who are attracting ADD and have higher share of volume of imports.
- xiii. Authority has stated with regard to cumulation that separate information for the three countries is on record with likelihood analysis separately undertaken for each country but completely failed to address it in the context of assessment of continued injury.
- xiv. Authority has considered prices from Korea to be a "feasible option" for the purposes of normal value from China PR, without any request for information from Korean producers, without any request for comments from Respondent pertaining to the acceptance of Korea as a surrogate country and without any opportunity to consider the normal value at all and despite all this it has actually constructed normal value on the basis the cost of production of domestic industry.
- xv. Authority to break down the construction of the Normal Value- prejudicial to the Respondent- and explain which element of cost pertains to Petitioners and which ones are taken from international sources.
- xvi. The continuation of an anti-dumping duty is an "exception" to the otherwise mandated expiry of the duty after five years as noted by WTO AB Report in *US Carbon Countervailing Duties on Certain Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products from* Germany.
- xvii. The Authority should either rely on the post-POI data or should completely leave the data aside. This picking and choosing of the data is unacceptable. Usage of words such as "slightly lowered" shows bias and should be refrained.
- xviii. The Authority must compare the import prices after addition of anti-dumping duties for undercutting and injury margin. Once ADD is added to the landed value of the subject countries, it becomes evident that the price levels of the subject goods are comparable with the price levels of imports from all other sources, and even comparable /higher than the NIP of the Petitioners.
- xix. Injury margin with respect to USA and Thailand is negative, at price levels of Rs.63.19 in the POI. Therefore, it is clear that imports from China at the price level of Rs. 61.09 have an injury margin of about 1%. There is no current injury or likelihood of injury on account of imports from China.
- xx. Authority should disclose the methodology of calculation of Non-Injurious Price and also, reconsider the same.
- xxi. China's share in total demand amounted to 12.17% in 2014-15 and which declined to 7.41% in POI and further to 4.84% in the post-POI. It cannot be considered as "significant" by the Authority, particularly when the share of non-subject countries in Indian demand amounts to 43.15% in post-POI.

- xxii. The data based on IHS Reports is incorrect- as the producers accounting for entire production of subject goods in Thailand have participated and established that there is no surplus capacity. Thus the same is likely to be incorrect for other countries.
- xxiii. Authority has not disclosed the basis of adoption of a new methodology for consideration of "price attractiveness" of Indian market.
- xxiv. The statement that "the Authority notes that the trade map data provided by the Petitioner is monthly data of global export to various destinations has validated the trade map data provided by the domestic industry with the WTA data available with the DGTR on an aggregate basis POI and Post POI to consider adopting the DI's data appropriately" is not clear at all.
- xxv. Individual transactions, picked and chosen for their "low" values, may represent specific contractual reasons such as being part of a long term contract, subject to shorter credit periods, related company transaction, part of a specific arrangement between producers/exporters and third party importer. In such a case, the discarding of average prices in favour of specific transactional prices appears to be without justification.
- xxvi. Imposition of these additional tariffs by USA against imports by China did not lead to any increased imports from China to India.
- xxvii. While there is a proposal to conduct various methodologies for price attractiveness- no data or facts pertaining to the same have been provided. Provision of methodology is one essential fact, but the data and trends before the Authority in this regard are also essential facts.

J. Brief of Domestic Industry Comments

- 105. i. Imports in relative terms declined till 2015-16 and increased thereafter in the POI. Imports have shown some decline in post POI as imports from other sources increased, however, the same remains significant. Further, imports in relative terms declined till 2015-16 and increased thereafter in the POI.
- ii. The ADD in place has prevented price suppression or depression in the domestic market. However, considering significant price undercutting in the product under consideration, it is evident that cessation of existing ADD will lead to significant price suppression / depression in the market.
- iii. Even a small difference of Rs. 500 PMT in product under consideration become so significant that a producer can lose an order if the price difference is found by consumer in the range of Rs. 500 PMT.
- iv. Profitability, cash profits and ROI have shown increase in the injury period. The current level of profits earned by domestic industry are in a situation where ADD is in place on product under consideration.
- v. If last 15 years is considered, it would be seen that the ROI of domestic industry is far below reasonable levels considered by the Authority even in a situation where the Authority determines ROI on the net present value of the investments (barring last two years).
- vi. The investigation has shown that the percentage of injurious exports that is likely to be diverted to India from USA is much higher than what was claimed by the domestic industry. Further, the Authority has stated that the price attractive analysis is not inflated and only conservative estimates are applied to evaluate attractiveness. This indicates that actual volume of must be significantly high posing threat of injury in the event of cessation of duties.
- vii. Exports from USA are attracting ADD in China and Turkey. The anti-dumping duties have been in force for more than 15 years. The duties have been extended on the grounds of likelihood of dumping and injury.
- viii. Pakistan has imposed anti-dumping duties on Thailand. Pakistan has imposed antidumping duty on much lower volume of imports as compared to volume of exports to India.
- ix. China and US have imposed additional customs tariffs on each other upto 25% which has implications on imports of PVC in both the markets.

- x. Behaviour of subject countries' prices considering month by month import prices from April 2008 till March, 2018 (i.e., 120 months) shows that out of total 120 months, Chinese prices were lowest in 28 months, while import price from USA were lower in 59 months and import price from Thailand were lower in 38 months.
- xi. Subject countries are currently exporting majority of their exports to India at prices lower than the domestic prices of the Indian Industry.
- xii. Since injury to the domestic industry is based on the likelihood of recurrence of injury to the domestic industry, any modification to the quantum of duty would not be appropriate. There can be injury margin only when there is an injury. If there is no injury, there can be no injury margin. Extension of existing anti-dumping duty is also fully permissible within the meaning of Section 9A(5).
- xiii. Anti-dumping duty may be imposed only as fixed quantum of anti-dumping duty (fixed form of duty), expressed as duty in US\$/MT.

K. Examination by Authority

106. (A) The Authority after examining the submissions on imports by M/s Shriram Axial reiterates that the imports made by them are extremely insignificant which may warrant exclusion of M/s DCM Shriram Ltd. from the scope of the Domestic Industry. None of the other Indian producers have opposed the petition. The Authority holds that the petitioning companies meet the standing threshold. The non-participation by M/s RIL and M/s Finolex can not be considered as a constraining factor for evaluating injury to the petitioning companies both in POI for material injury or post POI for a likelihood analysis, since the injury evaluation has to capture both volume effect and price effect. The evaluation of likelihood of diversion of third country exports to India as a volume effect is not impacted by the non-participation of M/s RIL and M/s Finolex. The Authority notes the submissions regarding petitioner domestic industry not having filed post POI data along with the application initially but later i.e. on 25/2/2019. The Authority notes that producers/exporters also filed the same data later after the oral hearing. The Authority has also considered and addressed the submissions made by certain parties in July 2019 after the last date to file the comments to the disclosure to factor in the recent increase in basic customs duty on subject goods while undertaking likelihood of injury analysis.

(B)

- i. The Authority notes the submissions of M/s Itochu (Thailand) Ltd. and M/s Itochu Plastics Pte Ltd., Singapore and holds that the data filed by both the above entities has been considered while evaluating the dumping margin for the producer. In this regard, the Authority underscores its recent practice to accord producer specific dumping margin which has been adopted in this case as well.
- ii. The Authority notes that M/s Westlake Vinyls Company LP (Producer and Exporter) has claimed that its sales to affiliated buyers has been wrongly rejected. In the earlier SSR 1, the domestic sales to both affiliated and non-affiliated were considered for evaluating dumping margin for them. The Authority notes that the prices to affiliated and non-affiliated vary quite a lot in the current investigation and therefore the facts in the present case are not same as the facts in SSR 1. As no appropriate justification have been provided by the exporter as to why prices to affiliated buyers are lower, the Authority has referenced the prices to non-affiliated parties only, to evaluate the dumping margin since these transactions are considered to be at arm's length. As regards M/s Westlake Vinyls Company LP submission on transfer price aspect, the Authority has adjusted the transfer price based on overall profit percentage of the company.
- iii. The Authority notes the submissions by M/s TPC/SCG regarding an error in the ex-factory export price computation. The Authority has re-examined and corrected the same by considering export rebate as an addition and not as a deduction and has recomputed the ex-factory export price as *** Bhat/MT (*** \$/MT) after appropriately considering all admitted adjustments. The dumping margin accordingly is re-computed as *** %. As regards non admissibility of certain adjustments on normal value and ex-factory export price submitted by M/s TPC/SCG, the Authority holds that as enumerated in the confidential disclosure, only those adjustments whose evidence and

justification was provided during onsite verification were considered for evaluating normal value and ex-factory export price appropriately.

iv. The Authority notes the submission regarding according individual dumping margin to cooperative producers/exporters who have participated now and did not participate earlier. The dumping margins of the participative producers/exporters have been evaluated for POI to establish the fact of dumping which is one of the essential parameters to consider continuance of the existing measure. The Authority holds that for cooperating producers/exporters likelihood has been examined on the basis of the aggregated transaction wise data as available from the cooperating producers/exporters and the continuance of existing AD duties has been considered appropriately.

C.

- i. The Authority notes the contentions of various interested parties on the likelihood analysis and holds that it has referenced the transaction wise data provided by the cooperating producers/exporters to evaluate the extent of diversion of exports to countries other than India by considering attractiveness of Indian Market and extent transactions being injurious, in event of anti-dumping duty being withdrawn. The methodology was demonstrated in the disclosure statement as also stated above in foregoing paras. The Authority holds that submission as to domestic industry is not suffering any injury and that they are profitable is infact also admitted by domestic industry and so stated by the Authority in the disclosure statement. The Authority has evaluated the likelihood of injury to domestic industry in event of withdrawal of anti-dumping duty.
- ii. Various Interested parties have stated that it is unlikely that post cessation of ADD all 3rd country exports which are at lower prices than to India may get diverted. Further the terms of trade are also an important parameter to determine the price. It has also been submitted that when post POI injury margins are negative, it is quite unlikely that the diverted exports may become injurious. The Authority has undertaken the likelihood analysis of diversion of exports to India considering the export prices from a subject country which are lower than export price to India, and which may be injurious in event of its landed value being lower than the indicative NIP, in post POI. Further as stated in later para, the recent hike in basic custom duty has also been factored in examining the likelihood.
- iii. The Authority notes the post disclosure submission by M/s Vinythai Public Company Limited (Producer) and M/s TPC/SCG on the aspect of their exports to India and likelihood of such exports causing injury to the domestic industry. The Authority notes that on the basis of both cooperative exporters data and the trade map data provided by the petitioner, it is seen that during Post POI, the likelihood of diverted exports of Thailand from countries other than India to India in the event of cessation of AD duty is less than ***% of the demand of PUC in India. This magnitude of injurious diversion does not indicate recurrence of injury to the domestic industry. Therefore it does not warrant extension of ADD on imports of Subject Goods from Thailand.
- iv. However the extent of third country exports by China and USA is quite high and with such a high export propensity, likelihood of diversion of exports and such diversion being injurious when considered even in a conservative scenario would be a significant proportion of demand in India. The Authority notes that submissions have been made by M/s LKS and M/s ELP representing producers/exporters from subject countries as stated earlier that the recent increase of BCD on PVC be considered for likelihood of injury analysis. By undertaking such an analysis the results still indicate that extent of injurious exports are quite significant. By factoring in the submission on increase in BCD for landed value computation in likelihood analysis, it is noted that the extent of share of injurious exports in demand is lowered. The percentage of diverted injurious exports as per cooperative producers/exporters data in POI and post POI for China becomes *** and *** respectively and USA becomes *** and *** respectively. As per domestic industry's data these shares become *** and *** respectively for China and *** respectively for USA. Therefore the quantum of injurious exports on diversion is noted to be reduced. However still the likely share of China and USA in total imports in India as per the most pessimistic scenario would

be in the range of 10% and 20% respectively. In any case the likelihood of volume injury would still remain quite significant. The tables H3 and H4 below depicts this scenario.

The attractiveness and the injurious exports amongst such diverted exports to India evaluated for POI and post POI are as under:

Table H1 - Cooperative producers/exporters

		POI							
S.No.	Country	Volume of export to India by responding exporters	Volume of export to third countries by responding exporters	% of attractive volumes to third country exports	% of injurious volumes to attractive volumes	Country volume attractive	Country volume injurious **	Volumes attractive as % of Indian demand	Volumes injurious as % of Indian demand
		MT	MT	%	%			%	%
1	China	***	***	55-65%	85-95%	***	***	14.20%	12.71%
2	Thailand	***	***	50-60%	45-55%	***	***	5.34%	2.49%
3	USA	***	***	50-60%	65-75%	***	***	51.25%	35.79%
		Post POI						•	
1	China	***	***	75-85%	50-60%	***	***	13.35%	7.48%
2	Thailand	***	***	45-55%	15-25%	***	***	4.31%	0.87%
3	USA	***	***	70-80%	85-95%	***	***	90.59%	79.29%

Table H2 - Trade map data of petitioner

			POI									
S.No.	Country	Volume of export to India as per Trade Map data	Volume of export to third countries as per Trade Map data	% of attractive volumes to third country exports	% of injurious volumes to attractive volumes	Country volume attractive	Country volume injurious	Volumes attractive as % of Indian demand	Volumes injurious as % of Indian demand			
		MT	MT	%	%			%	%			
1	China	***	***	80%	69%	***	***	19.66%	13.51%			
2	Thailand	***	***	60%	68%	***	***	7.53%	5.16%			
3	USA	***	***	12%	79%	***	***	12.37%	9.74%			
					Post PO	I						
1	China	***	***	57%	67%	***	***	9.37%	6.26%			
2	Thailand	***	***	61%	10%	***	***	6.86%	0.67%			
3	USA	***	***	43%	30%	***	***	51.41%	15.36%			

The Diversion with recent hike in BCD from 7.5% to 10% is evaluated on injury likelihood as under:

Table H3 - Cooperative producers/exporters

			POI									
S.No.	Country	Volume of export to India by responding exporters	Volume of export to third countries by responding exporters	% of attractive volumes to third country exports	% of injurious volumes to attractive volumes	Country volume attractive *	Country volume injurious **	Volumes attractive as % of Indian demand	Volumes injurious as % of Indian demand			
		MT	MT	%	%			%	%			
1	China	***	***	58%	73%	***	***	14.20%	10.41%			
2	Thailand	***	***	58%	47%	***	***	5.34%	2.49%			
3	USA	***	***	52%	59%	***	***	51.25%	30.18%			
					Post P	OI						
1	China	***	***	80%	30%	***	***	13.35%	4.06%			
2	Thailand	***	***	45%	20%	***	***	4.31%	0.87%			
3	USA	***	***	76%	78%	***	***	90.59%	70.84%			

Table H4 - Trade map data of Petitioner

					POI					
S.No.	Country	Volume of export to India as per Trade Map data	Volume of export to third countries as per Trade Map data	% of attractive volumes to third country exports	% of injurious volumes to attractive volumes	Country volume attractive	Country volume injurious	Volumes attractive as % of Indian demand	Volumes injurious as % of Indian demand	
		MT	MT	%	%			%	%	
1	China	***	***	80%	55%	***	***	19.66%	10.79%	
2	Thailand	***	***	60%	68%	***	***	7.53%	5.16%	
3	USA	***	***	12%	31%	***	***	12.37%	3.81%	
		Post POI								
1	China	***	***	57%	41%	***	***	9.37%	3.81%	
2	Thailand	***	***	61%	10%	***	***	6.86%	0.67%	
3	USA	***	***	43%	16%	***	***	51.41%	8.13%	

L. CONCLUSIONS

- 107. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority as recorded in this finding, the Authority concludes that:
 - i. The product under consideration has been exported to India from the subject countries during POI at dumped prices.
 - ii. The Domestic Industry has not suffered material injury during the POI in terms of either price or volume effect with Anti-dumping duty measure being in force. There exists likelihood of injury due to imports from USA and China on cessation of AD duty. The likelihood of injury of imports from Thailand is quite low and insignificant.
 - iii. The likelihood analysis indicates that in event of cessation of Anti-dumping duty, the exports by USA and China to countries other than India are likely to get diverted to India. The landed value

of significant volume of such diverted exports would cause injury to the domestic industry when compared with the NIP during post POI.

M. RECOMMENDATIONS

- 108. i. The Authority notes that all cooperating producers/exporters except M/s Westlake would fall under either non sampled/or residual category in original or the 1st SSR finding. Out of the 7 cooperating producers/exporters from China, the injury margin in the POI for 5 cooperating producers/exporters is positive. The injury margin for remaining 2 producers/exporters of China and 2 cooperating producers/exporters of USA ranges from low to moderate. The Anti-dumping duty was by and large higher in the 1st SSR as compared to the original finding on account of enhanced margins of dumping and/or injury.
 - ii. The Authority however notes that in the instant case the likelihood of injury has been claimed by the domestic industry which has so been assessed and evaluated by the Authority. The likelihood of injury is established only on imports from China and USA. The extent of injury may however decrease to some extent due to recent increase in BCD to 10% as stated in earlier paras. In view of this, the injury margins in POI in this case would not be relevant and the earlier imposed AD measure as applicable may warrant continuance. However keeping in view the fact though there is likelihood of injury which shows some decrease after enhanced Basic Customs Duty, the quantum of measure imposed in the original finding rather than the 1st SSR would be adequate for all cooperating producers/exporters except for M/s Westlake for whom an individual margin has been accorded in 1st SSR on account of cooperation.
 - iii. Further keeping in view that it is the 2nd SSR, tenure of 30 months of continued measure from the date of imposition of the measure as recommended below would be reasonable.
 - iv. In view of the aforesaid, the Authority recommends imposition of definitive Anti-Dumping Duties on the import of the Subject Goods, originating in or exported from People's Republic of China and United States of America as indicated in Col (7) of the duty table below for a period of 30 months from the date of Notification to be issued in this regard by the central government substituting existing custom Notification No. 23/2019-Customs (ADD) dated 11th June, 2019.

Duty Table

Sl.	Heading	Description	Country	Country of	Country of Producer		Unit	Currency
No	_	_	of origin	export				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	3904	Homopolymer of vinyl chloride monomer (suspension grade)	People's Republic of China	People's Republic of China	i. M/s Tianjin LG Bohai Chemical Co., Ltd. ii. M/s Tianneng Chemical Co., Ltd iii. M/s Tianjin Dagu Chemical Co., Ltd iv. M/s Xinjiang Shengxiong Chlor- Alkali Co., Ltd v. M/s Chiping Xinfa PVC Co., Ltd. vi. M/s CNSG Jilantai Salt Chlori - Alkali Chemical Co., Ltd. vii. M/s Yibin Haifeng Herui Co., Ltd.	61.14	MT	US Dollar
2.	3904	Homopolymer of vinyl chloride monomer (suspension grade)	People's Republic of China	People's Republic of China	Any other producer except i to vii mentioned above in column no. (6)	147.96	MT	US Dollar
3.	3904	Homopolymer of vinyl chloride monomer (suspension grade)	People's Republic of China	Any country other than People's Republic of China	Any	147.96	MT	US Dollar

4.	3904	Homopolymer of vinyl chloride monomer (suspension grade)	United States of America	United States of America	M/s Westlake Vinyls Company LP	29.99	MT	US Dollar
5.	3904	Homopolymer of vinyl chloride monomer (suspension grade)	United States of America	United States of America	M/s Oxy Vinyls LP	49.10	MT	US Dollar
6.	3904	Homopolymer of vinyl chloride monomer (suspension grade)	United States of America	United States of America	Any other producer except M/s Westlake Vinyls Company LP, M/s Oxy Vinyls LP	115.54	MT	US Dollar
7.	3904	Homopolymer of vinyl chloride monomer (suspension grade)	United States of America	Any country other than United States of America	Any	115.54	MT	US Dollar

Note: The product under consideration is Homopolymer of vinyl chloride monomer (PVC) (suspension grade) where various polymer chains are not linked to each other, which however, excludes the specialty poly vinyl chloride suspension resins such as cross-linked poly vinyl chloride, chlorinated poly vinyl chloride (CPVC), vinyl chloride – vinyl acetate copolymer (VC-Vac), poly vinyl chloride paste resin and poly vinyl chloride blending resin.

N. FURTHER PROCEDURE

109. An appeal against this notification shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority